MANOHAR PARRIKAR
idsa
MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR
DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

एमपी-आईडीएसए मोनोग्राफ श्रृंखला
नं. 94 अक्टूबर 2025

म्यांमार

तलाश एक समावेशी राजनीतिक तंत्र की

ओमप्रकाश दास

एमपी-आईडीएसए मोनोग्राफ श्रृंखला
न. 94 अक्टूबर 2025

म्यांमार: तलाश एक समावेशी राजनीतिक तंत्र की

ओमप्रकाश दास

MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR
DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

© मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

इस प्रकाशन के सभी अधिकार मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) के पास हैं। इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा बिना पहले से अनुमति लिए न तो छापा जा सकता है, न ही किसी संग्रहण प्रणाली में सुरक्षित या किसी तरीके से वितरित किया जा सकता है। भेजने का यह तरीका चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, मशीन से हो, फोटो-कॉपी हो, रिकॉर्डिंग हो या कोई और तरीका हो। इसके लिए मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) की अनुमति ज़रूरी है।

ISBN: 987-81-980805-2-3

अस्वीकरण: इस प्रबंध निबंध (मोनोग्राफ) में व्यक्त विचार लेखक के हैं और आवश्यक नहीं कि वे संस्थान या भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों।

पहला प्रकाशन: अक्टूबर 2025

कीमत: ₹ 350/-

प्रकाशकः मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा प्रकाशित
नं.1, डेवलपमेंट एन्क्लेव, राव तुला राम मार्ग,
दिल्ली कैंट., न्यू दिल्ली - 110010
फोनः (91-11) 2671-7983
फैक्स. (91-11) 2615 4191
वेबसाइटः http://www.idsa.in

आवरण चित्र सौजन्यः https://www.pexels.com/photo/silhouette-of-mountains1089288/
https://freesvg.org/myanmar-map-flag

आवरण और रूपरेखा: गीता कुमारी और विरेंद्र सिंह रावत

मुद्रण: पेंटागन प्रेस एलएलपी
206, पीकॉक लेन, शाहपुर जट,
नई दिल्ली -110049
फोनः (91-11) 26491568, 26490600
फैक्स: (91-11) 26490600
ईमेल: rajanaryaa@gmail.com
rajan@pentagonpress.in
वेबसाइट: http://www.pentagonpress.in

विषय वस्तु

		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	7
1.	म्यांमारः आधुनिक राष्ट्र-राज्य तक की राजनीतिक यात्रा	15
2.	म्यांमारः लोकतंत्र का उत्थान और पतन (1948–1962)	24
3.	लोकतंत्र से सैन्यतंत्र की ओर (1962 – 1974)	34
4.	नई एकपक्षीय संवैधानिक व्यवस्था और प्रतिनिधित्व का सवाल	42
5.	आठ-आठ-अट्ठासी क्रांति और लोकतंत्र की आकांक्षाएं	49
6.	नई सहस्राब्दीः लोकतंत्र की ओर दो कदम आगे, एक कदम पीछे	59
7.	लोकतांत्रिक सुधारों का दबाव बनाम यथास्थितिवाद (2007 - 2015)	65
8.	सीमित लोकतंत्र का जश्न और सेना की वापसी (2015 - 2020)	78
9.	2021 का तख्तापलट और गृहयुद्ध का नया दौर	89
10.	वैकल्पिक राजनीतिक प्रणाली और विरोधाभास	96
11.	निष्कर्षः तलाश जारी है…	115

टेबलों की सूची

टेबल 1	1956 के आम चुनाव के परिणाम (प्रतिनिधि सभा)	पृष्ठ सं. 29
टेबल 2	1990: चुनाव परिणाम	पृष्ठ सं. 53
टेबल 3	7-चरणों वाला रोडमैप 2003	पृष्ठ सं. 60
टेबल 4	म्यांमार: 1974 और 2008 के संविधान के बीच प्रमुख अंतर	पृष्ठ सं. 67
टेबल 5	2010 का आम चुनाव	पृष्ठ सं. 71
टेबल 6	2015: चुनाव परिणाम	पृष्ठ सं. 79
टेबल 7	2020 आम चुनावः परिणाम	पृष्ठ सं. 87

चित्रों की सूची

चित्र 1	म्यांमार: प्रमुख जातीय समूह	पृष्ठ सं. 5
चित्र 2	म्यांमार का राजनीतिक नक्शा	पृष्ठ सं. 32

चित्र 1.[1]

म्यांमार: प्रमुख जातीय समूह
जातीय समूह
बामर
शान
करेन
रखाइन
रोहिंग्या
काचिन
चिन
करेनी
मॉन
वा
कोकांग चाइनीज़
रखाइन रोहिंग्या अंतर-जातीय संघर्ष (2017)
प्रमुख जातीय संघर्ष के केंद्र
राजधानी
काचिन
INDIA
इंडिया
चीन
CHINA
म्यांमार
MYANMAR
वा
BANGLADESH
बांग्लादेश
शान
चिन
कोकांग
चाइनीज़
बामर
रोहिंग्या
रखाइन
करेनी
नेप्पीदॉ
Naypyidaw
THAILAND
थाईलैंड
करेन
मॉन
Source: Al Jazeera, agencies, freeburmarangers, Burma - Insurgency and the Politics of Ethnicity (Martin Smith)

प्रस्तावना

म्यांमार की राजनीतिक यात्रा विशेषकर एक आधुनिक लोकतंत्र के निर्माण की यात्रा एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया रही है, जिसे ऐतिहासिक परिवर्तन, जातीय संघर्ष, सैन्य प्रभुत्व और लोकतंत्र की एक समावेशी संरचना की सतत खोज ने आकार दिया है। एक सांस्कृतिक और जातीय विविधता से समृद्ध राष्ट्र के रूप में, म्यांमार लंबे समय से एक समावेशी राजनीतिक ढांचे की स्थापना के प्रयास में है, जो बहु-जातीय आबादी को समायोजित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बनाए रख सके। देश की शासन प्रणाली को उसके औपनिवेशिक अतीत, स्वतंत्रता के बाद के संघर्षों, लंबे सैन्य शासन और अस्थायी लोकतांत्रिक प्रयोगों ने आकार दिया है, जो आज भी राजनीतिक उथल-पुथल में दिखाई देता है।

ऐतिहासिक रूप से, म्यांमार की राजनीतिक संरचना एक केंद्रीकृत राजशाही पर आधारित थी, जिसमें सत्ता शासक वर्ग के हाथों केंद्रित थी। 1824 से 1948 तक चले ब्रिटिश शासन ने पारंपरिक सत्ता संरचना में व्यापक उथल-पुथल पैदा किया और एक नौकरशाही आधारित शासन प्रणाली स्थापित की, जिसके लिए कानूनी, आर्थिक और बुनियादी ढांचे में बदलाव किए गए। हालांकि, उपनिवेशवाद ने जातीय विभाजन को बढ़ावा दिया, कुछ जातीय समूहों को प्राथमिकता दी गई जिससे आर्थिक असमानताओं की खाई चौड़ी हुई लेकिन इसने पारंपरिक प्रशासनिक संस्थानों को कमजोर किया। इस अवधि ने म्यांमार के विविध जातीय समुदायों के बीच गहरे अविश्वास के बीज बोए, जो आज भी देश की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं।

1948 में स्वतंत्रता के बाद, म्यांमार की संसदीय लोकतंत्र की कोशिशें अल्पकालिक ही साबित हुईं, क्योंकि नई सरकार जातीय विद्रोहों, आर्थिक अस्थिरता और कमजोर संस्थागत ढांचे की चुनौतियों से निपटने में विफल रही। जातीय अल्पसंख्यकों को स्वायत्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का वादा किया गया था, लेकिन बहुसंख्यक बमार जातीय के प्रभुत्व वाले राजनीतिक ढांचे में वो हाशिए पर ही रहे। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों में जातीय समूहों

की मांगों को शामिल करने में विफलता ने व्यापक संघर्षों और सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया, जिससे नवगठित लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो गई। इस अस्थिरता ने सैन्य हस्तक्षेप के लिए रास्ता बनाया, जो 1962 के तख्तापलट के रूप में सामने आया और तात्मादॉ (म्यांमार की सेना) सत्ता के केंद्र में आ गई। तब से, सैन्य शासन ने देश की राजनीतिक दिशा को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। जिसे सेना ने अक्सर अपने प्रभुत्व को राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक बताकर उचित ठहराया है।

दशकों के अधिनायकवादी शासन के तहत, म्यांमार को गंभीर राजनीतिक दमन, आर्थिक कुप्रबंधन और नागरिक स्वतंत्रता के दमन का सामना करना पड़ा। सैन्य शासन ने लोकतांत्रिक भागीदारी को सीमित किया, प्रमुख सरकारी संस्थानों को नियंत्रित किया और ऐसी नीतियां लागू कीं, जो संसाधनों पर अभिजात वर्ग के नियंत्रण को मजबूत करती थीं। हालांकि, लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों ने गति पकड़ी, विशेष रूप से 1988 के विरोध प्रदर्शन और आंग सान सू ची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) का उदय हुआ—लेकिन सैन्य दमन ने लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यापक रूप से पूरा नहीं होने दिया। 2008 में सैन्य निगरानी में तैयार किए गए संविधान ने संसद में 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित रखकर और प्रमुख मंत्रालयों पर इसका नियंत्रण सुनिश्चित करके तात्मादॉ के प्रभुत्व को संस्थागत रूप दिया, जिससे निर्वाचित नागरिक सरकारों की शक्ति प्रभावी रूप से सीमित हो गई।

नए संविधान ने एक अर्ध-नागरिक राजनीतिक तंत्र के शुरुआत की नींव रखी। 2015 और 2020 में NLD की चुनावी जीत ने म्यांमार की राजनीतिक प्रणाली पर सैन्य नियंत्रण को बाधित तो किया लेकिन बुनियादी रूप से कोई चुनौती नहीं दी। फरवरी 2021 के तख्तापलट ने सैन्य सत्ता के वर्चस्व और लोकतांत्रिक संक्रमण की अस्थिरता को फिर से उजागर कर दिया। इस तख्तापलट ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों, नागरिक अवज्ञा आंदोलनों और सशस्त्र प्रतिरोध को जन्म दिया, जिससे देश और अधिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया। जातीय सशस्त्र समूहों के फिर से उभरने, पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज (PDFs) के गठन और समानांतर राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) की स्थापना ने राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना दिया, जिससे एक समावेशी और प्रतिनिधि शासन

मॉडल की निरंतर खोज थोड़ी और अस्थिर ही सही, लेकिन आगे बढ़ती दिखती है।

मौजूदा हालात को देखते हुए यह स्पष्ट है कि म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई मौलिक मुद्दों का समाधान करना ज़रूरी है। इन मुद्दों में जनादेश को संरचनात्मक और संवैधानिक रूप से स्थापित करना, कानून के शासन को मजबूत करना, संस्थागत विकास को बढ़ावा देना, राजनीतिक बहुलतावाद को प्रोत्साहित करना और आर्थिक समावेशी तंत्र को स्थापित करना शामिल है। एक वास्तविक लोकतांत्रिक म्यांमार का सपना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों, सार्वभौमिक मताधिकार और सैन्य प्रभाव से मुक्त नागरिक शासन के सिद्धांतों की स्थापना के सवाल पर अभी भी उलझा दिखता है। शायद इसीलिए म्यांमार में एक मजबूत और समावेशी कानूनी ढांचे की तलाश अब तक जारी है। इसके लिए विपक्षी ताकतें यह मांग करती रही हैं कि संविधान में संशोधन करके सेना की राजनीतिक भूमिका को सीमित किया जाए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित हो, और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह स्पष्ट है कि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग, एक पेशेवर सिविल सेवा और एक स्वतंत्र प्रेस जैसी संस्थाओं को मजबूत करना, जवाबदेही को बढ़ावा देना, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

म्यांमार के गहरे जातीय विभाजन एक और चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि यह विभाजन शासन से समावेशी और संवेदनशील होने की मांग करते हैं, जो किसी भी देश के लोकतांत्रिक तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संघवाद की मांग लंबे समय से जातीय अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रमुख मुद्दा रही है, जो विकेंद्रीकृत ढांचे के भीतर अधिक स्वायत्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। हालांकि, बमार बहुसंख्यक और सेना के प्रभुत्व वाली सरकारों ने वास्तविक संघीय सुधारों का विरोध किया है, जिसके पीछे यह तर्क दिया जाता रहा है कि इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाएगी। बुनियादी बात यह है कि एक सार्थक संघीय संरचना को लागू करने में विफलता ने जातीय संघर्षों को लंबा कर दिया है और राष्ट्रीय सुलह प्रयासों को बाधित किया है।

म्यांमार की एक आधुनिक लोकतांत्रिक समावेशी राजनीतिक राष्ट्र राज्य के रूप में रूपांतरण, अब तक दूर की ही कौड़ी रही है। इस मोनोग्राफ में कोशिश

है इस राजनीतिक यात्रा और ऐतिहासिक उथल-पुथल को राजनीतिक सरंचना के निर्माण के संदर्भ में समझा जाए। म्यांमार में समावेशी राजनीतिक ढांचे की खोज ऐतिहासिक, जातीय और संस्थागत जटिलताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। जब तक संघवाद, संवैधानिक सुधार, आर्थिक नीतियां और राजनीतिक संस्कृति में वास्तविक परिवर्तन नहीं होते, तब तक म्यांमार की स्थिर लोकतंत्र की राह अनिश्चित बनी रहेगी। क्योंकि अब तक म्यांमार बार-बार सैन्य हस्तक्षेप, राजनीतिक प्रतिरोध और सामाजिक अशांति के चक्र में फंसी रही है।

यह मोनोग्राफ ग्यारह अध्यायों में विभाजित है, जिसमें पहला अध्याय "म्यांमारः आधुनिक राष्ट्र-राज्य तक की राजनीतिक यात्रा" म्यांमार के ऐतिहासिक और राजनीतिक विकास को दर्शाता है, जिसमें साम्राज्यों के उत्थान, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक अस्थिरता को शामिल किया गया है। यह अध्याय इस बात को समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक राजशाही-सामंतवादी राज्य बाहरी आक्रमणों, आंतरिक संघर्षों और आर्थिक चुनौतियों की वजह से कमजोर हुआ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने आंग्ल-बर्मी युद्धों (1824–1885) के माध्यम से म्यांमार पर कब्ज़ा कर लिया और 1886 में इसे ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया। औपनिवेशिक शासन के दौरान, अंग्रेजों ने "बांटो और राज करो" नीति अपनाई, जिससे जातीय अल्पसंख्यकों और बमार समुदाय के बीच विभाजन बढ़ा। 1947 में जनरल आंग सान और अन्य नेताओं ने विभिन्न जातीय समूहों को एकीकृत करने के लिए पांगलोंग समझौता किया, परंतु इसके पूर्ण क्रियान्वयन से पहले ही आंग सान की हत्या कर दी गई, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई। आखिरकार, 4 जनवरी 1948 को म्यांमार ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ और 1947 का संविधान पारित किया गया, जो संघीयता और लोकतंत्र की अवधारणा पर आधारित था। हालांकि, यह संविधान जातीय स्वायत्तता की मांगों को पूरी तरह हल नहीं कर पाया, जिससे करेन, कचिन, शान और अन्य समूहों ने हथियार उठा लिए और देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी गई। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि म्यांमार की राजनीतिक संरचना कैसे ऐतिहासिक, औपनिवेशिक और जातीय संघर्षों से प्रभावित हुई है, जो आज भी देश की राजनीति और स्थिरता को चुनौती देती है। वही, दूसरा अध्याय (म्यांमारः लोकतंत्र का उत्थान और पतनः 1948–1962) में म्यांमार की

स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक यात्रा को उजागर करता है, जिसमें लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, जातीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और आखिरकार, 1962 के सैन्य तख्तापलट के कारण लोकतंत्र के पतन के कारणों की पड़ताल की गई है। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यू-नु के नेतृत्व में संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन जातीय समूहों की स्वायत्तता की मांग और कम्युनिस्ट विद्रोह के कारण सरकार को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह अध्याय म्यांमार में लोकतंत्र की विफलता के प्रमुख कारणों को रेखांकित करता है और सैन्य सत्ता के उदय की पृष्ठभूमि को समझने में मदद करता है। तीसरे अध्याय 'लोकतंत्र से सैन्यतंत्र की ओर (1962–1974)' में म्यांमार के उस दौर की बात की गई है जब सेना ने शासन, प्रशासन और राजनीतिक ढांचे पर अपनी पूरी पकड़ बना ली। 2 मार्च 1962 को जनरल ने-विन के नेतृत्व में हुए सैन्य तख्तापलट ने 1947 के संविधान को समाप्त कर दिया और क्रांतिकारी परिषद (Revolutionary Council) के तहत शासन की नई व्यवस्था स्थापित की, जिसने विधायी और कार्यकारी शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया। इस तख्तापलट को सरकार की विफलताओं और जातीय अलगाववादी आंदोलनों को नियंत्रित करने के नाम पर सही ठहराया गया, लेकिन वास्तव में इससे जातीय विद्रोह और असंतोष और बढ़ ही गया। यह अध्याय इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे 1962 के तख्तापलट से लेकर 1974 के नए संविधान निर्माण तक की अवधि में म्यांमार में सैन्य शासन पूरी तरह स्थापित हुआ और संघीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर दिया गया। इस दौर ने म्यांमार में लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अधिनायकवाद और राजनीतिक अस्थिरता की नींव भी रखी। इस मोनोग्राफ का चौथा अध्याय म्यांमार के उस राजनीतिक दौर की ओर इशारा करता है जब सैन्य शासन के दौरान हुए दमन, विरोध प्रदर्शन, चुनाव और जातीय संघर्षों का विस्तार होता गया। इसके साथ ही यह अध्याय लोकतांत्रिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि को भी समझने की कोशिश करता है, जो 1988 के एक व्यापक जनआंदोलन के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया जिसने म्यांमार में सेना को कुछ सुधारवादी कदम उठाने को मजबूर तक कर दिया। पांचवा अध्याय में 1988 के बाद के उस दौर की बात करता है जब म्यांमार में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों, विशेष रूप से लोकतांत्रिक आंदोलनों, सैन्य दमन, और संवैधानिक

परिवर्तनों की कोशिशें शुरु हुई। 1992 में, नए सैन्य नेतृत्व के तहत, म्यांमार में एक नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1993 में शुरू हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया तीन वर्षों तक चली, जिसमें सेना की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। यह अध्याय म्यांमार के लोकतंत्र के लिए संघर्ष और सेना के निरंकुश शासन के बीच टकराव के गहराई में उतरता है। वहीं, छठे अध्याय में 2003 से 2007 के बीच म्यांमार के राजनीतिक घटनाक्रमों और लोकतंत्र के संघर्षों पर चर्चा की गई है। 2003 में, सैन्य शासन ने "7-चरणीय रोडमैप" की घोषणा की, जिसका उद्देश्य "अनुशासित लोकतंत्र" स्थापित करना था, लेकिन यह योजना नागरिक समाज को अलग रखते हुए सेना के राजनीतिक नियंत्रण को बनाए रखने पर केंद्रित थी। 2007 में "केसर क्रांति" हुई और बौद्ध भिक्षु, जो समाज में उच्च सम्मान रखते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे और लोकतंत्र की बहाली की मांग की। यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया, लेकिन सैन्य सरकार ने कर्फ्यू, इंटरनेट प्रतिबंध, लाठीचार्ज, और गोलीबारी के माध्यम से इसे कुचलने की कोशिश की। यह आंदोलन म्यांमार के नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और इसने लोकतांत्रिक संघर्ष की एक नई लहर को जन्म दिया। सातवें अध्याय में 2007 से 2015 तक म्यांमार में लोकतांत्रिक सुधारों, राजनीतिक घटनाओं, और संघर्षविराम की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। 2007 की "केसर क्रांति" ने सैन्य शासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिससे आंतरिक और बाहरी दबाव में सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई। 2008 में सैन्य शासन ने एक नया संविधान लागू किया लेकिन संविधान की वैधता पर कई सवाल भी उठते रहे। 2010 के चुनावों का NLD ने बहिष्कार किया लेकिन इन चुनावों ने म्यांमार में एक अर्ध-नागरिक सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि, संविधान में सेना का प्रभाव और जातीय समूहों के लिए बेहद सीमित स्वायत्तता का प्रावधान ही था, नतीजतन कई जातीय सशस्त्र समूहों ने संविधान को खारिज कर दिया। आठवें अध्याय में म्यांमार में 2015 से 2021 के बीच हुए राजनीतिक घटनाक्रमों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रगति और सेना के प्रभाव के बीच संघर्ष स्पष्ट रूप से देखा गया। 2015 के आम चुनावों ने सैन्य शासन से अर्ध-लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर बढ़ने की उम्मीदें जगाईं। आंग सान सू ची की पार्टी NLD ने भारी जीत दर्ज

की और 2016 में सत्ता संभाली। हालांकि, संविधान में सेना के लिए आरक्षित सीटों और महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर उनके नियंत्रण के चलते लोकतांत्रिक शासन बाधित रहा। नवमें अध्याय में 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, नागरिक अवज्ञा और सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गए। सेना ने चुनावी धांधली का आरोप लगाकर आंग सान सू ची और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया और देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके जवाब में विपक्षी गुटों ने निर्वासित सरकार (NUG) और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस (PDF) का गठन किया, जो जातीय सशस्त्र संगठनों के साथ मिलकर सैन्य शासन का विरोध करने लगे। इसी दौरान गृहयुद्ध का एक लंबा और हिंसक दौर शुरु हुआ जिसमें सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस गृहयुद्ध में हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए, और म्यांमार की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। जबकि जुंटा ने 2025 में चुनाव कराने का वादा किया, लेकिन व्यापक संघर्ष के चलते इसकी वैधता पर सवाल उठते रहे। बढ़ते दबाव के कारण सेना ने विद्रोही गुटों से बातचीत का प्रस्ताव दिया। इस बीच, देश में सैन्य शासन की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है, और विद्रोही गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे म्यांमार का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। वहीं, दसवां अध्याय भविष्य की तरफ इशारा करता है। निर्वासित सरकार (NUG) और जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) ने सेना के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं साथ उन्होंने एक संघीय लोकतंत्र चार्टर भी प्रस्तुत किया, जो सैन्य शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक संघीय राज्य की स्थापना की रूपरेखा तैयार करता है। हालांकि, विपक्षी समूहों के बीच संघवाद की परिभाषा और राजनीतिक भविष्य को लेकर मतभेद बने हुए हैं। EAOs अधिक स्वायत्तता चाहते थे, जबकि NUG एक केंद्रीकृत लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर बढ़ रहा था। यह अध्याय विशेष रूप से उन कारणों की भी पड़ताल करता है कि आख़िर सेना राजनीतिक संरचना का हिस्सा क्यों बनी हुई है और क्यों सेना के शीर्ष अधिकारियों के लिए राजनीतिक तंत्र में वर्चस्व बनाए रखना उनके अस्तित्व से जुड़ा है। इसका नतीजा अब तक यह रहा है कि सैन्य और विपक्षी गुटों के बीच सत्ता-साझाकरण, स्वायत्तता और समावेशी शासन को लेकर गहरे अंतर्विरोध म्यांमार के लोकतांत्रिक भविष्य को जटिल बना रहे हैं। ग्यारहवां अध्याय एक अंतर्दृष्टि रखने की कोशिश करता है, जहां भविष्य की ओर तो इशारा है ही साथ

ही वैचारिक, सांस्थानिक और व्यवहारिक स्तर पर म्यांमार के राजनीतिक तंत्र की यात्रा को संकल्पना के स्तर पर स्तर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है।

इस मोनोग्राफ में 'म्यांमार' और 'बर्मा' दोनों का उपयोग किया गया है, हालांकि शुरु में ज्यादातर 'बर्मा' का ही उपयोग है। वहीं म्यांमार की सेना के लिए सेना, तात्मादॉ और बाद में जुंटा जैसे शब्दावलियों का एक समान अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जुंटा शब्द का प्रयोग विशेषकर 1990 के बाद के समय में किया गया है, जो सेना के सीधे शासन में होने की स्थिति पर आधारित है। यहां यह बात भी स्पष्ट कर देना बेहतर होगा कि इस मोनोग्राफ में 'जातीय' शब्द अंग्रेजी के 'Ethnic' शब्द का ही अनुवाद है।

म्यांमारः आधुनिक राष्ट्र-राज्य तक की राजनीतिक यात्रा

साम्राज्यों की भूमि से औपनिवेशिक शासन तक

भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड और लाओस से घिरे भूखंड को अंग्रेज़ों ने आधिकारिक रूप से बर्मा नाम दिया था, जिसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ऐतिहासिक रूप से बर्मा नाम, प्रमुख 'बर्मन' जातीय समूह के नाम पर ही पड़ा था। 1989 में जब सत्तारूढ़ सैन्य शासकों (जुंटा) ने देश नाम बदलकर 'म्यांमार' कर दिया।[2] उस समय तक, बर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ा हुआ था और अपनी छवि सुधारने और जातीय एकता को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुंटा ने 'म्यांमार' को अपनाया।[3]

म्यांमार का इतिहास लगभग 13,000 वर्ष पूर्व मानव बस्तियों की मौजूदगी तक फैला हुआ है। प्राचीनतम ज्ञात निवासी तिब्बती-बर्मी भाषी लोग थे, जिन्होंने प्यू नगर-राज्यों की स्थापना की, जो दक्षिण में पये (प्रोम) तक फैले थे, और जिन्होंने बाद में 'थेरवाद' बौद्ध धर्म को अपनाया।[4] एक अन्य समूह, बमर लोग, 9वीं शताब्दी की शुरुआत में ऊपरी इरावदी घाटी में आए। उन्होंने पगान साम्राज्य (1044–1297) की स्थापना की, जो इरावदी घाटी में फैले इलाकों पहला राजनीतिक एकीकरण था।[5] इस अवधि के दौरान बर्मी भाषा और संस्कृति विकसित होने लगी। सन् 1287 में मंगोल आक्रमण के बाद, कई छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें अवा का साम्राज्य, हंथवाडी साम्राज्य, मरौक-यू साम्राज्य और शान राज्य प्रमुख शक्तियाँ थीं। ये साम्राज्य आपस में कई बार गठबंधनों में भी रहते तो कई बार इनके बीच संघर्ष भी देखने को मिले।[6] 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तौंगू वंश (1510–1752) ने देश को फिर से एकीकृत किया और एक छोटी के अवधि के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया।[7] 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में,

कोनबांग वंश (1752–1885) ने राज्य को फिर से स्थापित किया और अपने साम्राज्य को केंद्रीय शासन की ओर ले गया। इस वंश ने अपने सभी पड़ोसियों के साथ युद्ध भी किए। उत्तराधिकार संघर्ष, आर्थिक अक्षमताएँ, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने में चुनौतियों ने राजतंत्र को और कमजोर किया।[8] बाहरी रूप से, म्यांमार को सियाम (आधुनिक थाईलैंड) और चीन से सैन्य और आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ा, जबकि यूरोपीय व्यापारियों और मिशनरियों के आगमन ने नई चुनौतियाँ पेश कीं। आखिरकार, आंग्ल-बर्मी युद्धों (1824–85) ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना की।[9]

म्यांमार की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, समृद्ध संसाधनों और उपजाउ भूमि के लिए जाना जाता रहा है और अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए यहां अपनी पकड़ बनाने के लिए लड़ाईयां लड़ी जो एंग्लो-बर्मी युद्धों के रूप में जाने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने का कोशिशों को अंजाम देने शुरु किया और इस दौरान तीन आंग्ल-बर्मी युद्ध हुए। 1885 के तीसरे आंग्ल-बर्मी युद्ध के बाद पूरा बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया और इसे 1886 में ब्रिटिश भारत के एक प्रांत के रूप में शामिल कर लिया गया।[10]

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, म्यांमार को बर्मा प्रॉपर और फ्रंटियर क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। बर्मा प्रॉपर में मुख्य रूप से केंद्रवर्ती मैदानी इलाकों में रहने वाले बमर बहुसंख्यक लोग रहते थे, जबकि फ्रंटियर क्षेत्रों में शान, कचिन, चिन, करेन और अन्य जातीय अल्पसंख्यक समूह रहते आए हैं।[11] अंग्रेज़ों की 'बांटों और राज करो' की नीति ने इन अल्पसंख्यक जातीय समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक विकास और प्रशासनिक एकीकरण जैसे विकास के कई स्तरों पर न सिर्फ पीछे रखा बल्कि इनके आपसी जातीय विभाजनों को और गहरा किया।[12]

जातीय समूह भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित हैं। बमर केंद्रवर्ती क्षेत्रों (यंगून, मंडाले, ने-पी-दॉ) पर हावी हैं, जबकि शान, वा और अन्य समूह शान राज्य (पूर्वी म्यांमार) में रहते हैं; कचिन और लिसू कचिन राज्य (उत्तर-पूर्व म्यांमार) में हैं; चिन पश्चिमी चिन राज्य में रहते हैं, जिनकी सीमा भारत से सीधे

लगती है।[13] करेन दक्षिण-पूर्वी करेन राज्य में बसे हैं; मोन दक्षिणी मोन राज्य में हैं; और राखाइन (बौद्ध) और रोहिंग्या (मुस्लिम) राखाइन राज्य में रहते हैं। राखाइन राज्य में अराकान समूह का वर्चस्व रहा है।[14] ये जातीय अल्पसंख्यकों के वर्चस्व वाले इलाके विशेष रूप से जेड, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध रहे हैं,[15] जो विद्रोहियों और तात्मदॉ (म्यांमार की सेना) दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

कई आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की पृष्ठमूमि में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ। यंग मेन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन (YMBA) और बाद में जनरल काउंसिल ऑफ बर्मी एसोसिएशंस (GCBA) जैसे संगठनों ने बर्मी संस्कृति को बढ़ावा देने और औपनिवेशिक शासन का विरोध करने की कोशिशें शुरु कर दीं।[16] 1920 और 1936 में छात्र हड़तालों, और साया सैन विद्रोह (1930–1932) जैसे ग्रामीण विद्रोहों ने बढ़ते असंतोष की बानगी को सामने रखा।[17]

वहीं, बर्मा में एक तबका वो भी था जब अंग्रेज़ों पर जातीय, सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को मान्यता देने का दवाब डाल रहा था। 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन ने बर्मा की भारत से भिन्नता को तर्क समाने रखा और अलगाव का रास्ता सुझाया। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने एक क़ानून पास किया जिसका नाम था 'बर्मा एक्ट 1935' (Government of Burma Act, 1935)।[18] इस क़ानून का उद्देश्य बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित करना था। यह अधिनियम बर्मा की जातीय, सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को मान्यता देने और स्थानीय असंतोष को शांत करने के लिए लाया गया।[19] भारतीय और चीनी प्रवासियों के आर्थिक प्रभुत्व, बर्मी समाज में व्याप्त असंतोष, और बर्मा की राजनीतिक स्वायत्तता की मांग जैसे कारकों ने इस अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की। इस क़ानून ने बर्मा को एक नया संविधान प्रदान किया, एक स्वतंत्र गवर्नर और निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की, लेकिन यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन बना रहा।[20]

इस अधिनियम के तहत "द्वैध शासन" की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें बर्मी मंत्री आंतरिक मामलों का प्रबंधन करते थे, जबकि रक्षा, विदेश नीति और

सीमांत क्षेत्रों जैसे प्रमुख विषय ब्रिटिश गवर्नर के नियंत्रण में बने रहे।[21] इस अधिनियम की एक बड़ी विशेषता थी, शासन का विभाजन। इस व्यवस्था में मंत्रियों को बर्मा (बर्मी बहुल क्षेत्र) और सीमांत क्षेत्रों (जातीय बहुल राज्य) के बीच बांट दिया गया था।[22] इस विभाजन ने असमान शासन संरचना बनाई, जिसने म्यांमार के संवैधानिक इतिहास में स्थायी चुनौतियाँ पैदा कीं, जिनमें राजनीतिक एकीकरण में असंतुलन और संघवाद और अलगाव के मुद्दे शामिल थे। यह देश के पूर्ण राजनीतिक एकीकरण की भावना के ख़िलाफ था, जो 21 वीं सदी में आज तक म्यांमार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस संविधान के तहत ब्रिटिश गवर्नर को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार दिए गए,[23] जिससे ब्रिटिश रणनीतिक और आर्थिक हितों की प्राथमिकता बनी रही। ये अधिकार म्यांमार के 2008 के संविधान के तहत सेना को दिए गए अधिकारों से मिलते-जुलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण सीमित था। इस क़ानून की तमाम आलोचनाओं से परे यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि 'बर्मा एक्ट 1935' देश की स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में पहला कदम साबित हुआ।

1 अप्रैल, 1937 को बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। इस नई राजनीतिक व्यवस्था में एक पूरी तरह निर्वाचित विधानसभा की स्थापना हुई।[24] हालांकि, इस कदम को कई तरह से विश्लेषित किया गया। एक वर्ग ने इसे देश की स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम माना, जबकि अन्य ने इसे बर्मा को उस भारत में हो रहे लोकतांत्रिक सुधारों से दूर रखने की अंग्रेज़ों की चाल के रूप में देखा।[25]

दूसरे विश्व युद्ध का एक वह दौर भी आया, जब बर्मा की धरती जापानी और मित्र देशों की सेनाओं के बीच की युद्धभूमि बन गई। युद्ध के दौरान एक समूह बर्मी राष्ट्रवादियों का भी था जो देश की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे। जनरल आंग सान के नेतृत्व वाली बर्मीज़ इंडिपेंडेंस आर्मी (BIA) की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने अपनी आज़ादी की उम्मीद में पहले जापानियों और बाद में मित्र देशों का समर्थन किया।[26]

1942 में जापानी सेना ने बर्मा पर आक्रमण किया, जिसे शुरुआती दौर में बर्मी राष्ट्रवादियों का समर्थन मिला। इस समूह में प्रमुख नेता आंग सान और उनके साथी ने-विन थे। जापानियों ने जल्दी ही बर्मा के केंद्रीय क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना पीछे हटकर भारत चली गई।[27] पीछे हटते समय ब्रिटिशों ने बर्मा के बुनियादी ढांचे का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। जापान ने बर्मा को "स्वतंत्र" घोषित किया और आंग सान को बर्मी युद्ध मंत्री तथा ने-विन को जापान समर्थित बर्मी सेना का जनरल स्टाफ प्रमुख नियुक्त किया। जापान के तीन साल के कब्जे के दौरान, ब्रिटिशों ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से जापानी सेना और उनके प्रशासन पर लगातार हमले किए। इस संघर्ष में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मार्च 1945 में, जब यह स्पष्ट हो गया कि जापान दूसरा विश्व युद्ध हारने वाला है तब आंग सान के नेतृत्व में बर्मी सेना ने जापान का साथ छोड़ दिया और मित्र राष्ट्रों की सहयोगी बन गई।[28] इसके बाद बर्मी सेना ने ब्रिटिश सेना को बर्मा पर फिर से कब्ज़ा करने में मदद की।

पांगलोंग समझौता

अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद, ब्रिटिशों ने अस्थायी रूप से अपना औपनिवेशिक प्रशासन बहाल किया। हालांकि, उन्हें आंग सान और बर्मी राष्ट्रवादियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जनवरी 1947 में, लंदन में प्रधानमंत्री एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1947 में हुए संसदीय चुनावों में आंग सान की पार्टी, 'एंटी फासिस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग' (AFPFL) ने 255 में से 248 सीटों पर जीत हासिल की।[29] म्यांमार शताब्दियों से कई जातीगत समूहों में बंटा था और हर समूह अपनी पहचान, संसाधनों पर हक़ और संवैधानिक स्वायत्तता को लेकर बेहद सतर्क और संवेदनशील था। जातीगत समूहों का ये बंटवारा देश के राजनीतिक एकीकरण के लिए एक चुनौती थी। इन्हीं जटिल मुद्दों को देखते हुए, युद्ध के बाद, आंग सान ने विभिन्न जातीय नेताओं के साथ वर्ष 1947 में पांगलोंग समझौता किया, जिसने एकीकृत बर्मा की नींव रखी। पांगलोंग समझौता 12 फरवरी 1947 को हुआ।[30] यह समझौता बुनियादी रूप से अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद बर्मा की अंतरिम सरकार और शान स्टेट्स,

काचिन हिल्स, और चिन हिल्स के नेताओं के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ाना था। शान स्टेट्स, काचिन हिल्स और चिन हिल्स म्यांमार में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो अपनी जातीय विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाने जाते हैं। पांगलोंग समझौता इन जातीय समूहों से स्वायत्तता और अधिकारों का वादा करता है।[31] लेकिन इस समझौते को पूरी तरह लागू न होने से सशस्त्र संघर्ष, जातीय तनाव और संसाधनों पर विवाद उभरे। शान स्वायत्तता, काचिन राज्य की मांग, और चिन क्षेत्र के विकास की कमी ने म्यांमार के एकीकरण में बाधाएँ पैदा की, जबकि केंद्र सरकार की बामर- और बौद्ध-केंद्रित नीतियों ने आज़ादी के बाद इन समस्याओं को बार बार उभारा, जिसने हथियारबंद संघर्षों को हवा ही दी। पांगलोंग समझौते में सीमांत क्षेत्रों के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान था, जिसे कार्यकारी अधिकार दिए गए थे, और जो इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व गवर्नर की कार्यकारी परिषद में करेगा।[32] समझौते ने सीमांत क्षेत्रों को आंतरिक प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान किया और उनके नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की गारंटी का वादा किया।[33] इसके अतिरिक्त, एकीकृत बर्मा के भीतर एक अलग काचिन राज्य की आवश्यकता को स्वीकार किया गया, जिसका निर्णय संविधान सभा को सौंपा गया। शान स्टेट्स की वित्तीय स्वायत्तता को बनाए रखा गया और काचिन और चिन हिल्स के लिए वित्तीय सहायता का वादा किया गया।[34] पांगलोंग समझौते का उद्देश्य बर्मा के विविध जातीय समूहों को स्वतंत्रता के एक साझा दृष्टिकोण के तहत एकजुट करना था, जबकि उनकी स्वायत्तता और विशिष्ट पहचान का सम्मान करना भी था।

पांगलोंग समझौता इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इससे स्वतंत्रता की प्रक्रिया तेज़ होती। लेकिन इस प्रक्रिया को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब 19 जुलाई 1947 को जनरल आंग सान की उनके अस्थायी सरकार के छह अन्य सदस्यों के साथ यांगून (तब रंगून) में हत्या कर दी गई।[35] हत्या का संदेह तुरंत आंग सान के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी यू-सॉ, पर गया, जो 1941 में जापानी आक्रमण तक बर्मा के प्रधानमंत्री रहे थे और म्यांमार की आज़ादी के बाद भी देश का शासन पूरी तरह अपने हाथ में ले लेना चाहते थे।

जनवरी 1947 में आंग सान के साथ यू-सॉ ने ब्रिटेन यात्रा की थी, लेकिन 27 जनवरी 1947 को एटली के साथ हुए स्वतंत्रता समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जनरल सान की हत्या के अगले दिन यू-सॉ को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला, और आख़िरकार 8 मई 1948 को फांसी पर चढ़ा दिया गया।[36] हालांकि, दुनिया के लोगों और मीडिया के एक वर्ग के लिए ये हत्याएं एक रहस्य रहीं और कुछ मीडिया प्रस्तुतियों में यह कहा कि यू-स़ॉ के हत्या में पूरी तरह शामिल होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं।[37] लेकिन आंग सान की हत्या बर्मा के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता के प्रमुख नेता और वास्तुकार थे। इसके बावजूद, बर्मा ने 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हो गई और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने सफर की शुरुआत की।

1947 का बर्मा संविधान: संघीयता और लोकतंत्र का प्रयोग

1935 का 'बर्मा एक्ट' देश की पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता था और महत्वपूर्ण विषय, जैसे रक्षा, विदेश नीति और सीमांत क्षेत्रों का नियंत्रण भी ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में रहता था। युद्ध के दौरान बर्मा के नेता आंग सान ने ब्रिटिश सरकार और जातीय अल्पसंख्यकों (शान, कचिन, कायाह) के साथ पांगलोंग समझौता किया, जिसमें एक संघीय संरचना के तहत सभी राष्ट्रीयताओं को समान भागीदारी का वादा किया गया था। इस समझौते ने अंग्रेज़ों को यह विश्वास दिलाया कि एक लोकतांत्रिक संविधान के माध्यम से बर्मा में स्थिरता लाई जा सकती है। साथ ही, दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के खिलाफ बढ़ते वैश्विक विरोध और संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशों की स्वतंत्रता की मांग ने ब्रिटिश साम्राज्य पर अपनी औपनिवेशिक नीति बदलने का दबाव डाला। आख़िरकार ब्रिटिश प्रशासन ने बर्मा में बढ़ती अस्थिरता और जातीय-राजनीतिक तनाव के कारण स्वतंत्रता और संविधान निर्माण को स्थिरता का एक रास्ता मान लिया।[38] वहीं, सच यह भी था कि ब्रिटेन के लिए बर्मा जैसे उपनिवेश पर शासन करना आर्थिक रूप से महंगा हो गया था, और दक्षिण-पूर्व एशिया में सामरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र और सहयोगी बर्मा की ज़रूरत थी। इस तरह से 1935 का 'बर्मा एक्ट' की जगह

पर 1947 के संविधान के माध्यम से स्वतंत्र और संघीय बर्मा की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का सपना देखा गया।[39]

1947 का बर्मा संविधान, स्वतंत्रता के बाद का पहला संविधान था और इसे एक प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक दस्तावेज़ माना जाता है। इसे 1935 के बर्मा अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनी हुई संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, जिससे इसे लोकतांत्रिक वैधता मिली। इस संविधान ने एक वास्तविक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया को साकार किया, लेकिन बाद में इसकी विफलता ने इसमें मौजूद उन कमज़ोरियों और चुनौतियों को उजागर किया, जो समय की कसौटी पर नहीं उतर पाए। यह संविधान वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल पर आधारित था, जिसमें एक औपचारिक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट थी, जो डिप्टी चैंबर के प्रति उत्तरदायी थी।[40] संविधान का उद्देश्य पांगलोंग समझौते को लागू करना था, जिसके तहत विभिन्न जातीय समूहों को उनकी मांगों और स्वशासन की क्षमता के आधार पर अलग-अलग स्तर की स्वायत्तता दी गई। बामर बहुल क्षेत्रों को एकात्मक राज्य के रूप में शासित किया गया, जहां संघीय संसद द्वारा सीधा कानून बनाया गया, जबकि शान, कचिन और कायाह राज्यों को पूर्ण राज्य शक्तियां प्रदान की गईं।[41] संघीय व्यवस्था में ऐसे क्षेत्र भी शामिल थे, जिन्हें सीमित स्वायत्तता प्राप्त थी, जैसे कि काव-थू-ले क्षेत्र (जो बाद में करेन राज्य बना) और चिन विशेष क्षेत्र। चिन जातीयता वाले क्षेत्रों को अलग से राज्य का दर्जा नहीं मिला था।[42]

संविधान की एक विशेषता यह थी कि इसमें अलग से चुने गए राज्य विधायिकाएं नहीं थीं। इसके बजाय, संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघीय संसद के सदस्यों से राज्य परिषदें बनाई गईं, जिन्होंने इन राज्यों की विधायिका के रूप में कार्य किया। राज्य सरकारों के नेता, जैसे कि शान और कचिन राज्यों के प्रमुख, संघीय सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य और संघीय शासन के बीच समन्वय स्थापित करना था, जो एंटी-फासीस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग (AFPFL) के शासन के दौरान प्रभावी रहा। हालांकि, 1958 में AFPFL के विभाजन के बाद बहुदलीय व्यवस्था में यह प्रणाली विफल हो गई, क्योंकि राज्य परिषदों और संघीय संसद

में अलग-अलग राजनीतिक बहुमत के कारण शासन में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई।

संविधान की एक और विशेषता शान और कायाह राज्यों के लिए अलगाव (सेशन) का अधिकार था। इस प्रावधान के तहत राज्य परिषद में दो-तिहाई बहुमत और जनमत संग्रह से जनता की इच्छा का निर्धारण आवश्यक था।[43] यह प्रावधान जातीय स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था, लेकिन इसने जनमत को विभाजित भी किया। कुछ के लिए, यह विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बीच एकता और परस्पर सम्मान के 'पांगलोंग भावना' का प्रतीक था।[44] दूसरों के लिए, यह एक कमजोर केंद्र का प्रतिनिधित्व करता था, जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन सकता था। 1947 के संविधान की संघीय संरचना अपने आप में कई नए सकारात्मक और समावेशी लोकतांत्रिक प्रयोगों का दुस्साहस कर रही थी, लेकिन यह जटिल और बाद में अस्थिर साबित हुई।

1948 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद, नए स्वतंत्र बर्मा राज्य को अस्थिरता का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जातीय समूहों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। इन विद्रोहों में सबसे पहले 1949 में करेन नेशनल यूनियन (KNU) का विद्रोह हुआ, जिसने करेन लोगों के लिए स्वतंत्रता की मांग की गई।[45] इसके बाद 1961 में गठित कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA), शान स्टेट आर्मी, मोन विद्रोही, करेनी विद्रोही और चिन नेशनल फ्रंट (CNF) जैसे अन्य समूहों ने भी हथियार उठाए।[46] इन विद्रोहों के साथ-साथ रेड फ्लैग और व्हाइट फ्लैग जैसे कम्युनिस्ट गुटों, पश्चिमी म्यांमार में मुजाहिद आंदोलनों और अराकान (आज के राखाइन राज्य) के अलगाववादी तत्वों ने राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया। यही नहीं बल्कि वो अल्पसंख्यक जो बर्मा सेना (बर्मा आर्मी) का हिस्सा थे, उनमें से भी कई लोग विद्रोह में शामिल हो गए। 1949 का करेन विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें करेन सेनाओं ने अन्य जातीय गुटों के साथ मिलकर रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।[47] अराकान क्षेत्र में, बौद्ध राखाइन और मुस्लिम मुजाहिद समूहों के संघर्षों ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इन आंदोलनों और संसाधनों से समृद्ध सीमा क्षेत्रों पर विद्रोहियों के नियंत्रण ने शासन और आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से बाधित किया।

दूसरा अध्याय

म्यांमार: लोकतंत्र का उत्थान और पतन (1948–1962)

म्यांमार के पहले प्रधानमंत्री यू-नु ने 4 जनवरी 1948 को बर्मा की सत्ता संभाली। संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र की रूपरेखा तैय़ार हो चुकी थी, संघीय ढांचे और नागरिक अधिकार भी संविधान के कागज़ों पर उकेरे जा चुके थे। जातीय और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए पंगलोंग समझौता जैसे प्रयास किए, लेकिन अलगाववाद और विद्रोह बड़ी चुनौतियां बनी रहीं। बौद्ध विचारों से ओतप्रोत यू-नु के साथ कम्युनिस्ट गुट और जातीय समूहों का वैचारिक टकराव भी जल्दी ही सामने आ गया, वहीं उत्तरी बर्मा में चीनी कूओमिनटांग राष्ट्रवादी भी यू-नु पर अलगाववाद का दबाव बना रहे थें।[48] इसके साथ-साथ देश के कुछ हिस्सों में गृहयुद्ध की चिंगारी जल रही थी। हालांकि, 1950 का दशक बर्मा के लिए प्रगतिशील था, क्योंकि अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ने लगी थी। बर्मी संविधान ने जातीय अल्पसंख्यक राज्यों के लिए 10 वर्षों के बाद स्वायत्तता की गारंटी दी थी, लेकिन यू-नु के नेतृत्व में यह लागू नहीं हो सका, जिससे व्यापक असंतोष फैला।[49]

इसके अलावा राजनीतिक दलों का सबसे प्रमुख समूह एंटी-फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग (AFPFL) भी जल्दी ही अपने विरोधाभासों का शिकार हो गया। AFPFL (एंटी-फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग) राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रभावशाली नेताओं तथा शक्तिशाली व्यक्तियों का एक ढीला परिसंघ था।[50] इसके सदस्य वामपंथ से वाम-मध्य राजनीति की व्यापक धाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जो किसी न किसी रूप में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। हर प्रमुख नेता के साथ अपने प्रतिबद्ध समर्थकों का समूह था, जिसमें सशस्त्र समर्थक भी शामिल थे। यहां तक कि पुलिस भी राजनीतिक आधार पर संगठित थी, और विभिन्न मंत्री पद AFPFL के गुटों के बीच बांटे गए थे।[51] लाभों और संसाधनों का वितरण व्यक्तिगत निष्ठाओं के आधार पर होता था।

वैचारिक मतभेदों की तुलना में व्यक्तिगत मतभेद अधिक महत्वपूर्ण थे। नतीजतन, AFPFL 1958 में "क्लीन AFPFL" और "स्टेबल AFPFL" दो भागों में विभाजित हो गया।[52] इसका मतलब यह भी था कि राजनीतिक ढांचे के एक महत्वपूर्ण ढांचे में ही विभाजन बहुत शुरु में ही हो गया, वह भी तक जब देश लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को चलाना सीख ही रहा था। वहीं बाद यह मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया कि 1947 का संविधान, हालांकि संघीय ढांचे की स्थापना करता था, लेकिन यह जातीय अल्पसंख्यकों की शिकायतों को पर्याप्त रूप से दूर करने में विफल रहा, जिससे विद्रोह और अस्थिरता को बढ़ावा मिला।[53] भ्रष्टाचार और संरक्षणवादी राजनीति ने AFPFL की विश्वसनीयता को और कमजोर कर दिया। इस अस्थिरता ने सेना को एक स्थिरता लाने वाले बल के रूप में उभरने का मौका दिया। 1958 तक आते आते AFPFL के अंदर तनाव की स्थिति इतनी बढ़ गई कि सेना को गृहयुद्ध की आशंका होने लगी। इस स्थिति से बचने के लिए 1958 में 'संवैधानिक तख्तापलट' किया गया और एक 'कार्यवाहक (अंतरिम) सरकार' का गठन किया गया।[54]

तत्कालीन प्रधानमंत्री यू-नु का यह एक असाधारण फैसला था, उन्होंने अपनी इच्छा से सत्ता सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल ने-विन को सौंप दी, ताकि देश में स्थिरता बहाल की जा सके और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। चुकी, यह कदम म्यांमार के संविधान के तहत लिया गया, इसलिए इसे 'संवैधानिक तख्तापलट' कहा गया।[55] हालाँकि, 1947 के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन इसकी अस्पष्टता ने यू-नु को इस कार्रवाई को सही ठहराने का मौका दे दिया। संविधान ने प्रधानमंत्री को संकटों को संभालने के लिए व्यापक कार्यकारी अधिकार दिए थे, लेकिन गंभीर राजनीतिक गतिरोधों से निपटने के लिए स्पष्ट तंत्र का अभाव था, जिससे सैन्य के अस्थायी हस्तक्षेप को वैधता मिली। 1958 का यह 'संवैधानिक तख्तापलट' म्यांमार में उस समय की लोकतांत्रिक संस्थानों की परिवक्वता को स्पष्ट रूप से सामने रखती है। इसके साथ ही भविष्य में होने वाले सैन्य हस्तक्षेपों की एक पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही थी।[56] इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संवैधानिक व्यवस्था सेना के हाथों में जाने से देश में थोड़े समय के लिए स्थिरता तो आई, लेकिन इससे सेना की राजनीति में भूमिका को वैध बनाने

और नागरिक नियंत्रण को कमजोर करने में भी मदद मिली। बहरहाल, सेना ने अक्टूबर 1958 में अंतरिम सरकार का गठन किया और जनरल ने-विन प्रधानमंत्री बने।[57]

'संवैधानिक तख्तापलट' और अंतरिम सरकार (1958-1960)

अंतरिम सरकार ने एक ऐसे समय में बागडोर संभालने की कोशिश की, जब देश का राजनीतिक ढांचा गंभीर संकट से गुज़र रहा था। राजनीतिक विभाजन अपने चरम पर पहुंच चुका था और लोकतंत्र के सपने पर बार-बार चोट कर रहा था। ऐसे में जनरल ने-विन के नेतृत्व में बनी यह अंतरिम सरकार के सामने एक राजनीतिक - प्रशासनिक स्थिरता स्थापित करने की चुनौती थी।[58]

देश में जातीय समूहों का विद्रोह, अतिवामपंथी धड़ों का विद्रोह और आंतरिक राजनीतिक विवादों से गुज़र रहा था। ऐसे में सेना ने सख्त रुख अपनाते हुए विद्रोहों और असहमतियों को दबाया। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी, नई सुरक्षा परिषदों और विद्रोहियों के खिलाफ सफल दमन के ज़रिए सरकार की पकड़ को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाकर और नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, सेना ने खुद को एक सक्षम और कुशल शासक संस्था के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की।[59] इसके अलावा, अंतरिम सरकार ने विदेशी मामलों में एक तटस्थ रुख बनाए रखा, म्यांमार की गुटनिरपेक्षता की नीति को जारी रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि देश शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा में न उलझे।[60]

अस्थाई और तुरंत मिली सफलताओं के बावजूद, अंतरिम सरकार को कई सीमाओं का सामना करना पड़ा, जिसने म्यांमार की राजनीतिक प्रणाली की अपरिपक्वता को उजागर कर दिया। जहां सेना कानून और व्यवस्था बहाल करने में कई हद तक सफर तो रही, वहीं इसके दमनकारी कार्यशैली ने राजनीतिक रूप से अलगाववाद को हवा दी। सरकार का ध्यान स्थिरता बनाए रखने पर था, जबकी इस स्थिरता के अंदर कई गहरे संरचनात्मक मुद्दे छिपे थे।[61] ये मुद्दे राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील थे जिसकी जड़ में जातीय अल्पसंख्यकों की स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की मांग ही थी। वहीं सेना ने कमोबेश सफल शासन ने राजनेताओं को लेकर एक संदेह की भावना को

पोषित ही किया, जिसमें भ्रष्ट, अक्षम और देश की जटिल चुनौतियों का प्रबंधन करने में अक्षम जैसी भावनाएं भी शामिल थीं।[62] इस एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, सेना का खुद को राष्ट्रीय एकता के अंतिम रक्षक के रूप में स्थापित करना। अंतरिम सरकार के प्रदर्शन ने सैन्य नेताओं के बीच इस धारणा को और मजबूत किया कि वे म्यांमार पर नागरिक राजनेताओं की तुलना में बेहतर शासन कर सकते हैं। अंतरिम सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने की इसकी क्षमता थी। इसने दिखाया कि सेना कम से कम औपचारिक रूप से नागरिक शासन को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध थी। इन चुनावों ने 1960 में यू-नु के 'क्लीन AFPFL' गुट को निर्णायक जीत दिलाई, जिससे अंतरिम सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया।[63]

1960 का चुनाव और सैन्य शासन की पूर्वपीठिका

1960 के सफल चुनाव के बाद यू-नु की सत्ता में वापसी हो गई, लेकिन जिन मुद्दों की वजह से देश की राजनीति तंत्र में सेना का हस्तक्षेप हुआ था, वो अभी भी अनसुलझे थे।[64] जातीय अशांति, प्रशासनिक अक्षमताएं और राजनीतिक अस्थिरता नागरिक सरकार को परेशान करती रही। बौद्ध धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित के विवादास्पद फैसले ने विशेष रूप से गैर-बौद्ध अल्पसंख्यक समूहों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। देश के विशाल भूभाग पर काबिज़ जातीय अल्पसंख्यकों की स्वायत्तता की मांग आंतरिक संघर्ष का एक बड़ा कारण था और इसके 1947 के संविधान ने भी सुनिश्चित करने की बात की थी।[65] लेकिन लोकतांत्रिक सरकार एक बार फिर से इस मुद्दे पर असफल रही। इसके उलट, सरकार प्रतीकात्मक उपायों, जैसे बड़ी संख्या में पगोडा (बौद्ध मंदिर) निर्माण में ज्यादा रुचि लेती हुई दिखाई दी। आर्थिक रूप से, मुद्रास्फीति और विकास के कार्यों में ठहराव ने असंतोष को और बढ़ा दिया।[66] नागरिक शासन में जनता का विश्वास कमजोर पड़ गया, और सेना भी बेचैन थी, क्योंकि सेना अब तक यह मान चुकी थी कि राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखने में सक्षम एकमात्र संस्था वह खुद है।

सत्ता का केंद्रीयकरण और कुलबुलाता असंतोष

राजनीतिक रूप से बर्मा का संघ स्वरूप एक एक नाजुक संरचना थी, जो 12 फरवरी 1947 को पंगलोंग समझौते का परिणाम थी। यह संघ मूख्य रूप से बर्मी क्षेत्रों और शान, काचिन, कायाह, और बाद में करेन राज्य के अस्थाई जैसे स्वरूप में गठित हुआ। इसके अलावा, चिन विशेष प्रभाग (प्रांत) भी था। 1947 के संविधान के तहत, शान और कायाह राज्यों को दस वर्षों के बाद जनमत संग्रह के माध्यम से संघ छोड़ने का अधिकार था। बाद में, सैन्य शासन के तहत, मोन और अराकान राज्यों की स्थापना हुई।[67] ज्यादातर बड़े अल्पसंख्यक जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व एक द्विसदनीय विधायिका में था, और प्रत्येक का अपना राजनीतिक तंत्र था, लेकिन उनके पास बहुत सीमित संसाधन थे। अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए, संघ के राष्ट्रपति का पद पर नियुक्तियों या चुनाव को जातीय आधार पर लचीला बनाया गया। पहले राष्ट्रपति शान समुदाय से थे तो दूसरे बर्मी, और तीसरा करेन जातीय समूह से। हालांकि 1962 के सैन्य तख्तापलट हो गया, नहीं तो दी गई व्यवस्था के तहत चौथा राष्ट्रपति काचिन समुदाय से होता। हालांकि, शक्ति प्रधानमंत्री के पास थी, जो अधिकांश नागरिक शासन अवधि में यू-नु थे।

1947 से 1960 के बीच बर्मा में चार चुनाव हुए। 1947 का चुनाव एक संविधान सभा के गठन के लिए आयोजित किया गया था, जिसने देश के ब्रिटिशों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार किया। इस चुनाव में 255 सीटों के लिए देश भर में चुनाव हुए। 1947 का चुनाव आयोजित करना बर्मा के लिए एक संसदीय लोकतंत्र की तैयारी का एक महत्वपूर्ण कदम था। इस चुनाव में AFPFL ने 210 में से 173 सीटें जीतीं।[68] 1951–52, 1956 और 1960 में भी बहुदलीय चुनाव हुए। पहले तीन चुनावों में AFPFL (एंटी-फासिस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग) ने एक एकीकृत पार्टी के रूप में भारी जीत हासिल की। विद्रोहियों की समस्याओं के कारण, अगला चुनाव जून 1951 से अप्रैल 1952 तक कई महीनों में आयोजित हुआ। इस चुनाव में AFPFL ने 250 में से 147 सीटें जीतीं।[69] वहीं, 1956 का चुनाव 27 अप्रैल को निचले सदन (चैंबर ऑफ डेप्युटीज) की 250 में से 202 सीटों के लिए हुआ; बाकी की 48 सीटों पर AFPFL के उम्मीदवारों के खिलाफ कोई

विपक्षी उम्मीदवार नामांकन न करने के कारण अपने आप ही चुना हुआ मान लिया गया। कुल मिलाकर, इस चुनाव में AFPFL ने 147 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि वामपंथियों के समूह 'नेशनल यूनाइटेड फ्रंट' ने 48 सीटें जीतीं।[70] इसके अलावा, यूनाइटेड हिल पीपल्स कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, देश की आज़ादी के बाद सरकार गठन के लिए चौथा लोकतांत्रिक चुनाव सेना की अंतरिम सरकार की देखरेख में 6 फरवरी 1960 को हुआ। इन चुनावों तक AFPFL दो हिस्सों में बंट चुका था और इस चुनाव ने यह तय किया कि कौन सा गुट अगली सरकार बनाएगा। इस चुनाव में 'AFPFL क्लीन गुट' ने भारी जीत दर्ज की। 1956 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली वामपंथियों का समूह 'नेशनल यूनिटी फ्रंट' इस बार एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसके अलावा, स्वतंत्र उम्मीदवार और जातीय आधार वाली पार्टियां भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां जातीय अल्पसंख्यक समूहों का वर्चस्व था।

टेबल 1

1956 के आम चुनाव के परिणाम (प्रतिनिधि सभा)[71]	
राजनीतिक दल	**सीटें**
AFPFL1	147
नेशनल यूनाइटेड फ्रंट (NUF)	48
निर्दलीय	13
यूनाइटेड हिल पीपल्स कांग्रेस (UHPC)	14
बर्मा डेमोक्रेटिक पार्टी (BDP)	0
बर्मा नेशनलिस्ट ब्लॉक (BNB)	1
पीपल्स इकनोमिक कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (PECDO)	4
ऑल शान स्टेट ऑर्गेनाइजेशन (ASSO)	4
अराकान नेशनल यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन	5
शान स्टेट्स पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (SSPO)	2
कचिन नेशनल कांग्रेस (KNC)	2
यूनाइटेड नेशनल पा-ओ ऑर्गेनाइजेशन (UNPO)	1
अनिर्णीत सीटें	9

आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में आधिकारिक शिक्षा बर्मी भाषा में ही होती रही थी, और स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें और सामग्रियों की आधिकारिक तौर पर अनुमति नहीं थी (कुछ चीनी प्रकाशनों को छोड़कर)। स्थानीय भाषाओं को निजी स्तर पर और गैर-सरकारी संस्थानों, जैसे चर्चों में पढ़ाया जाता था, लेकिन आधिकारिक पाठ्यक्रम बर्मी केंद्र द्वारा अनिवार्य था। हालांकि 1947 का संविधान (और इसके बाद के संविधान) स्थानीय संस्कृतियों की रक्षा का आह्वान करता था, लेकिन इसे प्रभावी केंद्रीय सरकारी समर्थन प्राप्त नहीं था।

अल्पसंख्यक सरकारों की स्थायी शिकायत यह थी कि केंद्र सरकार उनके लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित नहीं करती थी। अल्पसंख्यक अक्सर दावा करते थे कि भले ही उनकी जनसंख्या कम हो, उनकी भूमि का क्षेत्रफल बड़ा था और राज्य के अधिकांश प्राकृतिक संसाधन अल्पसंख्यक क्षेत्रों में थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली। कुछ अल्पसंख्यक सीधे विदेशी सहायता एजेंसियों के साथ बातचीत करना चाहते थे, लेकिन केंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया, शायद इस डर से कि विदेशी साजिशें अलगाववाद के प्रयासों में मदद कर सकती हैं।[72] इस बीच बहस में धर्म का मामला भी सामने आया, प्रधानमंत्री नु एक कट्टर बौद्ध धर्मावलंबी थे और देश में इनकी संख्या भी सर्वाधिक थी। ऐसे में यू-नु ने अपने दूसरे कार्यकाल (1960-1962) में बौद्ध धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया,[73] जिससे कई अल्पसंख्यक समूहों के साथ साथ, काचिन और चिन जैसे ईसाई अल्पसंख्यकों को और अधिक अलग-थलग कर दिया, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव गहरा हो गया।

1962: निलंबित लोकतंत्र और सैन्य शासन की शुरुआत

जनरल ने-विन के नेतृत्व में वर्ष 1962 में हुआ सैन्य तख्तापलट देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2 मार्च 1962 को सेना ने रंगून में महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों पर तेजी से कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री यू-नु, कैबिनेट मंत्रियों, और शान और करेननी समुदायों के नेताओं सहित कई प्रमुख हस्तियों को हिरासत में ले लिया। तख्तापलट के बाद 1947 के संविधान को निलंबित कर दिया गया और ने-विन के नेतृत्व में एक परिषद ने सत्ता संभाली। इसने

केंद्रीकृत नियंत्रण लागू किया और संघवाद के लिए जातीय आकांक्षाओं को दरकिनार कर दिया।

1962 का सैन्य तख्तापलट देश के राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था। इस सैन्य शासन के दौरान न सिर्फ 1947 के संविधान को निलंबित कर दिया गया बल्कि संघीय ढांचे को समाप्त कर दिया गया, और ने-विन के नेतृत्व में क्रांतिकारी परिषद (रेवोल्युश्नरी काउंसिल/RC) को एकमात्र प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया।[74] "बर्मी समाजवाद" (Burmese Way to Socialism) की शुरुआत ने एक कट्टरपंथी वैचारिक परिवर्तन को स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें समाजवादी सिद्धांतों को बर्मी सांस्कृतिक मूल्यों के ऊपर थोपने की कोशिश की गई।[75] इसके परिणामस्वरूप देश के संस्थाओं का व्यापक रूप से शासन ने राष्ट्रीयकरण के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। इसका एक उदाहरण उद्यमों में विदेशी निवेश को समाप्त करना भी था। इस नए शासन ने लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित रूप से पंगु बना दिया, साथ ही सत्ता और सैन्य नेतृत्व का घालमेल करके उसे केंद्रीकृत कर दिया गया।[76] इस प्रक्रिया में जातीय अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डाल दिया गया, जो पहले से ही संघीय समझौतों के माध्यम से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। तात्मदॉ (सेना) ने शासन, अर्थव्यवस्था और राज्य नौकरशाही के हर पहलू में खुद को गहराई से शामिल कर लिया। बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (BSPP) के गठन ने एकदलीय शासन को संस्थागत रूप दे दिया और निगरानी और दमन की एक सर्वव्यापी प्रणाली स्थापित की।[77]

चित्र 2

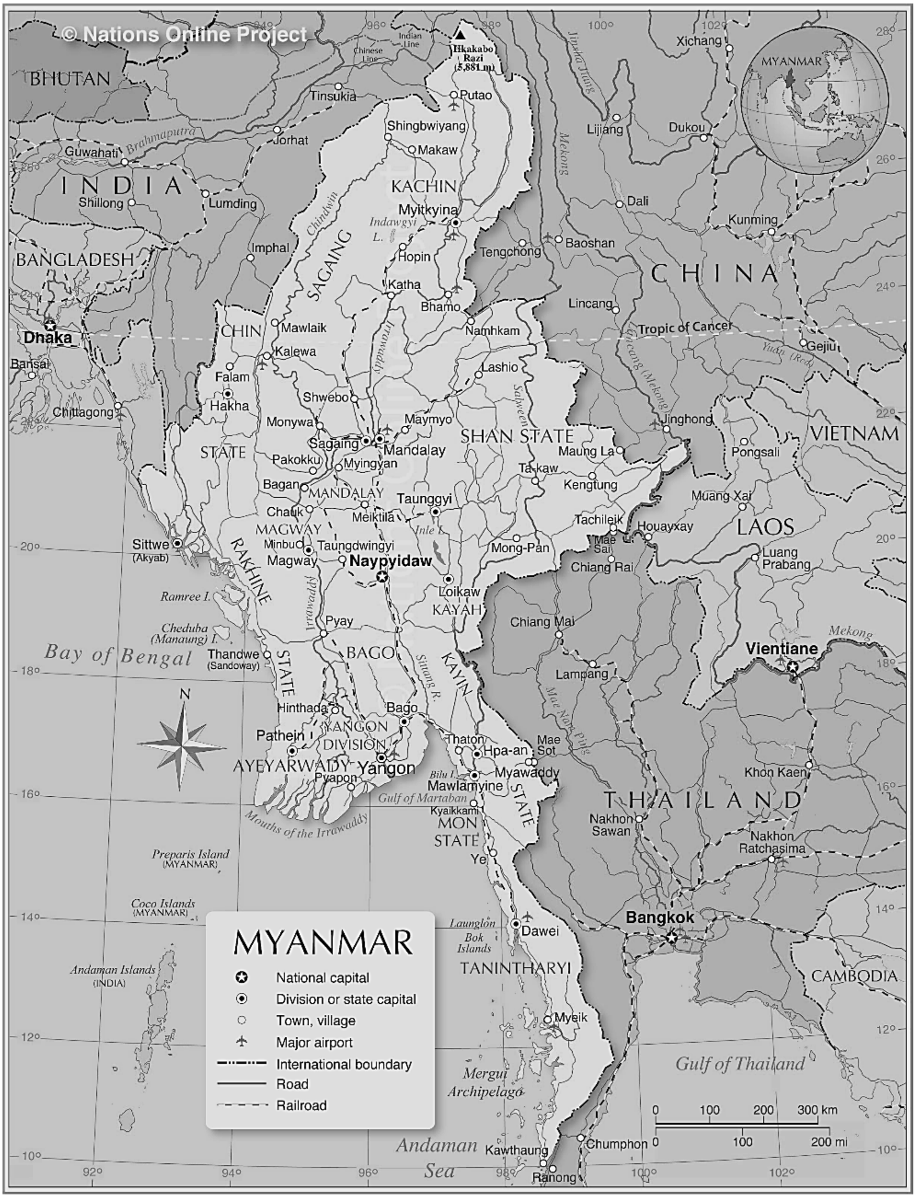

Source: "Political Map of Myanmar," Nations Online Project,
at https://www.nationsonline.org/oneworld/map/Myanmar-political-map.htm#google_vignette.

इस तख्तापलट के दीर्घकालिक परिणाम बहुत गहरे थे। म्यांमार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से अलग-थलग पड़ गया और आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे यह दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। राज्य-नियंत्रित आर्थिक नीतियों के कारण व्यापक गरीबी की स्थिति बनने लगी। जातीय स्वायत्तता की आकांक्षाओं के दमन ने सशस्त्र नागरिक संघर्षों को जन्म दिया।[78] 1962 का तख्तापलट केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि एक परिवर्तनकारी अवधि थी, जिसने म्यांमार के राजनीतिक संरचना को मौलिक रूप से बदल दिया। इसने सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक अलगाव, और जातीय तनाव के एक सिलसिले को स्थापित कर दिया।

लोकतंत्र से सैन्यतंत्र की ओर (1962 – 1974)

1962 से शुरु हुए एक नई राजनीतिक प्रणाली ने म्यांमार के राजनीतिक इतिहास में एक परिवर्तनकारी और उथल-पुथल भरे अध्याय को आकार दिया। जिसे जनरल ने-विन के नेतृत्व में सैन्य शासन को संरचनात्मक रूप से मज़बूत तो किया ही साथ ही व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों द्वारा को भी नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की। 2 मार्च 1962 को हुए सैन्य तख्तापलट ने 1947 के संविधान के तहत स्थापित लोकतांत्रिक शासन को अचानक समाप्त कर दिया, जिसकी जगह पर क्रांतिकारी परिषद (रेवोल्युश्नरी काउंसिल/RC) को स्थापित करने की कोशिश हुई।[79] इस परिषद पूरी तरह से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का ही वर्चस्व था, जिसने देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया।[80] इसके तुरंत बाद, 1947 के संविधान को निलंबित कर दिया गया, और संसद, राजनीतिक दलों और स्वतंत्र संस्थाओं को भंग कर दिया गया। सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ क्रांतिकारी परिषद में केंद्रित हो गईं।[81]

तख्तापलट को सेना द्वारा जातीय अलगावादी ताकतों को रोकने, शासन की विफलताओं को संभालने, और संघ को सुदृढ़ करने के नाम पर सही ठहराया गया। लेकिन सैन्य तानाशाही के इस दौर में भी जातीय अल्पसंख्यकों की गतिविधियों और उनसे संवाद व सामंजस्य की कमी के कारण तनाव और विद्रोह की स्थिति बढ़ ही रही थी, वहीं देश में शासन की चुनौतियाँ भी बेहतरी से दूर ही दिख रही थीं।[82] सत्ता को केंद्रीकृत करने के बार-बार किए गए प्रयासों ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों को अलग-थलग कर दिया, जिन्होंने राज्य को बमर प्रभुत्व के एक औज़ार के रूप में देखा।

30 अप्रैल 1962 को, क्रांतिकारी परिषद ने समाजवाद के एक बर्मी संस्करण यानी 'बर्मी समाजवाद' ('The Burmese Way to Socialism'" 'द बर्मीज़ वे टू सोशलिज्म') पेश किया, जो समाजवाद, राष्ट्रवाद, और बौद्ध धर्म के

सिद्धांतों को मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था और समाज को पुनर्गठित करने का एक वैचारिक ढाँचा था।[83] देश में उद्योगों, व्यापार, निजी स्कूलों, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जबकि विदेशी एजेंसियों और मिशनरियों को बाहर कर दिया गया।[84] इससे आर्थिक अलगाव, व्यापक गरीबी, और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी होने लगी। इन नीतियों की वजह से भारतीय और चीनी व्यापारियों का देश के बाहर भी पलायन शुरु हो गया।[85]

इन नीतियों का वैदेशिक और कूटनीतिक संबंधों पर काफी असर होने लगा, जिसमें वीज़ा प्रतिबंध देश को एक भूराजनीतिक रूप से एक अलगाव की ओर ले जाने लगे।[86] जुलाई 1962 को हुई एक विशेष घटना ने पूरी दुनिया का का ध्यान अपनी ओर खींचा जिसने यह भी बताया कि कैसे सैन्य शासन देश के परंपरागत और औपनिवेशिक संघर्ष के प्रतीकों को भी देखना नहीं चाहता। दरअसल में, शासन के आदेश पर रंगून विश्वविद्यालय छात्र संघ के उस भवन को ध्वस्त कर दिया गया, जो उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलन का प्रतीक स्थल था।[87]

जुलाई 1962 में बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (BSPP) की भी स्थापना की गई। इस पार्टी ने म्यांमार में सैन्य शासन (जुंटा) को संस्थागत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पार्टी का विस्तार शुरु में केवल सैन्य अधिकारियों तक ही सीमित था जो 1970 के दशक तक एक जन-संगठन में बदल गई।[88] जिसने समाज के प्रबुद्ध वर्गों (सिविल-सोसाईटी), प्रशासन, और राजनीतिक विमर्शों को भी नियंत्रित किया। इसका असर धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन में भी पड़ा शुरु हो गया। BSPP की सदस्यता नौकरियों में प्रगति के लिए आवश्यक बनती गई, जिससे पार्टी का प्रभाव राज्य प्रणाली के हर स्तर पर मजबूत हुआ।[89] 1964 तक आते आते देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी विशेषकर कृषि उत्पादन में कमी आई, काले बाजार और भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ता गया। बिगड़ते हालातों को देखते हुए जुंटा ने 1964 में आर्थिक स्थिरीकरण के लिए मुद्रा विमुद्रीकरण की कोशिश की, जो असफल रहा, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं।[90] 1960 के दशक के अंत तक आते-आते सैन्य शासन को लेकर आम लोगों के बीच असंतोष बढ़ने लगा। राजनीतिक असंतोष के सवाल

को लेकर बढ़ते दबाव के बीच जुंटा ने वर्ष 1971 में एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की घोषणा कर दी।[91]

1974 का संविधान

सैन्य शासकों ने भले ही 1971 में संविधान निर्माण की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस पर काम होने और निर्माण में कई साल और लग गए यानी 1962 की सैन्य तख्तापलट से लेकर 1974 तक एक दशक के ज्यादा समय तक जुंटा बिना किसी संविधान के शासन कर चुका था।[92] वर्ष 1947 का पंगलोंग समझौता इस बात को मुखरता से कहता है कि शान, काचिन और चिन जातीय समूहों एकीकृत स्वतंत्र बर्मा में शामिल होंगे बशर्ते कि उन्हें 'आंतरिक प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता' और 'सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को लोकतांत्रिक समाजों में माने जाने वाले मौलिक अधिकार और विशेषाधिकार' दिए जाएंगे।[93] लेकिन ऐसा लगा कि 1970 के दशक आते आते देश का नेतृत्व समझौते के उन वादों से दूसरी ओर रुख कर चुका है। सितंबर 1971 में, ने-विन ने 97 सदस्यीय संविधान मसौदा आयोग का गठन किया, जिसने क्रांतिकारी परिषद की सख्त निगरानी में एक नया संविधान तैयार किया।[94] दिसंबर 1973 में, इस संविधान को अनुमोदित करने के लिए एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया, जिसमें 94.45 प्रतिशत मतदाताओं ने इसे समर्थन दिया,[95] हालांकि इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए।[96]

1960 के दशक के अंत तक, म्यांमार के लोगों में सैन्य शासन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा था। बढ़ते दबाव और राजनीतिक असहमति के जवाब में, सैन्य सरकार ने 1971 में एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की घोषणा की।[97] इस कदम का उद्देश्य अपने शासन को वैध बनाना और जनता की चिंताओं का समाधान करना था। हालांकि, 1973 में नए संविधान के लिए हुए जनमत-संग्रह पर निष्पक्षता और वैधता को लेकर गंभीर सवाल उठे। इन गंभीर सवालों के केंद्र में था 1962 के तख्तापलट के बाद का नियंत्रित राजनीतिक माहौल क्योंकि इस माहौल में सैन्य सैन्य शासन ही जनमत-संग्रह की पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रही थी। आधिकारिक आंकड़ों में मतदान में उच्च भागीदारी और भारी समर्थन दिखाया गया, लेकिन पारदर्शिता और स्वतंत्र सत्यापन की कमी के कारण इन आंकड़ों पर व्यापक रूप से सवाल उठाए गए।

जनमत संग्रह में राजनीतिक भागीदारी और बहस को सीमित रखा गया था। विपक्षी आवाज़ों को अपनी बात रखने के मौके सीमित ही रहे और वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए बहुत कम जगह दी गई।[98] शासन और उसके तंत्र की दबाव की अनकही व्यवस्थाओं ने पूरी प्रक्रिया पर और संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि नए संविधान पर मतदान परोक्ष रूप से मौजूदा सैन्य शासन पर ही जनमत संग्रह था। इन सभी वजहों ने 1973 के जनमत संग्रह को निष्पक्ष नहीं माने जाने की धारणा को जन्म दिया और नए संविधान की वैधता पर सवाल खड़े किए।

1974 का संविधान और संघीय ढांचे का पतन

1974 का संविधान म्यांमार के राजनीतिक इतिहास का मील का पत्थर इसलिए भी है क्योंकि इसने 1947 के संविधान के ज़रिए देश के संघीय संरचना को स्थापित करने की कोशिश की थी उसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इन नए संविधान ने सैन्य शासन को संवैधानिक रूप से एक संस्थागत रूप दिया और बहुदलिय शासन के बजाए एक दल के प्रभुत्व के लिए रास्ते खोल दिए। यह संविधान मुख्य रूप से सेना के शासन को वैधता प्रदान करने, उसकी शक्ति को सुदृढ़ करने और देश को समाजवादी दिशा में ले जाने के लिए तैयार किया गया था।

इस एकात्मक प्रणाली या कहें एक दलिय राजनीतिक प्रणाली में BSPP को एकमात्र वैध पार्टी के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई। यह संविधान 1947 के अपने पूर्ववर्ती के कई स्तरों पर बिल्कुल विपरीत था। मसलन, 1947 का संविधान द्विसदनीय था, 1974 एकसदनीय; 1947 एक बहुदलीय लोकतंत्र था, 1974 एक एकदलीय शासन; 1947 संविधान म्यांमार में वेस्टमिंस्टर प्रणाली को लागू करने का प्रयास था, जबकि 1974 का संविधान सोवियत-शैली के साम्यवादी ढांचे का अनुसरण करता था।[99] इस प्रकार, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी तीनों शाखाओं पर हावी एकमात्र कानूनी पार्टी बन गई। 1974 का संविधान सात राज्यों और सात क्षेत्रों की एक नई क्षेत्रीय संरचना की स्थापना करता है। इसमें राज्यों और प्रभागों के बीच औपचारिक समानता का सिद्धांत पेश किया गया। हालांकि, सभी विधायी शक्तियां केंद्र स्तर की एकसदनीय संसद के पास थीं। न्यायपालिका भी पार्टी के अधीन थी और किसी स्वतंत्र संस्था की अनुमति नहीं थी।[100]

सैन्य शासन के प्रमुख जनरल ने-विन ने 1972 में सेना से सेवानिवृत्ति ली लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते रहे।[101] 1974 में नए संविधान के तहत हुए पहले आम चुनाव ने प्रत्यक्ष सैन्य शासन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, लेकिन BSPP के प्रभुत्व ने राजनीतिक शक्ति को केंद्रीकृत और निरंकुश बनाए रखा।[102, 103]

27 जनवरी से 10 फरवरी 1974 के दौरान म्यांमार में आम चुनाव की प्रक्रिया हुई, जो 1973 के जनमत संग्रह में अपनाए नए संविधान के तहत पहला चुनाव था। चुनाव में जनरल ने-विन के नेतृत्व वाली BSPP ने पीपुल्स असेंबली की सभी 451 सीटों पर जीत हासिल की।[104] चुकी इस चुनाव में एक ही वैध राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने थी और मतदान करना भी अनिवार्य था तो चुनाव का परिणाम का एकतरफा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। नतीजतन, पीपुल्स असेंबली (तब की म्यांमार की एकसदनीय संसद) की सभी सीटें सेना के प्रति वफादार BSPP सदस्यों से भर गईं।[105] यह स्थिति 1974 के संविधान को लागू करने के बाद की बेहद केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली की एक तस्वीर थी, जिसमें असहमति या विरोध के लिए कोई स्थान नहीं था।[106] जिन जातीय अल्पसंख्यकों ने लंबे समय से अधिक स्वायत्तता और उनके अधिकारों की मान्यता की मांग की थी, वे इस नई प्रणाली के तहत और भी अधिक हाशिए पर आ गए, जिसने समावेशिता के बजाय केंद्रीकरण को प्राथमिकता दी।[107] जुंटा ने इस कदम को देश में स्थिरता और प्रगति की दिशा में एक कदम के रूप में सामने रखा, लेकिन यह भी साफ हो रहा था कि अधिनायकवाद स्थिति गहरी होती जा रही है। चुनाव की खामियां, जैसे पारदर्शिता की कमी, असहमति का दमन और वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति ने जनता की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का दमन ही किया। इस घटना ने दशकों तक राजनीतिक दमन, सामाजिक अशांति और देश में लोकतंत्र और स्वायत्तता के संघर्ष की आशंकाओं को और बढ़ा दिया।

बदलती राजनीतिक संरचनाएं और जातीय समूह

1962 के बाद के सैन्य शासन में, तात्मदॉ ने कठोर काउंटर-इंसर्जेंसी रणनीतियों को तेज़ी से आगे बढ़ाया। जिनमें "फोर कट्स" की नीति प्रमुख थी। फोर कट्स' एक ऐसी सैन्य रणनीति थी, जिसे 1960 और 1970 के दशक में देश की सेना

ने विद्रोही जातीय सशस्त्र समूहों को कमजोर करने के उद्देश्य से लागू किया था।[108] इस नीति का मकसद विद्रोहियों को समर्थन प्रदान करने वाले चार मुख्य संसाधनों—खाद्य आपूर्ति को पूरी तरह बाधित करना, आर्थिक संसाधनों के स्रोतों का सफाया करना, खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को तोड़ना, और विद्रोही संगठनों में भर्ती की रफ्तार को बाधित या पूरी तरह समाप्त करना था।[109] सेना ने ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए, जिसमें नागरिकों को उनके गांवों से विस्थापित करना, फसलें जलाना, और खाद्य आपूर्ति रोकना जैसे कठोर कदम शामिल थे। इन उपायों से विद्रोही समूहों को कमजोर करने में कुछ सफलता मिली, लेकिन इसके कारण आम नागरिकों को व्यापक दमन और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस नीति की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ, जिसमें बलात्कार, हत्या और आम लोगों की संपत्तियों का नुकसान जैसी गतिविधियां शामिल थी।[110] "फोर कट्स" नीति ने म्यांमार में जातीय संघर्ष को और गहरा किया और सैन्य शासन के प्रति असंतोष बढ़ा दिया।

म्यांमार का इतिहास यह भी बताता है कि कैसे केंद्रीय स्तर से नियंत्रण की कोशिशों के बीच विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनों ने एकजुट होने की कोशिशें की। जिनमें शान स्टेट आर्मी (SSA) शामिल थी, जो 1964 में शान नेशनल यूनाइटेड फ्रंट और शान स्टेट इंडिपेंडेंस आर्मी (SSIA) के विलय के बाद सामने आई। बाद में इसका एक राजनीतिक विंग, शान स्टेट प्रोग्रेस पार्टी (SSPP), विकसित हुआ। करेनी नेशनल प्रोग्रेस पार्टी (KNPP), 1875 की संधि पर आधारित एक प्रमुख गैर-समाजवादी समूह, अपने सैन्य अंग, करेनी लिबरेशन आर्मी की एकजुटता को और मज़बूत करने की कोशिश की। वहीं, 1970 के दशक के दौरान पश्चिम में रोहिंग्या पैट्रियोटिक फ्रंट को "फोर कट्स" जैसी क्रूर अभियानों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से रोहिंग्या आबादी को न सिर्फ व्यापक हिंसा का शिकार होना पड़ा बल्कि उन्हें विस्थापन के लिए भी मजबूर होना पड़ा। काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गनाइजेशन (KIO) और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA), बर्मी कम्युनिस्ट पार्टी (BCP) के साथ सहयोग करने के लिए एक मंच पर आए, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में अपने-अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों की वजह से विरोधाभास पैदा हुए, जिससे वो एक बार फिर अलग हो गए। इसी तरह, 1970 के दशक की शुरुआत में शान स्टेट

आर्मी और बर्मी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहयोग की शुरुआत तो हुई लेकिन 1976 में मादक पदार्थों के व्यापार को लेकर विवाद के कारण दोनों के रास्ते फिर से अलग हो गए।[111] हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत तक कुछ स्तरों पर सहयोग जारी रहा। इसके अलावा, वा नेशनल आर्मी (WNA) ने BCP नेतृत्व को चुनौती दी,[112] जिससे इस अवधि के दौरान म्यांमार के जटिल जातीय और राजनीतिक परिदृश्य में एक और परत जुड़ गई। ये घटनाक्रम इस युग में म्यांमार के आपस में जातीय स्तर पर विभाजन और संघर्षग्रस्त दौर को सामने रखते हैं, क्योंकि इन जातीय समूहों का संघर्ष केंद्रीय सैन्य सत्ता से था बल्कि कई बार इनका टकराव दूसरे जातीय समूहों के साथ होता था, विशेषकर उस समय जब हितों का टकराव और प्रभाव क्षेत्र के विरोधाभास सामने आते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह टकराव आज भी गृहयुद्ध की स्थिति में किसी न किसी रूप में जारी है।

1970 के दशक में एक बदलाव यह भी हुआ कि जातीय सशस्त्र समूहों ने छात्र और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन करना शुरू किया, जिससे तात्मदॉ के खिलाफ उनका प्रतिरोध बढ़ गया। वहीं, 1974 के छात्र प्रदर्शनों ने तात्मदॉ की नीतियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष को उजागर किया। यही वह दौर भी था जब नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (NDF) का भी उदय हुआ, जो विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहों का गठबंधन था, जिसका उद्देश्य तात्मदॉ के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को एकजुट करना था। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (NDF) 1976 में स्थापित हुआ, जिनका दावा रहा है कि वह म्यांमार के स्वदेशी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।[113] आधिकारिक दस्तावेज़ों के मुताबिक इस फ्रंट में "अराकान, चिन, करेन, करेनी, काचिन, लाहू, मोन, पा-ओ, पालाउंग, शान और वा समुदाय शामिल हैं। अपनी स्थापना के समय से ही फ्रंट ने अपना उद्देश्य अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक वास्तविक संघीय म्यांमार संघ के निर्माण के कोशिशों को पूरा करना रहा।"[114] एनडीएफ ने मुखर रूप से म्यांमार के लिए एक संघीय राजनीतिक सरंचना की स्थापना को रखा, जहां विभिन्न जातीय समूहों को अधिक आत्मनिर्णय और प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

ज्यादातर जातीय नेताओं ने 1974 की नई संवैधानिक व्यवस्था संघीय व्यवस्था और स्वायत्तता के वादों के बरअक्स एक विश्वासघात के रूप में देखा। इसके परिणामस्वरूप, करेन, शान, और कचिन जैसे जातीय समूहों के विद्रोह और तीव्र हो गए, जिनमें इन समूहों ने सैन्य ठिकानों पर हमले शुरु कर दिए।[115] करेन ने अपना सशस्त्र संघर्ष जारी रखा, विशेषकर आज के कयिन जैसे क्षेत्रों में। सबसे बड़े राज्यों में से एक, शान में भी 1970 के दशक के अंत में सशस्त्र जातीय समूहों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया।[116] कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA) ने भी अपनी गतिविधियाँ तेज कीं और उत्तरी म्यांमार में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरु किया। मोन और अराकानी समूहों ने भी, विशेष रूप से थाई-म्यांमार और बांगलादेश सीमा क्षेत्रों में, विद्रोही गतिविधियों को तेज़ कर दिया।[117] इसके अलावा, जातीय विद्रोहियों के साथ-साथ छात्र और श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन भी बढ़े। इन सशस्त्र जातीय संघर्षों ने म्यांमार में हिंसा और असंतोष की ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की जो अभी तक देश में गहरे विभाजन और संघर्षों का कारण बनी हुई है।

चौथा अध्याय

नई एकपक्षीय संवैधानिक व्यवस्था और प्रतिनिधित्व का सवाल

6 जून 1974 को तब की म्यांमार की राजधानी रंगून में छात्रों के एक बड़े प्रदर्शन पर मौजूदा सैन्य प्रशासन ने गोलियां चलाना का आदेश दे दिया। सैन्य प्रशासन की यह कार्यवाई इतनी बड़ी थी कि इस गोलीबारी में 100 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई।[118] छात्रों का यह प्रदर्शन उस आंदोलन का हिस्सा था जो काफी पहले से ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी, आर्थिक दुशवारियों और राजनीतिक प्रक्रिया में सेना की बढ़ता वर्चस्व जैसे मुद्दों को लेकर चल रही थी।[119] छात्रों ने पहले के प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक बंदियों की रिहाई, छात्रों को संघ बनाने की स्वतंत्रता और वस्तुओं की कीमतों में कमी की मांग भी एक प्रदर्शन का हिस्सा था।[120] इन समस्याओं के मुख्य-रूप से सैन्य दमन के प्रति गहरी नाराजगी से जुड़ी थी।

प्रदर्शनकारियों में से कई जातीय अल्पसंख्यक समूहों से भी लोग मौजूद थे, जो छात्रों के साथ एक समावेशी संघीय राजनीतिक प्रणाली की भी मांग कर रहे थे।[121] हिंसात्मक दमन यह भी बताने के लिए था कि सैन्य सरकार लोकतांत्रिक सुधारों या समावेशी राजनीतिक प्रणाली की मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 6 जून 1974 का नरसंहार कोई एकल घटना नहीं थी, बल्कि तब के शासन के दमन के सिलसिले का एक हिस्सा ही कहा जा सकता है। यह घटना बर्मा की बहुसंख्यक केंद्रीय सरकार और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के बीच गहरे तनाव का प्रतीक बन गई, जिनमें से कई लंबे समय से एक संघीय प्रणाली की मांग कर रहे थे।[122] लेकिन इस सबके बावजूद, 6 जून 1974 की घटना और इसके परिणामों ने म्यांमार में राजनीतिक विरोध की एक लंबी परंपरा स्थापित की। इसने राज्य प्रायोजित हिंसा के एक ताने-बाने को स्थापित किया, जो भविष्य में राजनीतिक आंदोलनों और विरोधों का हिस्सा बना। इस घटना ने एक संघीय संवैधानिक आंदोलन को और मजबूत किया, क्योंकि इसने यह

साबित किया कि सैन्य शासन में शक्ति साझा करने की कोई संभावना नहीं है। इसने अल्पसंख्यक जातीय समुदायओं में अहिंसक रास्ते से अपने लिए स्वायत्तत राजनीतिक प्रणाली स्थापित करने के भरोसे तो तोड़ दिया।[123] इसके साथ ही लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं और जातीय संगठनों के बीच प्रतिरोध की एक साझे सफर की शुरुआत कर दी। लोकतांत्रिक सुधारों और दूसरे सामयिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी ही था। ये आंदोलन का मकसद ही तातमादॉ के केंद्रीकृत शासन को चुनौती देना था, ऐसे में सैन्य सरकार ने 11 दिसंबर 1974 को बढ़ते प्रदर्शनों के जवाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया।[124] इसके अगले दिन, 12 दिसंबर को, रंगून में हुई हिंसक कार्रवाई में नौ लोगों की मौत हो गई, जो देश के लंबे लोकतांत्रिक संघर्ष और संघीय संवैधानिक शासन की इच्छा का एक और दर्दनाक अध्याय है।[125] मार्शल लॉ की घोषणा ने सैन्य शासन को असहमतियों को दबाने के लिए व्यापक अधिकार दिए।

नियमित विधायी चुनाव और प्रतिनिधित्व का मुद्दा

1 से 15 जनवरी 1978 के बीच म्यांमार में एक बार फिर से आम चुनाव हुए और एक बार फिर से उस समय तक एकमात्र वैध राजनीतिक दल बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (BSPP) ने अपने दबदबे को साबित किया। जनरल ने-विन के नेतृत्व में BSPP ने पीपुल्स असेंबली की सभी 464 सीटों पर जीत हासिल की।[126] जैसे ऊपर दिए गए घटनाक्रमों से पता चलता है कि 1978 के चुनाव व्यापक असंतोष, हिंसक दमन और अशांति की पृष्ठभूमि में हुए। इन चुनावों ने एक बार फिर से केंद्रीय सरकार को एक दमनकारी ताकत में संवैधानिक रूप से स्थापित कर दिया, नतीजतन कई जातीय अल्पसंख्यकों ने अपने सशस्त्र प्रतिरोध को तेज़ कर दिया।[127] 1978 के चुनाव ने म्यांमार के लोकतंत्र और संघवाद के लिए संघर्ष करने वाले तत्वों, संस्थानों, समूहों और साथ ही साथ स्वायत्तता की और देश के संसाधनों पर न्यायपूर्ण बंटवारे की मांग करने वाले अल्पसंख्यक जातीय समूहों को स्पष्ट संदेश दिया कि BSPP का अधिनायकवादी प्रभुत्व के खिलाफ राजनीतिक बहुलता हासिल करने का संघर्ष अभी लंबा और चुनौतियों भरा है।[128]

अक्टूबर 1981 में म्यांमार एक बार फिर से विधायी चुनाव का गवाह बना, जो एक बार फिर से बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (BSPP) के लिए एक-पक्षीय

ही साबित हुए। BSPP को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के पीपुल'स असेंबली 475 सीटें में से सभी 475 सीटें मिली।[129] 1981 के विधायी चुनाव BSPP की सत्ता पर अपनी पकड़ को वैधता प्रदान करने के लिए अब तक एक नियमित राजनीतिक चक्र का हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि एक बार फिर से इस चुनाव में, विपक्षी दलों या स्वतंत्र उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति न होने के कारण, यह जन इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। 1974 के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री तो बदलते रहे लेकिन BSPP की राज्य तंत्र पर पार्टी की पकड़ बनी रही।[130] हालांकि, बढ़ती आर्थिक चुनौतियों और बर्मी समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से जातीय अल्पसंख्यकों और छात्र समूहों का असंतोष जारी रहा। राजनीति वर्चस्व का ये सिलसिला आने वाले चुनाव में भी जारी रहा। अक्टूबर 1985 में हुए विधायी चुनाव में एक बार फिर से BSPP ने सभी 489 सीटें जीत लीं।[131] इसी दौर में जातीय समूहों और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी भी एक संरचनात्मक आकार ले रही थी।[132]

सशस्त्र विद्रोह और सेना

1970 और 1980 के दशक में, बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी (CPB) और दूसरे हथियारबंद जातीय समूहों की म्यांमार की सेना और केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहा, विशेष रूप से चीन और थाईलैंड की सीमाओं से सटे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में।[133] ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन सीमाई राज्यों में काफी जातीय विविधता थी और यहां कई सशस्त्र जातीय समूह इन्हीं क्षेत्रों में सक्रिय थे जो अपनी संवैधानिक स्वायत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन समूहों का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य पहले शान और कचिन राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना और उसके बाद म्यांमार के केंद्रीय मैदानी हिस्सों आक्रमण करना था।

बर्मी कम्युनिस्ट पार्टी (BCP) दूसरे लोकतंत्र समर्थक और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के साथ, जुंटा के खिलाफ प्रतिरोध के अग्रणी मोर्चे पर था। देश के एक तबके में असंतोष स्पष्ट रूप से अपनी जगह बना चुका था, ऐसे में 15 मार्च 1975 को BCP के अध्यक्ष ठाकिन ज़िन की सेना ने हत्या कर दी।[134] ठाकिन ज़िन की हत्या इस जारी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने यह दिखाया कि सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सेना किस हद तक जा सकती

है। इस घटना ने लोकतांत्रिक सुधारों और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वायत्तता की लड़ाई में BCP और अन्य विरोधी समूहों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को भी उजागर किया।

1970 दशक के दौरान म्यांमार के केंद्रीय भूभाग से तात्मादॉ ने कम्युनिस्ट विद्रोह को कुचल दिया, जिसमें 172 विद्रोहियों और 135 सरकारी सैनिकों की मौत हो गई।[135] यह हिंसक टकराव सैन्य शासन द्वारा किसी भी प्रतिरोध को दबाने के लिए अपनाए गए रास्तों की पड़ताल करता है, विशेष रूप से बर्मी कम्युनिस्ट पार्टी (BCP) से, जो सरकार को उखाड़ फेंककर एक वैकल्पिक शासन स्थापित करना चाहती थी। संघर्ष जारी रहा, और 22-28 मार्च 1976 के बीच पूर्वी म्यांमार में सरकार के सैनिकों और कम्युनिस्ट विद्रोहियों के बीच एक और टकराव हुआ, जिसमें 96 विद्रोही और 35 सैनिक मारे गए।[136] लगातार चलने वाले इन प्रतिरोधों के दमन के बाद भी वैकल्पिक राजनीतिक विचारों की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रहा। इसके अलावा, जुलाई 1976 को, सैन्य सरकार के सामने सेना के अंदर भी विद्रोह की स्थिति पैदा हुई, जिसे जुंटा ने कुचल दिया।[137] इस घटना से यह भी सामने आया की सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर भी आंतरिक विभाजन की स्थिति मौजूद थी। ये घटनाएँ म्यांमार के सैन्य शासन और विभिन्न विपक्षी समूहों, जैसे कम्युनिस्ट, जातीय सशस्त्र समूहों और लोकतंत्र समर्थक ताकतों के बीच व्यापक राजनीतिक संघर्ष को दर्शाती हैं। इसे इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि फरवरी 2021 सैन्य तख्तापलट के बाद जो गृहयुद्ध शुरु हुआ, वहां भी हमें सेना में विभाजन की कई स्थितियों देखने को मिलती हैं।

CPB जैसे बलों ने जातीय सेनाओं के साथ गठजोड़ किया और 1970 के दशक के अंत तक यह पूर्वोत्तर इलाकों में विद्रोही समूहों के गठबंधन में सबसे मजबूत बल बन गया, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 30,000 लड़ाके शामिल थे। इसके बावजूद, इन समूहों की आपसी संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की कमी ने उनकी संख्यात्मक बढ़त का पूरा लाभ उठाने में बाधा डाली। इसी अवधि में सेना के साथ हुई लड़ाइयों में इस गठबंधन के लड़ाके भारी संख्या में हताहत हुए। 1980 के दशक की शुरुआत तक, जातीय समूहों ने चीन की सीमा के पास अवैध कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रित में कर लिया

था, जहाँ पांगसाई और मोंगला जैसे बाजार आर्थिक केंद्र बन गए थे। इसके अलावा, CPB, कचिन स्वतंत्रता संगठन (KIO) के साथ मिलकर खदानों से जेड को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने के काम में भी शामिल थे।[138] लेकिन जल्दी ही तात्मादॉ के लगातार हमलों ने CPB की व्यापारिक और सशस्त्र संघर्ष की क्षमताओं पर असर डालना शुरु कर दिया था।[139] 1980 के दशक के शुरुआती पांच सालों में ही CPB उसका प्रभाव कम होता गया, लेकिन जातीय अल्पसंख्यक ने किसी तरह अपनी गतिविधियां जारी रखी थी।

म्यांमार में राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतंत्र के लिए संघर्ष के नज़रिए से देखें तो 1980 का दशक सरकार की रणनीतियों में "गाजर" (प्रोत्साहन) और "छड़ी" (दमन) दोनों ही नीतियों का उपयोग दिखता है। इस नीति का सीधा उद्देश्य विपक्ष को नियंत्रित करना और यथास्थितिवाद को बढ़ावा देना था। बहुसंख्यक वर्चस्व इस यथास्थितिवाद का एक प्रमुख हिस्सा था, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मई 1980 में आयोजित "बुद्ध धर्म के शुद्धिकरण, स्थायित्व और प्रचार के पहले सम्मेलन" में बौद्ध भिक्षुओं ने एक नया धार्मिक संविधान तैयार किया।[140] इस संविधान में भिक्षु समुदाय (संघ) पर केंद्रीय शासन तंत्र को थोपने को बढ़ावा दिया गया, जिसके मूल में था धार्मिक मंत्रालय द्वारा भिक्षुओं पर निगरानी में रखना। इस पहल को सार्वजनिक समर्थन भी मिलता दिखा। हालांकि, धार्मिक आदेश पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहले के प्रयासों का विरोध हुआ था, विशेष रूप से 1965 में जब पहले के प्रयासों को पहचान पत्र लागू करने में विफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि धर्मगुरुओं के पक्ष में जनता का समर्थन था। सरकारी सेनाओं ने वैसे तो विद्रोहियों के खिलाफ कभी बंद नहीं किया था लेकिन 1980 के दशक में इसमें तेज़ी आई, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें तात्मदॉ को मिली जुली सफलता ही मिली। "मिन यान आउंग" के नाम से जानी जाने वाली सैन्य आक्रमण सेना ने BCP विद्रोहियों के खिलाफ नवंबर 1979 में शुरु किया। जिसमें दोनों पक्षों को काफी नुकसान झेलना पड़ा।[141] सैन्य मोर्चे पर सरकार के विद्रोही समूहों को दबाने की कोशिशों को झटका भी लगा और कई इलाकों में विद्रोहियों ने अपनी पकड़ मज़बूत की।[142] म्यांमार की सेना ने 1979 में शान राज्य में कम्युनिस्ट विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन 'किंग कॉन्करर' शुरू किया, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से भारी जनहानि के बावजूद,

सेना विद्रोहियों को हराने में सफल नहीं हो पाई।[143] बड़ी घटनाओं की बात करें तो अप्रैल 1983 में पांगलोंग (शान राज्य) के पास मिन यान आंग-II नामक सैन्य अभियान के दौरान BCP के विद्रोहियों और सरकारी सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई। इस झड़प में 83 विद्रोहियों और 27 सरकारी सैनिकों की मौत हुई।[144] पांगलोंग में हुई यह हिंसक झड़प के कई बड़े मायने रहे, क्योंकि पांगलोंग का ऐतिहासिक महत्व भी था। 1947 के पांगलोंग समझौते में जातीय नेताओं और आंग सान के बीच संघीय ढांचे की सहमति हुई थी, जिसे बाद में सैन्य सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया।[145] यह ऐतिहासिक विश्वासघात जातीय असंतोष और सशस्त्र संघर्ष का आधार 21वीं सदी में भी बना रहा। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, नवंबर 1986 को शान राज्य के ह्सी-ह्सीवान पर्वतीय क्षेत्र में BCP विद्रोहियों और सेना के बीच एक बड़ा वार-पलटवार देखने को मिला।[146] इसके बाद, जनवरी 1987 में भी सरकार ने विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और BCP के कई महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ताओं को पकड़ा गया, जिससे BCP की संचालन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुए। इन झड़पों में 591 विद्रोही और 175 सरकारी सैनिक मारे गए।[147] इस सैन्य अभियान ने न केवल विद्रोहियों को कमजोर किया, बल्कि नागरिकों पर भी भारी असर डाला। लगभग 6,000 नागरिक, संघर्ष और हिंसा से बचने के लिए, चीन की सीमा की ओर शरण लेने को मजबूर हुए।

जुंटा की कठोर नीतियाँ और सैन्य अभियान विद्रोहियों को समाप्त करने में असफल रहे, बल्कि इसके विपरीत, उन्होंने ग्रामीण आबादी और जातीय अल्पसंख्यकों के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप विद्रोही गुटों को स्थानीय समर्थन और अधिक बल मिला। इसी तरह, बर्मा-थाई सीमा पर करेन विद्रोहियों के खिलाफ अभियानों में भी सेना को नाकामी का सामना करना पड़ा, और करेन सेनाओं ने अपने क्षेत्रों की प्रभावी रूप से रक्षा की। सरकार के विद्रोहियों को दबाने और सीमा क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के संघर्षों ने यह सिद्ध कर दिया कि इसकी दमनात्मक उपायों की सफलता सीमित ही थी।

इसी दौरान, 1978 के "ऑपरेशन नागा मिन" के तहत सेना ने रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे 2,000,00 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश

भागने को मजबूर हुए।[148] यह घटना जातीय और धार्मिक तनाव को और गहरा कर गई।[149] दूसरी ओर, BSPP की समाजवादी आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक ठहराव, व्यापक गरीबी और अवैध कारोबार (काला-बाजार) का विकास हुआ, जिसने जनता को और अधिक अलग-थलग कर दिया। 1980 के दशक में किए गए सीमित आर्थिक सुधार इन चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहे, और संयुक्त राष्ट्र ने बर्मा को 'सबसे अविकसित देश' (LDC) के रूप में वर्गीकृत किया।[150] जनता में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था, जिसमें छात्र और बुद्धिजीवी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। 1987 में सरकार द्वारा अचानक नोटबंदी के फैसले ने स्थिति और बिगाड़ दी, जिससे लोगों की बचत खत्म हो गई और आर्थिक संकट गहरा गया।[151] इस दौर ने म्यांमार में चल रहे जातीय संघर्षों और सरकार की "सैन्य-प्रथम"[152] नीति की सीमाओं को उजागर किया, जिसने न तो विद्रोहियों के खिलाफ स्थायी शांति सुनिश्चित की और न ही उन जमीनी समस्याओं को सुलझाया, जिनके चलते यह संघर्ष पैदा हुआ।

आठ-आठ-अट्ठासी क्रांति और लोकतंत्र की आकांक्षाएं

1980 के दशक के आखिरी साल आते आते यह स्पष्ट हो चुका था कि देश में एक-दलीय व्यवस्था ने लगातार राजनीतिक विरोधों और असहमतियों को दबाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी सीधा हुआ, मसलन आर्थिक उत्पादन और व्यापार के क्षेत्रों में गिरावट आती गई और म्यांमार का वैश्विक बाजार से संपर्क लगभग टूट गया। इसने देश में गंभीर आर्थिक मंदी का कारण बना, और इस मंदी ने म्यांमार के नागरिकों के जीवन को काफी मुश्किल बना दिया।[153] हालांकि शासन ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सामाजिक सुधारों की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी सरकारी तंत्र की व्यवस्थागत अक्षमताओं के कारण ज़मीन पर पूरी तरह उतर नहीं पाए।[154] सेना (तत्मादॉव) ने शासन में प्रभुत्व स्थापित करने की ओर बढ़ चुकी थी, और ने-विन (जो 1988 की क्रांति के पहले तक BSPP के अध्यक्ष थे) और उनके जनरलों ने समाज में कड़े नियंत्रण को थामे रखने की नीति को आगे बढ़ाया।[155]

दमनकारी नीतियों का असर केवल आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरे रूप से हुआ। सैन्य शासन ने नागरिक अधिकारों की अनदेखी की, और लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता को कुचला। विरोध की आवाजों को दबाने के लिए सत्ता ने हिंसा का सहारा लिया, और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने वाले आंदोलनों को निर्ममता से कुचला। तात्मादॉ और उनके समर्थित सरकार और राजनीतिक दल यह शासन, जो 'सामाजिक न्याय' और 'समानता' की बात करता था, असल में एक निरंकुश तानाशाही के रूप में तब्दील होता गया, जिसने म्यांमार के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को न केवल बिगाड़ दिया बल्कि उसे एक गहरी राजनीतिक अस्थिरता की ओर भी धकेल दिया।[156]

1980 के दशक में, म्यांमार की स्थिति और भी खराब हो गई। सरकार के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ने लगा, और इसके कारण एक बड़ा नागरिक विरोध आकार लेने लगा। 1987 में सरकार ने अचानक 25, 35 और 75 चैट (Kyat) के नोटों को अमान्य कर दिया, जिससे लाखों नागरिकों की पूरी बचत एक पल में खत्म हो गई।[157] इस फैसले ने म्यांमार के समाज में पहले से चले आ रहे आर्थिक संकट को असहनशीलता की हद तक पहुंचा दिया, जिसने जल्दी ही गहरे आक्रोश का रूप ले लिया। नतीजा विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरु हो गई। शुरुआत में ये प्रदर्शन केवल छात्रों तक सीमित थे, लेकिन बहुत जल्दी ही ये पूरे देश में फैल गए और एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसके साथ ही, श्रमिकों, भिक्षुओं और अन्य नागरिकों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया, जिससे यह विरोध और भी संगठित और विशाल रूप में सामने आया।[158] प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से देश में लोकतंत्र की वापसी और राजनीतिक बदलाव की ज़रूरत की मांग कर रहे थे। इन देश व्यापी प्रदर्शनों में लोगों के बीच एक नया उत्साह था जिसके केंद्र में राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष था। सैन्य शासन ने इस विरोध का कड़ा प्रतिकार किया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसात्मक दमन की राह अपनाई। प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए सेना और पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। इस दौरान सैकड़ों लोगों की जान गई, और कई लोग लापता हो गए।[159] लेकिन जुलाई 1988 में वह समय भी आया जब जनरल ने-विन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की।[160] 27 जुलाई, 1988 को जनरल 'सिन ल्विन' को बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (BSPP) के अध्यक्ष और देश के राष्ट्रपति दोनों के रूप में नियुक्त किया गया।[161] लेकिन इस बदलाव के बावजूद बर्मा में कोई वास्तविक और बुनियादी राजनीतिक सुधार नहीं हुआ। जनरल विन के उत्तराधिकारी जनरल 'सिन ल्विन' की सरकार भी इस प्रदर्शन को शांत करने में असफल रही, और हिंसात्मक दमन के सिलसिले ने और ज़ोर पकड़ लिया। नए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लागू किया। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने और निजी व्यवसाय के लिए अवसर खोलने का वादा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान 8 अगस्त 1988 को एक राजधानी रंगून में एक छात्रों के एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन हुए, जिस पर सेना ने बर्बर हिंसात्मक कार्यवाई की। इस कार्यवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए और सैंकड़ों घायल हुए।[162] दमन की इस कार्रवाई

के लिए ही तत्कालीन राष्ट्रपति सीन ल्विन को "रंगून के कसाई" तक कहा गया। लेकिन जल्दी ही यानी राष्ट्रपति सिर्फ 17 दिनों की सेवा के बाद 12 अगस्त, 1988 को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा।[163]

इसी उथल-पुथल के बीच, 18 सितंबर 1988 को एक और सैन्य तख्तापलट हुआ। जिसके बाद, जनरल 'सॉ माउंग' ने सत्ता पर कब्जा किया और देश में व्यवस्था बहाली के लिए 'राज्य कानून और व्यवस्था बहाली परिषद' (SLORC) का गठन किया।[164] नए सैन्य शासन ने वादा किया कि वह चुनाव कराएगा और देश में लोकतंत्र बहाल करेगा। इन परिस्थितियों में SLORC के पास एक बेहतरीन अवसर था देश में लोकतंत्र की स्थापना का, लेकिन उसकी गतिविधियों ने लोकतंत्र समर्थन समूहों को निशाना बनाना शुरु कर दिया। इसी में एक प्रमुख दल था 'नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी' (National League for Democracy - NLD)। SLORC ने NLD की प्रमुख नेता 'आंग सांग सू ची' और उनके समर्थकों को दमन का शिकार बनाया।[165]

'आंग सांग सू ची का उभार'

1988 के आंदोलन से कई लोकतंत्र समर्थक आवाज़ें निकली, जिसमें से 'आंग सांग सू ची' आंदोलन की पहचान और चेहरा बनकर उभरीं। यह एक संयोग ही था कि आंदोलन के वक्त विदेश में रहने वाली 'सू ची'अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए बर्मा/म्यांमार में थीं। उन्होंने 'आंग गेई' और 'टिन ऊ' जैसे पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया।[166]

'आंग सांग सू ची' का भी अपना एक विशेष इतिहास रहा है। वह म्यांमार के स्वतंत्रता सेनानी जनरल 'आंग सांग' की बेटी हैं, जो बर्मा की आज़ादी के नायक और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे।[167] उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और थाकिन आंदोलन से लेकर बर्मीज़ इंडिपेंडेंस आर्मी (BIA) का गठन किया। हालांकि, 1948 में बर्मा को ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले, जब वह सिर्फ दो साल की थीं, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी।[168] आंग सांग आज भी म्यांमार के 'राष्ट्रपिता' के रूप में सम्मानित हैं। 1960 में, सू ची अपनी मां 'दॉ खिन ची' के साथ भारत

आईं, जिन्हें म्यांमार का दिल्ली में राजदूत नियुक्त किया गया था। चार साल बाद, वह यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गईं, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। वहीं उनकी मुलाकात अपने होने वाले पति माइकल एरिस से हुई, जो एक प्रोफेसर थे। जापान और भूटान में रहने और काम करने के बाद, वह यूके में बस गईं और अपने दो बच्चों, अलेक्जेंडर और किम, की परवरिश करने लगीं। 1988 में, जब उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं, तब वह यांगून लौटीं। 26 अगस्त 1988 को यांगून में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा, "मैं अपने पिता की बेटी के नाते जो कुछ हो रहा था, उससे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती थी।"[169] उन्होंने अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर और भारत के महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलनों से प्रेरणा ली।[170] उन्होंने रैलियां आयोजित कीं और पूरे देश का दौरा करते हुए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सुधार और स्वतंत्र चुनावों की मांग की। इसी दौरान, 20 जुलाई 1989 को, NLD की तत्कालीन महासचिव आंग सान सू ची को स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रंगून में भी अपने पुश्तैनी घर पर नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि आने वाले सालों में कई बार उन्हें नज़रबंदी का सामना करना पड़ा।[171] 1989 की नज़रबंदी 10 जुलाई 1995 तक लगभग 6 वर्षों तक चली। इसके बावजूद, 1990 के चुनावों में उनकी पार्टी ने भारी जीत दर्ज की, जिसे सैन्य शासन ने मान्यता नहीं दी। 1991 में ही सू ची को नज़रबंदी के दौरान ही नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें "निर्बलों की शक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण" के रूप में सराहा।[172]

1990 में हुए चुनावों में NLD ने भारी जीत हासिल की, लेकिन सैन्य शासन ने चुनावी परिणामों को ठुकरा दिया और अपनी सत्ता बनाए रखी। यह स्थिति म्यांमार में लोकतांत्रिक आंदोलन की गंभीरता को उजागर करती है। 1988 का जन आंदोलन न केवल म्यांमार के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना, बल्कि इसने देश में लोकतांत्रिक बदलाव की आवश्यकता की गहरी समझ को भी बढ़ाया। इस आंदोलन ने म्यांमार के नागरिकों में अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति एक नया उत्साह पैदा किया, जो लोकतंत्र की वापसी के लिए उनका संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित करता रहा।[173]

1990 का चुनाव और जुंटा की वादाखिलाफी

27 मई, 1990 को म्यांमार में दशकों के बाद पहली बार बहुदलीय आम चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव में 93 राजनीतिक दलों और 87 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 492 संसदीय सीटों में से 485 सीटों पर चुनाव लड़ा। इन चुनावों में लोगों की काफी संख्या में भागीदारी देखने को मिली और मतदान प्रतिशत 72.59% रहा। NLD को 59.87% मतों के साथ कुल 392 सीटें मिलीं, जो कुल सीटों का करीब 81% था। यह एक जबरदस्त जीत थी और इस परिणाम ने जनता में लोकतांत्रिक परिवर्तन की इच्छा को भी सामने रखा। चुनाव परिणाम सत्तारूढ़ सैन्य शासन के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया।[174]

टेबल 2

1990: चुनाव परिणाम[175]	
राजनीतिक दल	**सीटें**
नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD)	392
नेशनल यूनिटी पार्टी (BSPP का नया अवतार)	10
शान नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी	23
यूनियन नेशनल डेमोक्रेसी पार्टी (आंग गी)	01
राखाइन डेमोक्रेसी लीग	11
अन्य दल (21 अलग-अलग समूह)	34
निर्दलीय	06

SLORC के लिए इन चुनाव परिणाम का मतलब यह नहीं था कि वह लोकतांत्रिक शक्तियों को तुरंत सत्ता का हस्तांतरण कर दे। बल्कि SLORC ने इसे एक दीर्घकालिक और नियंत्रित संक्रमण प्रक्रिया का हिस्सा मानना बेहतर समझा। NLD ने अपनी जीत को सत्ता संभालने के स्पष्ट संकेत के रूप में देखा, लेकिन SLORC ने जोर देकर कहा कि यह चुनाव केवल नए संविधान का मसौदा तैयार करने और एक स्थायी राजनीतिक ढांचे की स्थापना की व्यापक प्रक्रिया का एक चरण थे। सैन्य शासन ने सत्ता हस्तांतरण में देरी को

यह कहकर उचित ठहराया कि न तो 1947 का संविधान (सैन्य शासन से पहले का) और न ही 1974 का संविधान (समाजवादी युग का) देश के भविष्य के शासन के लिए पूरी तरह सही नहीं है। इसके बजाय, SLORC ने जोर दिया कि सत्ता हस्तांतरित करने से पहले एक नया संविधान तैयार किया जाना चाहिए।[176] जानकार बताते हैं कि यह रुख सेना की व्यापक रणनीति के अनुरूप था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक संरचनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना और अपनी संस्थागत और व्यक्तिगत हितों की रक्षा करना था।[177] सेना के इस रुख के बाद NLD और SLORC के बीच तनाव बढ़ गया क्योंकि NLD ने म्यांमार की संसद के 'प्रतिनिधि सभा' (Pyithu Hluttaw) का सत्र को तुरंत बुलाने और एक अंतरिम संविधान के आधार पर सत्ता हस्तांतरण करने पर जोर दिया। वहीं, सैन्य शासन (जुंटा) ने 27 जुलाई, 1990 को अधिसूचना जारी करके कहा कि जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों पर SLORC का नियंत्रण बना रहेगा।[178] इस अधिसूचना ने प्रभावी रूप से NLD के सत्ता के दावे को नकार कर दिया। इसका यह मतलब भी था कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक संघर्ष अभी जारी रहेगी। एक बार फिर से जुंटा ने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दमन की व्यापक कार्रवाई शुरु कर दी। कई NLD प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कईयों ने देश से बाहर भागकर निर्वासन में एक समानांतर सरकार, नेशनल कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा (NCGUB), की स्थापना की।[179]

वर्ष 1992 में SLORC में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, और वरिष्ठ जनरल 'थान श्वे' ने नियंत्रण संभाला। उनके नेतृत्व में सैन्य शासन ने राजनीतिक संरचना में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। SLORC ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में चाहे कैसी भी राजनीतिक प्रणाली देश में स्थापित हो, उसमें देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा करने के साथ-साथ शासन में तात्मादॉ (म्यांमार सेना) की न सिर्फ भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए बल्कि उसे एक संस्थागत रूप भी दिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, SLORC ने 1993 में नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाई। यह सम्मेलन का ताना बाना इस तरह से बुना गया था कि कि सैन्य शासन के मुख्य हित संरक्षित रहे। सम्मेलन की कई

स्तरों पर आलोचना के बाद, आखिरकार 9 जनवरी 1993 को इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कुल 702 प्रतिनिधियों में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, हालांकि 1990 के चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली पार्टी NLD के सिर्फ 10 प्रतिनिधियों सहित राजनीतिक समूहों के कुल 91 प्रतिनिधियों को ही शामिल किया गया यानी सम्मेलन के कुल प्रतिनिधियों का केवल 14.4% हिस्सा। सम्मेलन में जुंटा ने इस लक्ष्य को आगे बढ़ाया जो इस बात को सुनिश्चित करे कि संसद में 25% प्रतिनिधि खुद सैन्य नेतृत्व द्वारा चुने जाएं। सम्मेलन के उद्देश्यों में देश की एकता की रक्षा, राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के साथ साथ, राजनीति में तात्मादॉ की नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित करना, और 'अनुशासित लोकतंत्र' की शासन प्रणाली विकसित करना शामिल भी था। यह सम्मेलन लगभग तीन वर्षों तक चला और 30 मार्च 1996 को तब जाकर समाप्त हुआ, जब भारी हताशा के कारण NLD ने अपनी भागीदारी वापस ले ली और सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया।[180] NLD के राष्ट्रीय सम्मेलन से बाहर निकलने से संवैधानिक मसौदा प्रक्रिया एक लंबे समय तक राजनीतिक गतिरोध में फंसा रहा। हालांकि, सम्मेलन में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 104 बुनियादी सिद्धांतों को रूपरेखा के रूप में तय कर लिया गया। इन्हीं परिस्थितियों में SLORC को वर्ष 1997 में फिर से नया रूप देने की कोशिश की गई, जिसका नया नामकरण स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल (SPDC) रखा गया।

भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थकों के प्रदर्शनों का दमन कर दिया गया हो और चुनाव परिणामों को लागू करने से मना कर दिया गया हो, लेकिन राजनीतिक सुधारों के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया। SPDC ने 2003 में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने का वादा करते हुए 'सात चरणों के एक रोडमैप' की घोषणा की। इस रोडमैप में राष्ट्रीय सम्मेलन को फिर से बुलाने से लेकर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना तक का एक सिलसिलेवार योजना शामिल थी। हालांकि, आलोचकों ने इस रोडमैप की व्यापक आलोचना की क्योंकि इस योजना में सबकी भागीदारी और पारदर्शिता जैसे बुनियादी तत्वों की भारी कमी थी।[181] कई समीक्षकों ने इसे वास्तविक लोकतंत्रीकरण की बजाय सैन्य वर्चस्व को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा।

राजनीतिक संचरना और नया संविधान

यह समय 20वीं सदी के अंत से लेकर 21वीं सदी के शुरुआत तक था, जब म्यांमार की सेना भले ही अपने वर्चस्व को कायम रखने की चुनौतियों से जुझ रही थी। लेकिन इसके साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय जगत और अपने समर्थक देशों को भी यह संदेश देना चाहती थी कि वह एक नई राजनीतिक संरचना को लेकर गंभीर है जो पहले से ज्यादा लोकतांत्रिक दिखे।[182]

जुंटा इस पर मंथन कर रही थी कि एक राष्ट्रपति प्रणाली वाली ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें ऐसी विधायी संरचना हो जहां शासन व्यवस्था में सेना लगातार निर्णायक भूमिका में रहे। इंडोनेशिया के मॉडल से प्रेरित राष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना का विचार स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल (SLORC) द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किया गया था।[183] यह प्रणाली कार्यपालिका शाखा को मजबूत करने और विधायिका से शक्तियों को अलग रखने पर बल देती है। कार्यपालिका के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति को कठोर पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

20वीं सदी के आखरी दशक में जब SLORC ने राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रक्रिया शुरू की, जुंटा ने म्यांमार में एक राष्ट्रपति शासन स्थापित करने के विचार को बढ़ावा दिया।[184] सरकारी मीडिया के ज़रिए इंडोनेशियाई राजनीतिक प्रणाली की ख़ूबियों को बार-बार जनता के सामने पेश किया गया। जब जुंटा ने म्यांमार के संविधान की बुनियादी रूपरेखा तय की तो एक ऐसे सशक्त कार्यपालिका की परिकल्पना की गई, जहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा शामिल हो।[185] कार्यपालिका में राष्ट्रपति को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया। राष्ट्रपति पद की योग्ताओं में तमाम बातों के अलावा इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विदेशी में किसी विषय या नागरिक के अधिकार और विशेषाधिकार के पात्र नहीं होना चाहिए। यहां इस बात को कुछ समीक्षकों ने रेखांकित किया कि इन राजनीतिक पात्रताओं की सूची में यह नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति के पास सैन्य अनुभव या सैन्य सेवा होना अनिवार्य है। न ही यह उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति को तात्मादॉ (म्यांमार सेना) का सक्रिय सदस्य होना चाहिए।[186]

SLORC द्वारा आकार दी गई इस राजनीतिक संरचना में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया सीधे जनता के वोट से नहीं होती, बल्कि यह संसद (विधान मंडल) के चुनाव से जुड़ी होती है। म्यांमार की संसद, जिसे Pyidaungsu Hluttaw (संघ संसद) कहा जाता है, दो सदनों से बनी होती है, जिसमें निचला सदन यानी 'प्रतिनिधि सभा' (Pyithu Hluttaw) और ऊपरी सदन यानी 'राष्ट्रवादियों की सभा' (Amyotha Hluttaw) में कुल 440 सीटें होती हैं, जिनमें से 330 सीटें जनसंख्या के आधार पर चुनी जाती हैं, जबकि 110 सीटों पर सेना प्रमुख (कमांडर-इन-चीफ) सांसदों का नामांकन करते हैं। वहीं, ऊपरी सदन में कुल 224 सीटें होती हैं, जिनमें से 168 सीटें हर राज्य और क्षेत्र से समान संख्या में चुनी जाती हैं, और 56 सीटें पर सेना प्रमुख सदस्यों का नामांकन करता है।[187] म्यांमार 14 राज्यों और क्षेत्रों में बंटा हुआ है और हर राज्य से 12 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि सेना प्रमुख की सूची से हर राज्य से 4 प्रतिनिधि नामांकित होते हैं। इस प्रकार, संसद में कुल 664 सीटें होती हैं, जिनमें से 498 सीटें चुनाव से तय होती हैं (330 निचले सदन के लिए और 168 ऊपरी सदन के लिए), जबकि 166 सीटें सेना प्रमुख की नामांकन सूची से आती हैं।[188]

राष्ट्रपति का चुनाव एक राष्ट्रपति चुनावी कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें तीन समूह शामिल होते हैं: निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, ऊपरी सदन के निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के सैन्य प्रतिनिधि। प्रत्येक समूह एक उप-राष्ट्रपति उम्मीदवार को नामित करता है, और यूनियन संसद के सभी 664 सदस्य वोट देकर इनमें से एक को राष्ट्रपति चुनते हैं, जबकि शेष दो उप-राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार को कुल मतों का 50% से अधिक (332 या अधिक) प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि कोई राजनीतिक दल या गठबंधन दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त करता है, तो वह दो उप-राष्ट्रपति उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है, जिनमें से एक निश्चित रूप से राष्ट्रपति बनेगा। इस स्थिति में, सैन्य द्वारा नामित उप-राष्ट्रपति केवल उप-राष्ट्रपति पद तक सीमित रह जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि सेना का कमांडर-इन-चीफ (C-in-C) विधायिका में 25% सीटों के लिए नामांकन करता था। साथ ही रक्षा, गृह मामलों और सीमा मामलों जैसे प्रमुख मंत्रालयों में नेतृत्व को नियुक्त करता था, और पुलिस और अर्धसैनिक बलों

सहित सभी सशस्त्र बलों पर नियंत्रण रखता था।[189] C-in-C नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल (NDSC) में भी बहुमत की स्थिति कायम रखते हैं, क्योंकि काउंसिल के 11 सदस्यों में से छह सेना से जुड़े होते थे। प्रमुख तथ्य यह भी है कि वैसे तो राष्ट्रपति औपचारिक रूप से C-in-C को नियुक्त करता है, लेकिन यह निर्णय NDSC द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता था।

नई सहस्राब्दी: लोकतंत्र की ओर दो कदम आगे, एक कदम पीछे

2000 के दशक की शुरुआत से ही म्यांमार का राजनीतिक परिदृश्य लगातार उथल-पुथल का गवाह रहा है। नई सहस्राब्दी की इस आगाज़ में देश के अंदर संघीय संवैधानिक व्यवस्था के स्वरूप पर विचार-विमर्श, लोकतंत्र के लिए संघर्ष, जातीय समूहों की तरफ से केंद्रीय सैन्य सत्ता को चुनौती, दमन और हिंसा के तत्व भी शामिल थे। सैन्य शासन के खिलाफ विरोध और संघर्षों का सिलसिला कई प्रमुख घटनाओं से गूंज रहा था। इनमें से एक महत्वपूर्ण घटना 30 मई, 2003 को डेपायिन (सगाईन क्षेत्र) में हुई, एक हिंसक झड़प में 50 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता मारे गए।[190] इसके तुरंत बाद 31 मई, 2003 को आंग सान सू की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) की नेता को गिरफ्तार किया गया और सितंबर 2003 तक के लिए उन्हें फिर से नजरबंद कर दिया गया।[191] इस दमनकारी नीति की वजह से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव के लिए संघर्ष और अधिक कठिन होता गया। 20 अक्टूबर, 2004 को प्रधानमंत्री खिन न्याट (Khin Nyunt) की जगह लेफ्टिनेंट जनरल सो-विन (Soe Win) को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।[192] यह बदलाव सैन्य अभिजात वर्ग द्वारा सत्ता के खुद तक सीमित रखना और म्यांमार की राजनीतिक प्रक्रियाओं में नागरिक या लोकतांत्रिक प्रभाव को किनारे करने की रणनीति प्रमुख भूमिका निभा रही थी। इस समय तक, म्यांमार की सैन्य सरकार ने लोकतांत्रिक आंदोलनों और नागरिक संस्थाओं के खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिससे यह संदेश मुखरता से निकल कर आ रहा था कि सैन्य शासन के नेतृत्व में कोई वास्तविक राजनीतिक बदलाव बेहद मुश्किल है। जुंटा की हिंसक कार्यवाईयां केवल घरेलू दमन तक सीमित नहीं थीं; म्यांमार की कार्रवाइयों ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों और संस्थाओं का ध्यान खींचा।

विहंगम नज़रिए से देखें तो इस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि देश में राजनीतिक प्रणाली से संरचनात्मक बदलाव को लेकर जारी संघर्ष मोटे रूप से दो हिस्सों में बंटा था, एक तरफ लोकतंत्र को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का संघर्ष और दूसरी ओर जातीय समूहों को अपनी पहचान को संवैधानिक और कार्यकारी वैधता दिलाने की मांग। इन संघर्षों ने उस समय के सत्ता प्रतिष्ठानों को कुछ कदम उठाने के लिए बाध्य किया। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए 7 चरणों वाले एक रोडमैप को सामने लाया गया। जिसे जनरल खिन न्यून्ट ने 30 अगस्त 2003 को घोषित किया। स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल (SPDC) द्वारा समर्थित एक रणनीतिक योजना थी,[193] जो देश को "अनुशासित लोकतंत्र" की ओर ले जाने के लिए तैयार की गई थी।[194]

टेबल 3

7-चरणों वाला रोडमैप 2003[195]	
राष्ट्रीय सम्मेलन को फिर से बुलाना	1996 से निलंबित राष्ट्रीय सम्मेलन को एक नया संविधान तैयार करने के लिए फिर से बुलाया गया।
लोकतांत्रिक प्रणाली का कार्यान्वयन	राष्ट्रीय सम्मेलन की सफल समाप्ति के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यों का चरणबद्ध कार्यान्वयन
संविधान का मसौदा तैयार करना	राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर एक मसौदा संविधान तैयार किया गया
राष्ट्रीय जनमत संग्रह	मसौदा संविधान को मंजूरी देने के लिए एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित किया गया।

आम चुनाव	संसद (ह्लुत्ताव) के गठन के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए गए।
संसदीय प्रक्रिया (ह्लुत्ताव) प्रणाली का क्रियान्वयन	निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसद के गठन के लिए बैठकों का आयोजन
सरकार का गठन	संसदीय प्रक्रिया के ज़रिए सरकार और प्राधिकृत निकाय और एक नए लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना

यह रोडमैप एक चरणबद्ध प्रक्रिया की ओर इशारा करता है, जिसका उद्देश्य एक अर्ध-लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना करना था, लेकिन साथ में यह सुनिश्चित करना भी कि सेना राजनीतिक प्रक्रिया पर अपना प्रभाव और नियंत्रण बनाए रखे। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इस पूरी प्रक्रिया से नागरिक समाज या तो दूर था या फिर राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे तत्वों को बिलकुल ही दूर रखा गया था।[196] विशलेषक यह कहते हैं कि यह रोडमैप म्यांमार में लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक संघर्षों, राजनीतिक अशांति और सुधारों के लिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव के जवाब में पेश किया गया। लेकिन आम लोगों का भरोसा इस प्रक्रिया पर नहीं था, क्योंकि आने वाले वक्त में एक और व्यापक क्रांति की सुगबुगाहट जारी थी।

केसर क्रांति (Saffron Revolution)

1988 की क्रांति को म्यांमार की जनता नई सहस्राब्दी में भी भूल नहीं पाई और उस क्रांति के निशान और पहचान वहां की समाज में आज भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में समाज के दूसरे वर्गों के साथ धार्मिक बौद्धों ने राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के संघर्ष में अपनी एक अनोखी भूमिका निभाई। यह क्रांति की शुरूआत उस समय हुई जब म्यांमार की सैन्य सरकार ने ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी, जिससे परिवहन और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में

कठिनाइयां बढ़ती चली गईं। बौद्ध भिक्षु, जो म्यांमार समाज में उच्च सम्मान रखते हैं, नागरिकों की कठिनाइयों को देखकर शांतिपूर्ण मार्च के माध्यम से सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए।[197] सितंबर 2007 में हजारों भिक्षुओं और नागरिकों ने यांगून और अन्य शहरों में सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक सुधार और सैन्य शासन को समाप्त करने की मांग की। इस आंदोलन को "केसर क्रांति" इसलिए कहा गया क्योंकि यह बौद्ध भिक्षुओं के केसरिया वस्त्रों का प्रतीक बन गया, जो उनकी आस्था और त्याग को दर्शाता है। हालांकि सैन्य सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए हिंसात्मक कार्रवाई की, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस क्रांति ने म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की मांग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता दिलाई।[198] यह आंदोलन बौद्ध धर्म की अहिंसा और म्यांमार के नागरिकों की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया।

बौद्ध धर्म और सैन्य शासकों के बीच संबंध 1962 के तख्तापलट के बाद से बेहद अलग रहे हैं, जिसे 2007 के विरोध प्रदर्शनों ने नए संदर्भों में देखने और समझने को मजबूर किया। 1962 के तख्तापलट के बाद से सैन्य सरकार द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के बावजूद, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और सैन्य सरकार द्वारा राजनीतिक वैधता के लिए धर्म के उपयोग अपने साथ कई विरोधाभास लेकर आया था। 1962 के तख्तापलट के बाद से, सैन्य और इसके बाद की एकपक्षीय नियंत्रित सरकारों ने बौद्ध धर्म को म्यांमार की राष्ट्रीय पहचान के एक स्तंभ के रूप में प्रचारित किया, ताकि सत्ता को मजबूत किया जा सके और उनके शासन को उचित ठहराया जा सके।[199] उन्होंने धार्मिक गतिविधियों को वित्त पोषित किया, पगोडों का निर्माण किया और खुद को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से बौद्ध बहुल जनसंख्या का विश्वास जीतना और धार्मिक राष्ट्रवाद के माध्यम से असंतोष को दबाना था। इसके विपरीत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो करुणा, अहिंसा और न्याय में निहित हैं, सैन्य शासन की निरंकुश और दमनकारी प्रकृति के साथ स्वाभाविक रूप से असंगत थे। सैन्य शासन द्वारा व्यापक मानवाधिकार हनन, भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन ने इन मूल्यों का उल्लंघन किया, जिससे भिक्षुओं को, जो नैतिक और आध्यात्मिक नेता हैं, शासन के खिलाफ कार्य करने के लिए मजबूर

होना पड़ा। इस नैतिक दायित्व को 2007 की केसर क्रांति के दौरान और भी बढ़ावा मिला।[200] ऐतिहासिक रूप से, म्यांमार में भिक्षुओं को नैतिकता और न्याय के संरक्षक के रूप में देखा गया है, जो उपनिवेशीय शासन और उसके बाद के संघर्षों के दौरान सार्वजनिक भावना को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। केसर क्रांति के नेतृत्वकारी भूमिका में आने के बाद बौद्धों ने इस परंपरा को जारी रखा और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करते हुए और सैन्य दमन को समाप्त करने की अपील करते हुए लोगों की नैतिक आवाज के रूप में कार्य किया।

सितंबर 2007 में, बर्मा में 1988 के विद्रोह के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसका आगाज 15 अगस्त को तब हुआ जब शासन ने बिना किसी चेतावनी के ईंधन की कीमतों में 500% तक की वृद्धि कर दी।[201] 19 अगस्त को विरोध की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व '88 जनरेशन स्टूडेंट्स' समूह के प्रमुख नेताओं ने किया। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही पूरे देश में फैल गए, लेकिन शासन ने दमनकारी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कई लोकतंत्र समर्थक नेता भी शामिल थे। भिक्षुओं ने शांतिपूर्ण मार्च और प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते हुए ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ और जनता के अधिकारों की बहाली के लिए आवाज उठाई। 22 सितंबर को लगभग 2,000 भिक्षु और नागरिक सड़कों पर उतर आए और आंग सान सू की के घर के बाहर जमा हुए।[202] यह दृश्य लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और बौद्ध भिक्षुओं के बीच एकता का प्रतीक बन गया। 24 सितंबर तक रंगून में 1 लाख से अधिक लोग सड़कों पर थे, और बर्मा के हर राज्य और संभाग में प्रदर्शन हो रहे थे। यह 1988 के विद्रोह के बाद का सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन था।[203] 25 सितंबर को शासन ने कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट सेवाएं को बंद कर दिया, और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग की शुरुआत कर दी गई। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे, और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई गई। बौद्ध मठों पर छापेमारी की गई, भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया, और उन्हें मठों से बाहर जाने से रोक दिया गया। प्रदर्शनों की इस श्रृंख्ला में कई लोग मारे गए, जिनकी संख्या को लेकर भारी मतभेद रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 9 लोग मारे गए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि मृतकों की संख्या 200 से अधिक थी।[204] कुछ

स्रोत 26-29 सितंबर के बीच मारे जाने वाले प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा ही 30 तक बताते हैं।[205] शासन ने 6,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें लगभग 1,400 भिक्षु शामिल थे।[206] यही नहीं अक्टूबर के अंत में, भिक्षु और नागरिक फिर से सड़कों पर उतरे। इस विद्रोह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बर्मा में सैन्य शासन के दमनकारी चरित्र को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र ने बर्मा पर अपना पहला औपचारिक वक्तव्य जारी किया और शासन से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने, नागरिकों के खिलाफ हिंसा बंद करने, और लोकतंत्र समर्थक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत करने का आग्रह किया। यूरोपीय संघ ने बर्मा से लकड़ी, धातु, और रत्नों के आयात पर प्रतिबंध लगाया।[207] यह आंदोलन बर्मा की जनता और लोकतंत्र समर्थकों के लिए आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बना।

सातवां अध्याय

लोकतांत्रिक सुधारों का दबाव बनाम यथास्थितिवाद (2007 - 2015)

2007 के केसर क्रांति (Saffron Revolution) ने म्यांमार के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि सैन्य शासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने आंतरिक और बाहरी सुधारों की मांग को बढ़ावा दिया। इसके जवाब में, वरिष्ठ जनरल थान श्वे (Senior General Than Shwe) के नेतृत्व वाले सैन्य शासन ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सीमित परिवर्तन शुरू किए।[208] इसका एक महत्वपूर्ण कदम 2008 का संविधान था। संविधान का पाठ 4 अप्रैल 2008 को जनता के लिए जारी किया गया, और जनमत संग्रह मूल रूप से 10 मई 2008 को निर्धारित किया गया था।[209] एसपीडीसी (स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल) के अनुसार, 98 प्रतिशत से अधिक पात्र मतदाता संविधान पर जनमत संग्रह के लिए मतदान में शामिल हुए। मतदान केंद्रों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने मतदान में अपेक्षाकृत कम उपस्थिति और कई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की सूचना दी।[210] संविधान के मसौदे को कथित तौर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह में 94% मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसकी वैधता को लेकर कई सारे सवाल उठे। यह संविधान न केवल यह सेना को विधायिका में बड़ी उपस्थिति प्रदान करता है, बल्कि अनुच्छेद 59(f) प्रभावी रूप से NLD प्रमुख आंग सान सू ची को राष्ट्रपति बनने से रोकता है।[211] यह प्रावधान कथित तौर पर राष्ट्रपति पद को "विदेशी प्रभाव से मुक्त"[212] रखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि सू ची के पति विदेशी और बच्चे भी विदेश में रहते हैं। इसके अलावा, संविधान सात जातीय राज्यों—चिन, काचिन, कायाह, कायिन, मॉन, रखाइन, और शान—को सतही रूप से प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने की बात करता है।[213]

संविधान के तहत एक द्विसदनीय विधायिका (bicameral legislature) का प्रावधान किया गया जिसमें सैन्य अधिकारियों के लिए 25% संसदीय सीटें (दोनों सदनों में) आरक्षित कीं।[214] रक्षा, गृह मामलों और सीमा मामलों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर सैन्य नियंत्रण बरकरार रखा गया।[215] इन नए संविधान के बाद म्यांमार आधिकारिक रूप से "द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार" हो गया।[216] इन सुधारों के पीछे के मुख्य कारणों में म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय छवि में सुधार करना और शासन में अपने महत्व को बनाए रखते हुए सेना की भूमिका को नए सिरे से व्यवस्थित और आकार देना शामिल था।[217] 2008 का संविधान, 1974 की तरह ही सैन्य वर्चस्व को संस्थागत रूप तो देता है, लेकिन यह संविधान एक स्तर पर सीमित राजनीतिक बहुलवाद की अनुमति देता है।[218]

संविधान की इस द्विसदनीय विधायिका में प्रतिनिधि-सभा (Pyithu Hluttaw) और राष्ट्रवादियों का सदन (Amyotha Hluttaw) दोनों शामिल। इसका उद्देश्य सामान्य और जातीय निर्वाचन क्षेत्रों दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।[219] संविधान ने विधायिका के दोनों सदनों में 25% सीटें सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि तात्मादॉ विधायी प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखे। राष्ट्रपति, जिसे विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, को राज्य प्रमुख बनाया गया।

संविधान ने जातीय अल्पसंख्यकों के लिए 14 स्वशासी क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान किया, जिससे इन क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई।[220] स्वशासी क्षेत्रों की स्थापना ने कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन कई जातीय समूहों ने महसूस किया कि यह उनके अधिक स्वशासन और समान प्रतिनिधित्व की मांगों को पूरा करने में असफल रहा। शासन के प्रमुख पहलुओं पर सेना का प्रभुत्व जारी रहने से जातीय सशस्त्र समूहों के साथ तनाव और संघर्ष बना रहा। कई समूह जुंटा के इरादों को लेकर संशय में थे और उन्होंने अपने सशस्त्र प्रतिरोध को जारी रखा। नए संवैधानिक ढांचे ने कुछ जातीय समूहों को सरकार के साथ शांति वार्ता में भाग लेने का आधार प्रदान किया।[221] हालांकि, आपसी अविश्वास और सैन्य की सत्ता छोड़ने की अनिच्छा ने इन प्रयासों में बाधा डाली। 2008 के संविधान ने 2010 में म्यांमार के पहले आम

चुनावों के लिए मंच तैयार किया, जिसने अधिक नागरिक-नेतृत्व वाली सरकार की ओर एक धीमी प्रगति की शुरुआत की।

टेबल 4

म्यांमार: 1974 और 2008 के संविधान के बीच प्रमुख अंतर[222]		
विषय	**1974 का संविधान**	**2008 का संविधान**
शासन प्रणाली	बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (BSPP) के तहत समाजवादी एकदलीय प्रणाली।	सीमित राजनीतिक बहुलवाद के प्रावधानों के साथ अर्ध-नागरिक प्रणाली।
सेना की भूमिका	सेना का शासन में कोई स्पष्ट भूमिका नहीं थी और यह BSPP के अधीन था।	सैन्य (तत्मादॉव) के लिए संसदीय सीटों का 25% आरक्षित और प्रमुख मंत्रालयों पर नियंत्रण।
विधायिका	एकसदनीय जनसभा (Pyithu Hluttaw)	द्विसदनीय विधायिका जिसमें प्रतिनिधि सभा (Pyithu Hluttaw) और राष्ट्रवादियों का सदन (Amyotha Hluttaw) दोनों शामिल।
राष्ट्र-प्रमुख	जनसभा द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, जिसके पास औपचारिक शक्तियां थीं।	कार्यकारी शक्तियों वाले राष्ट्रप्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, जिसे दोनों सदनों की संयुक्त सभा (The Pyidaungsu Hluttaw) द्वारा चुना जाता है।
जातीय प्रतिनिधित्व	जातीय स्वायत्तता या अल्पसंख्यक अधिकारों पर न्यूनतम ध्यान।	जातीय अल्पसंख्यकों के लिए सीमित स्वायत्तता के साथ 14 स्व-प्रशासित क्षेत्रों का गठन।

न्यायपालिका	न्यायपालिका विधायिका के नियंत्रण में, जिससे स्वतंत्रता प्रभावित होती थी।	न्यायपालिका को नाममात्र स्वतंत्र घोषित किया गया, लेकिन सैन्य-समर्थित सरकार की निगरानी में।
चुनाव	BSPP द्वारा नियंत्रित एकदलीय चुनाव।	बहुदलीय चुनाव, हालांकि सैन्य का प्रभाव बना रहा।
नागरिक स्वतंत्रता	सीमित नागरिक स्वतंत्रताएँ, राज्य का समाज और अर्थव्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण।	कुछ राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएँ दी गईं, लेकिन सैन्य का महत्वपूर्ण नियंत्रण बरकरार।
शांति और जातीय संघवाद	जातीय सशस्त्र समूहों या संघवाद के साथ कोई औपचारिक वार्ता नहीं।	युद्धविराम और जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) के साथ संवाद के प्रावधान, लेकिन संघवाद की आकांक्षाएँ अधूरी।
संविधान संशोधन	संशोधन के लिए जनसभा की मंजूरी आवश्यक।	संशोधनों के लिए 75% संसदीय अनुमोदन आवश्यक, जिससे सैन्य को प्रभावी रूप से वीटो शक्ति प्राप्त।
स्रोत: "Comparing Three Versions of The Myanmar (Burma) Constitution," ConstitutionNet, at https://constitutionnet.org/comparing-three-versions-myanmar-burma-constitution. (Accessed 22 January 2025)		

म्यांमार की राजनीति में यही वह दौर भी रहा जब जुंटा ने नए सिरे से राष्ट्रीय सुलह की कोशिशें भी शुरु की। SPDC ने कचिन स्वतंत्रता संगठन (KIO) और संयुक्त वा राज्य पार्टी (UWSP) जैसे समूहों के साथ संघर्षविराम समझौते की कोशिशें की लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ सका।[223] ये समझौते मुख्य रूप से सामरिक थे और जातीय संघर्षों के मूल कारणों को हल करने में विफल रहे। लगातार जारी आंतरिक असंतोष और संघर्षों के बीच जातीय समूहों, जैसे कि

करेन नेशनल यूनियन (KNU) और कचिन स्वतंत्रता सेना (KIA) नए सिरे अपने को संगठित कर रहे थे। इनके बीच दोनों पक्षों के बीच स्वायत्तता का दायरा, संसाधन पर नियंत्रण और आत्मनिर्णय के अधिकार क्षेत्रों को लेकर जबरदस्त तनाव था।[224]

सैन्य जुंटा द्वारा तैयार और लागू किया गया 2008 का संविधान ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के प्रावधान सामने रखे, वो अभी भी 1947 के पांगलोंग समझौते से बहुत दूर थे।[225] इस संविधान में 14 स्व-प्रशासित क्षेत्रों और प्रभागों का प्रावधान किया गया था, लेकिन आरोप यह था कि ये प्रावधान नाममात्र की स्वायत्तता प्रदान करते हैं। संविधान ने सत्ता को सेना के तहत केंद्रीकृत कर दिया, 25% संसदीय सीटें तात्मादॉ के लिए आरक्षित कीं और महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर नियंत्रण दिया, जिससे संघीय व्यवस्था की भावना कमजोर हो गई।[226] स्व-प्रशासित क्षेत्रों स्वायत्तता केवल प्रतीकात्मक थी क्योंकि शासन या संसाधनों पर वास्तविक अधिकार नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर केंद्रीकृत नियंत्रण ने जातीय क्षेत्रों को न्यायसंगत आर्थिक लाभों से वंचित कर दिया, जिससे नाराजगी बढ़ी और संसाधन संपन्न क्षेत्रों में भी गरीबी बनी रही। इसी के साथ संविधान की मसौदा प्रक्रिया से जातीय समूहों को बाहर रखना इसे और अधिक अवैध बनाता है। संविधान के प्रावधानों पर ये भी आरोप लगाए गए कि इसके प्रावधान जातीय प्रतिनिधित्व में विभाजन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनके प्रावधान कुछ समूहों को स्व-प्रशासन के तंत्र से ही बाहर रखते हैं।[227] कई जातीय सशस्त्र संगठनों को स्पष्ट लगा कि संविधान के ज़रिए सेना अपने क्षेत्रों में अपने नियंत्रण को और मजबूत करना चाहती है, नतीजतन उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपनी सशस्त्र संघर्ष जारी रखी।

2008 का संविधान लोकतंत्र की ओर संक्रमण का एक भरोसा देता लगता है। इसके प्रावधान तात्मदॉ को अपने वर्चस्व को स्थायी करने का एक मौका भी देता है, क्योंकि संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तातमदॉ की स्थायी भूमिका बनी रहे। संसद में एक तरफ तो 25% सीटें सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित की गई, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक संशोधनों के लिए 75% से अधिक सांसदों की सहमति को

अनिवार्य बनाया गया।[228] इससे यह स्पष्ट होता था कि सैन्य प्रतिष्ठान के पास हमेशा ही किसी भी बड़े सुधार पर वीटो करने की क्षमता है। साथ ही, "संघ की अखंडता" बनाए रखने जैसे प्रावधानों का उपयोग संघीय शासन के खिलाफ उपाय के रूप में किया गया,[229] जिससे जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) को स्वायत्तता की मांग को हतोत्साहित किया जा सके। सत्ता के विकेंद्रीयकरण को करीने से किनारा किया गया, क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधनों पर सैन्य का एकाधिकार पर भी चोट पहुंचती। यहां तक कि संविधान शांति और सुलह प्रक्रिया को सीधे तौर पर कमजोर करता है, क्योंकि संविधान में बातचीत का एक असमान ढांचा प्रस्तावित किया गया, जहां सैन्य प्रतिष्ठान अपनी शर्तें थोपता है।[230] संविधान का ढांचा संसदीय कोटा और शांति वार्ता को जोड़ता है, क्योंकि EAOs की शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन सैन्य सहमति के बिना व्यावहारिक रूप से असंभव हैं। लेकिन, इसी ढांचे के तहत बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ी और 2015 तक कुछ प्रगति भी देखने को मिली।

2010 का आम चुनाव

7 नवंबर 2010 को 2008 के नए संविधान के अनुसार देश में चुनाव हुए।[231] हालाँकि, NLD और लोकतंत्र समर्थक जातीय और राजनीतिक दलों ने चुनावों का बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने चुनावों में भाग लेने के लिए कई शर्तें रखी थीं। इस शर्तों में संविधान में कुछ संशोधनों और जुंटा की ओर से प्रस्तावित राजनीतिक संरचना में कुछ बदलाव शामिल थे। जिसमें संसद पर सेना की भागीदारी को कम करने के लिए संविधान में परिवर्तन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और निगरानी, आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। लेकिन सैन्य शासकों ने इन शर्तों की ओर शायद ही ध्यान दिया हो, नतीजतन उस समय की सबसे बड़ी लोकतंत्र की हामी राजनीतिक दल ने चुनाव में भाग नहीं लिया।[232]

जुंटा समर्थित राजनीतिक पार्टी यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP) एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने दो सदनों वाली संसद और 14 क्षेत्रीय विधानसभाओं में चुनाव के लिए उपलब्ध 1,168 सीटों में से लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कुल 1,551 सीटों में से बाकी की सीटें 2008 के

संविधान के अनुसार सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित थीं।[233] नवंबर तक 37 पार्टियों ने पंजीकरण कराया था और चुनाव लड़ रही थीं। इनमें से कई छोटी, जातीय-आधारित पार्टियां थीं जो केवल कुछ सीमित क्षेत्रीय सीटों पर चुनाव लड़ रही थीं। मतदान 32 टाउनशिप के उन हिस्सों में नहीं कराया गया जहां सरकार और जातीय समूह सशस्त्र संघर्ष में शामिल थे। कुछ क्षेत्रों में व्यापक अनियमितताओं की सूचना मिली, जैसे कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा अग्रिम सामूहिक मतदान।[234] चुनाव के बाद, USDP यूएसडीपी ने द्विसदनीय राष्ट्रीय संसद में 80 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतीं।[235] 14 राज्य और क्षेत्रीय विधानसभाओं में परिणाम मिश्रित रहे, जहां कुछ जातीय पार्टियों ने आधी सीटें जीतीं, विशेष रूप से अराकान और शान राज्यों में।

टेबल 5

2010 का आम चुनाव[236]		
पार्टियां	**सीटें** (उच्च सदन)	**सीटें** (निचला सदन)
यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी	129	259
नेशनल यूनिटी पार्टी	5	12
नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स	4	8
शान नेशनलिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी	3	18
राखाइन नेशनलिटीज़ डेवलपमेंट पार्टी	7	9
ऑल मोन रीजन डेमोक्रेसी पार्टी	4	3
चिन प्रोग्रेसिव पार्टी	4	2

राष्ट्रवादियों का सदन (उच्च सदन) की 224 सीटों में से 168 सीटों पर चुनाव हुए।[237] बाकी की 56 सीटें (25%) चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखी गईं और क्योंकि उन्हें 2008 के संविधान के मुताबिक सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित किया गया, जिन्हें आधिकारिक रूप से "सेना के प्रतिनिधि" कहा जाता है। इसी तरह, प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) की 440 सीटों में से 325 सीटों पर चुनाव हुए, जबकि शान राज्य में 5 सीटों को रद्द कर दिया गया था। बाकी की 110 सीटें (25%) भी चुनाव से बाहर रखी गईं और उन्हें सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित किया गया। बर्मी-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अधिकांश USDP उम्मीदवारों का चयन हुआ। कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के पास व्यापक भ्रष्टाचार, विशेष रूप से USDP के सदस्यों और उनका समर्थन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं।[238]

2010 के चुनाव की सबसे बड़ी विफलता थी विपक्षी नेता आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) और अन्य प्रमुख दलों का इसका बहिष्कार करना। वहीं, जुंटा समर्थित राजनीतिक पार्टी यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP) की बड़ी जीत ने चुनाव की वैधता पर और बड़े सवाल खड़े कर दिए। USDP ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के वरिष्ठ जनरलों और प्रमुख व्यापारिक और सामुदायिक नेताओं को उम्मीदवार बनाया था।[239] 37 दलों ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें से कुछ जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन कई महत्वपूर्ण जातीय दल, जैसे कि कचिन प्रोग्रेसिव पार्टी, को बाहर रखा गया।[240] सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान को रोका गया, जो सरकार के कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है। चुनाव प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं ने भी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए।[241]

चुनाव के बाद 50 वर्षों में पहली बार म्यांमार में बहुदलीय निर्वाचित संसद का गठन हुआ और क्षेत्रीय विधानसभाओं की स्थापना हुई, जिससे जातीय राजनीतिक दलों को शासन में भाग लेने का अवसर मिला। इसने जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) और नागरिक समाज के साथ संवाद और बातचीत की संभावनाएं पैदा कीं। क्षेत्रीय विधानसभाओं के गठन ने जातीय समूहों के लिए विकेंद्रीकरण और प्रतिनिधित्व की संभावनाओं को बढ़ावा दिया।[242] इसके

अलावा, इस चुनाव ने एक नागरिक सरकार का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका नेतृत्व पूर्व सैन्य अधिकारी यू थिन सेन ने किया। उन्होंने शांति वार्ताओं को प्रोत्साहित करने और धीरे-धीरे सुधार लागू करने का प्रयास किया। हालांकि, सैन्य सत्ता की गहरी जड़ें और 2008 के संविधान की सीमाएं वास्तविक लोकतंत्रीकरण को बाधित करती रहीं। अपनी खामियों के बावजूद, 2010 का यह चुनाव म्यांमार के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।[243] इसने सुलह और सुधार की संभावनाओं की झलक पेश की, लेकिन साथ ही केंद्रीकरण, जातीय तनाव, और सैन्य प्रभुत्व की स्थायी चुनौतियों को भी उजागर किया। हालांकि इसकी प्रभावशीलता और दीर्घकालिक प्रभाव पर उस समय तो बहस होती रही, लेकिन 2021 के तख्तापलट ने इस प्रक्रिया की नाज़ुकता और सैन्य वर्चस्व की चुनौती को लेकर स्थिति रुख पूरी तरह मोड़ दिया। जो बताता है कि लोकतांत्रिक सुधारों की एक सीमा है।

NLD ने 2010 के आम चुनाव का बहिष्कार तो किया, हालांकि समय के साथ NLD ने इस गतिरोध की स्थिति को आदर्शवादी तरीके के बजाए व्यवहारिक तरीके से सुलझाने की कोशिश 2012 तक आते-आते यह समझ बनती गई कि राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना मौजूदा तंत्र के भीतर से लोकतांत्रिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है।[244] 2012 के उप-चुनाव और 2015 के चुनावों में भाग लेकर, NLD ने राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने और संविधान में संशोधन करने और अधिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को हासिल करने की दिशा में काम करने का प्रयास किया।

अपने शासन को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दिलाने और लोकतंत्र विरोधी छवि को दूर करने में जुंटा कुछ हद तक कामयाब होती दिखी, क्योंकि 2015 तक राजनीतिक दर चुनावों में भागीदारी शुरु कर चुके थे। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि आख़िर कैसे इस प्रक्रिया में शुरुआती रूप से स्थापित तंत्र अपनी वैधता कायम करने में कम से कम सफल दिखता है। कई अध्ययन यह बताते हैं कि म्यांमार की सैन्य सत्ता ने कानूनी और प्रशासनिक तंत्रों का योजनाबद्ध रूप से उपयोग किया है ताकि पूर्ण लोकतंत्र की मांग और जातीय अल्पसंख्यकों को कमजोर किया जा सके। ख़ास बात यह भी है कि राज्य विरोधी राजनीतिक आवाज़ों पर दबाव बनाने के लिए केवल प्रत्यक्ष हिंसा पर निर्भर नहीं है, बल्कि

"कानूनी दमन" का सहारा लेता है, जिसमें कानूनों, विनियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके उनके स्वायत्तता को कमजोर किया जाता है और उनके प्रतिरोध की क्षमता को कम किया जाता है।[245] अधिनायकवादी तंत्र के पास ये ऐसे उपाय होते हैं, जो आमतौर पर तो निष्पक्ष और वैध प्रतीत होते हैं, जैसे म्यांमार में नागरिकता कानून, भूमि स्वामित्व नीतियां और सुरक्षा से संबंधित नियमों को बहिष्कार और नियंत्रण के प्रमुख साधनों के रूप में इस्तेमाल किया गया है।[246]

2008 के संविधान का ऊपर किया गया विशलेषण इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसके प्रावधान यह भी स्थापित करते है कि इसमें प्रस्तावित राजनीतिक संरचना काफी नाज़ुक है और जिसका एक बड़ा उदाहरण वर्ष 2021 के फरवरी में हुआ सैन्य तख्तापलट है। इस तख्तापलट ने संविधान को सीधे दरकिनार करके सैन्य शासन को सीधे बहाल कर दिया। आगे हम इस तख्तापलट की विस्तार से व्याख्या करेंगे। हालांकि संविधान शांति स्थापना की प्रक्रिया और सुलह की कोशिशों को पूरी तरह से रोकता नहीं है, लेकिन यह समावेशी और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के निर्माण के लिए होने वाले ज़रूरी सुधारों के दायरे को सीमित करता है। इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि क्या क्रमिक या कहें कि धीरे-धीरे होने वाले सुधार की आकांक्षा पूरी हो पाएगी या नहीं।

2015 का संघर्षविराम समझौता

2010 के चुनाव के बाद, म्यांमार में एक अर्ध-नागरिक सरकार की स्थापना और लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरु हुई। राष्ट्रपति थीन सीन की सरकार ने 2013 में जातीय सशस्त्र समूहों (Ethnic Armed Organizations - EAOs) के साथ बातचीत शुरू की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी युद्धविराम समझौता करना और राजनीतिक संवाद स्थापित करना था। 15 अक्टूबर 2015 को, म्यांमार सरकार और 8 जातीय सशस्त्र समूहों ने NCA पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संघर्षविराम, राजनीतिक संवाद, और संघीय व्यवस्था की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता शामिल थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख संगठनों में करेन नेशनल यूनियन (KNU), शान राज्य पुनर्स्थापना परिषद (RCSS), और चिन

नेशनल फ्रंट (CNF) शामिल थे।[247] इसके अलावा, अराकान लिबरेशन पार्टी, पाओ नेशनल लिबरेशन संगठन, करेन नेशनल यूनियन/करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी पीस काउंसिल, और डेमोक्रेटिक करेन बेनेवोलेंट आर्मी-5 (DKBA-5) जैसे छोटे संगठन भी शामिल थे।[248] हालांकि, कचिन इंडिपेंडेंस संगठन (KIO), यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी (UWSA) जैसे प्रभावशाली समूहों ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि क्षेत्रीय स्वायत्तता, संघीय शासन और कुछ समूहों को प्रक्रिया में शामिल करने के मुद्दों पर समझौता नहीं हो सका था।[249]

हम देख चुके हैं कि कैसे 1962 में सैन्य शासन की शुरुआत के साथ ही जातीय समूहों के अधिकारों को अनदेखा किया गया और उन्हें राजनीतिक रूप से और बलपूर्वक दबाया गया। इसके बावजूद, 2011 में अर्ध-नागरिक सरकार का गठन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत ने शांति की दिशा में कुछ प्रगति की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। 2013 में जातीय सशस्त्र समूहों के साथ शांति वार्ता की प्रक्रिया का बुनियादी लक्ष्य था, एक समावेशी संघीय व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना।

15 अक्टूबर 2015 को म्यांमार सरकार और आठ प्रमुख जातीय सशस्त्र समूहों ने राष्ट्रव्यापी युद्धविराम समझौता (NCA) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में संघर्षविराम, राजनीतिक संवाद की शुरुआत, और संघीय प्रणाली की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता थी।[250] यह एक ऐतिहासिक समझौता था, जो म्यांमार के इतिहास में पहली बार सरकार और जातीय समूहों के बीच औपचारिक शांति प्रयास के रूप में सामने आया।[251] NCA के बावजूद, म्यांमार की शांति प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण समस्याएं बनी रहीं। शुरुआत में, शांति प्रक्रिया की दिशा में कुछ प्रगति देखने को मिली, लेकिन विभिन्न जातीय समूहों के बीच संवाद की कमी इस प्रक्रिया बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रही थी। इस प्रक्रिया में समावेशिता यानी सारे पक्षों को बराबरी से स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में साझेदारी का मौका देना एक बड़ी चुनौती थी। जिसकी बुनियाद में था सेना का वर्चस्व, जो सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह बहुआयामी थे जहां प्राकृतिक संसाधनों और नागरिक अधिकारों की पूर्ण

बहाली भी शामिल थे।[252] NCA के दौरान कई प्रमुख सशस्त्र समूहों के न शामिल होने के कारण, शांति की प्रक्रिया में स्थायित्व की कमी बनी रही।

इस राष्ट्रीय संघर्षविराम समझौते के मूलभूत सिद्धांतों के प्रावधान कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य एक संघ की स्थापना करना है जो लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित हो, जो राजनीतिक संवाद के परिणामों के अनुसार और पांगलोंग की भावना में हो, जो लोकतांत्रिक अधिकारों, राष्ट्रीय समानता और स्व-निर्णय के अधिकार की पूरी गारंटी प्रदान करता है, जबकि संघ की अखंडता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों को बनाए रखता है।[253] इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय संघर्षविराम स्थापित करना होगा। इसमें एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की बात की गई है जहां सभी नागरिकों के ना सिर्फ समान अधिकार हों बल्कि जाति, धर्म, संस्कृति या लिंग के आधार पर भेदभाव को हटाने की बात की गई है।[254] इतना ही नहीं, समझौते में सभी जातीय समूहों के विशिष्ट इतिहास, सांस्कृतिक प्रथाओं, साहित्य, भाषा और राष्ट्रीय विशेषताओं को मान्यता देकर एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने का वादा किया गया है। इसमें एक संयुक्त संघर्षविराम निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है, जो समझौते के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने पर निगरानी और कथित उल्लंघनों की जांच भी करेगा।[255] इस समझौते में यह प्रावधान भी किए गए कि संघर्षविराम क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां जैसे क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए सैनिकों/लड़ाकों की तैनाती, भर्ती, सशस्त्र हमले, बारूदी-सुरंग बिछाना, और ऐसे ही दूसरे सैन्य अभियानों को रोकना होगा। सभी पक्षों द्वारा बिछाई गई खदानों को हटाने के लिए सरकार के साथ समन्वय में कार्रवाई की जाएगी।[256] एक महत्वपूर्ण बिंदु इन प्रावधानों में से यह भी था कि संघर्षविराम क्षेत्रों में कानून व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

समझौते में दोनों पक्षों के सभी सैनिकों/लड़ाकों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में सीमित रखना और सैन्य अड्डों की संख्या पर आपसी सहमति से समन्वय करना ज़रूरी होगा। बिना हथियार के सैनिकों की आवाजाही को सभी क्षेत्रों में, सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर, अनुमति दी जाएगी।[257] राजनीतिक रोडमैप के तहत इसके प्रावधानों में राजनीतिक संवाद की रूपरेखा का मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसमें यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस और पायडाउंगसु समझौते पर हस्ताक्षर

करना शामिल है। हालांकि यहां यह समझना ज़रूरी है कि 'प्यीदौंग्सु समझौता' नाम का कोई एक दस्तावेज़ नहीं है, यह विभिन्न शांति पहलों, समझौतों और सम्मेलनों से मिलकर बनता है, जो लगातार चलती रहेगी।[258] जैसे कि राष्ट्रव्यापी युद्धविराम समझौता (NCA) और 21वीं सदी का पांगलोंग शांति सम्मेलन। इन प्रयासों का उद्देश्य राजनीतिक संवाद, शक्ति-साझाकरण और संवैधानिक सुधारों के लिए एक ढांचा स्थापित करना है[259] ताकि जातीय अल्पसंख्यकों की शिकायतों का समाधान किया जा सके और एक संघीय और लोकतांत्रिक म्यांमार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

इस समझौते के शुरुआत से ही जब कुछ प्रमुख समूह जैसे KIA और UWSA इससे बाहर रहे, तो इसकी वैधता पर बड़े सवाल उठ गए थे।[260] आज यह कहा जा सकता है कि तात्मदॉ ने इस शांति प्रक्रिया का उपयोग अपने रणनीतिक हितों को साधने और विवादित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए किया, जिसकी इजाज़त इस समझौते के प्रावधानों में ही है।

सरकार और सेना ने EAOs के भीतर मतभेदों का लाभ उठाया और संघवाद के लिए उनकी एकीकृत मांगों को कमजोर कर दिया।[261] युद्धविराम की स्थिति ने जुंटा को विवादित क्षेत्रों में अपने प्रशासनिक और सैन्य प्रभाव का विस्तार करने के मौके दिए, जिसने 2008 के संविधान के केंद्रीकृत ढांचे को और मजबूत ही किया। वहीं, EAOs के बीच आपसी विभाजन और सरकार/सेना की संघीय राजनीतिक संरचना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी भी प्रमुख बाधाएं रहीं। इसके अलावा, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए बनाई गई समितियां प्रभावी साबित नहीं हुईं।[262] इसके परिणामस्वरूप, संघर्षविराम के बावजूद, सैन्य अभियानों में तेजी आई और सशस्त्र संघर्षों में कोई कमी नहीं आई।

आठवां अध्याय

सीमित लोकतंत्र का जश्न और सेना की वापसी (2015 - 2020)

2008 से लागू संविधान के आधार पर दूसरा आम चुनाव नवंबर 2015 में हुआ। 2015 का आम चुनाव म्यांमार के राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि 2010 के चुनाव के विपरीत इन चुनाव ने दशकों से जारी सैन्य शासन से अर्ध-लोकतांत्रिक प्रणाली के सफर को पूरी दुनिया के सामने रखा। 1962 में जनरल ने विन द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद से, म्यांमार ने सैन्य शासन के तहत सत्तावादी शासन सहा, जिसमें सैन्य बल ने राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। 2011 में राष्ट्रपति थीन सीन के नेतृत्व में उदारीकरण के प्रयास शुरू हुए, जिन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई, प्रेस की स्वतंत्रता में छूट और आर्थिक आधुनिकीकरण सहित सुधारों की प्रक्रिया शुरू की।[263] इन परिवर्तनों ने 2015 के चुनावों के लिए एक आधार-भूमिका तैयार किया। हालांकि अभी तक संविधान के तहत संसद की 25% सीटें (अनुच्छेद 436)[264] सेना के लिए आरक्षित दी और जिससे राजनीतिक व्यवस्था में सेना का प्रभाव बना रहा। इन बाधाओं के बावजूद, यह चुनाव सुधारों की गंभीरता और लोकतंत्र के प्रति देश की प्रतिबद्धता की परीक्षा के रूप में देखा गया। 2015 की इस बड़ी जीत की एक पृष्ठभूमि भी है जो 2012 के उपचुनाव से जुड़ी है। दरअसल में 2010 में हुए आम चुनावों के बहिष्कार के बाद 1 अप्रैल 2012 में 45 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें सू ची की पार्टी NLD ने पहली बार भागीदारी की थी।[265] इस चुनाव में 45 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें से NLD को 43 सीटों पर जीत मिली। इन 45 सीटों में से 40 सीटें तो प्रतिनिधि सभा की हीं थी, जो कई कारणों की वजह से खाली हुई थी, जिनमें एक मुख्य कारण था निर्वाचित सांसदों का कार्यकारी शाखा में शामिल होना।[266] NLD को 13 दिसंबर 2011 को उपचुनावों के लिए फिर से अपना पंजीकरण कराना पड़ा, जो 2010 से

म्यांमार में चल रहे सुधारों का हिस्सा था। आंग सान सू ची खुद भी रंगून क्षेत्र के सीट से प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ीं और विजयी हुईं। यह जीत से साथ उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद पहली बार राष्ट्रीय संसद में पहुंची, जो म्यांमार की राजनीतिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रही थीं।[267] हालांकि संसद के अंदर NLD और सेना के बीच संविधान के कई पहलुओं को लेकर टकराव की स्थिति पैदा होती रही। बहरहाल, इसी टकराव के हालातों के बीच 2015 का आम चुनाव हुआ और आंग सान सू ची के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर, एकतरफा जीत दर्ज की। उच्च सदन की 224 सीटों के लिए हुए चुनाव में NLD ने 135 सीटों के साथ एक बड़ी जीत हासिल की, जबकि सेना समर्थित पार्टी USDP को सिर्फ 12 सीटें मिलीं और अराकान नेशनल पार्टी (ANP) ने 10 सीटें जीतीं, जबकि 56 सीटें सेना के लिए आरक्षित थीं।[268] इसी तरह, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचली सदन के लिए 440 सीटों में 433 पर हुए चुनाव में से NLD ने 255 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। वहीं USDP को 30 सीटें मिलीं, ANP और शान नेशनलिटीज लीग फॉर डेमोक्रेसी (SNLD) को 12-12 सीटें मिलीं और 110 सीटें सेना के लिए आरक्षित थीं।[269] इस निर्णायक जीतों के बाद, NLD ने अप्रैल 2016 में सत्ता संभाली।

टेबल 6

2015: चुनाव परिणाम[270]		
राजनीतिक दल	**(निचला सदन)** सीटें	**(उच्च सदन)** सीटें
नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD)	255	135
यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP)	30	11
अराकान नेशनल पार्टी (ANP)	12	10
शान नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (SNLD)	12	3
अन्य दल	14	9
कुल निर्वाचित	323	168

यह 1962 के बाद पहली बार था जब एक नागरिक नेतृत्व वाली सरकार सत्ता संभालने जा रही थी। इस बदलाव ने नागरिक स्वतंत्रता और सैन्य प्रभुत्व को नकारने का जनादेश दिया। हालांकि, सू ची को उनके विदेशी मूल के परिवार के कारण राष्ट्रपति बनने से रोकने वाली संवैधानिक बाधा के बावजूद, उन्होंने एक विश्वसनीय सहयोगी को राष्ट्रपति नियुक्त करके सरकार को आगे बढ़ाया।[271] चुनाव को शांतिपूर्ण और विश्वसनीय माना गया और इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने व्यापक रूप से सराहा।

चुनाव ने राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार के विविध जातीय समूहों के बीच सुलह, आर्थिक विकास और दशकों पुराने संघर्षों के अंत की उम्मीदें बढ़ाईं। हालांकि, सेना की गहरी पैठ, अनसुलझे जातीय तनाव और चल रहे रोहिंग्या संकट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लोकतांत्रिक परिवर्तन में बाधा बने रहे। इसके अतिरिक्त, 2008 के संविधान की संरचनात्मक सीमाओं ने सेना को पर्याप्त प्रभावी बनाए रखा। इसके बावजूद, 2015 का चुनाव म्यांमार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जो लंबे समय तक लोकतंत्र के प्रति लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बना रहा और कई मायनों में आज भी है। यह राजनीतिक परिवर्तन की संभावनाओं और सीमाओं की एक मजबूत याद दिलाता है, जो एक सत्तावादी अतीत और विविध सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहे राष्ट्र के लिए बेहद प्रासंगिक है। NLD की यह जीत लोकतंत्र के प्रति व्यापक जनसमर्थन और USDP से असंतोष की घोषणा करती है। हालांकि, शान और रखाइन राज्यों में विशेष रूप से जातीय अल्पसंख्यक पार्टियों को सीमित सफलता मिली, लेकिन चुनाव परिणामों ने NLD के अधिकांश क्षेत्रों में प्रभुत्व को उजागर किया और जातीय विभाजनों और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की जटिल भूमिका को रेखांकित किया।[272]

1990 के चुनाव परिणामों को मान्यता देने से सेना के इनकार की पृष्ठभूमि इस बदलाव को लेकर आशंकाएं तो पैदा कर रही थीं, क्योंकि 1962 के तख्तापलट के बाद से सेना ही देश को नियंत्रित कर रही थी। सैन्य नेताओं द्वारा शांतिपूर्ण हस्तांतरण के आश्वासन के बावजूद, NLD के शासन संरचना, प्रशासन में सू ची की भूमिका, संवैधानिक सुधारों पर संभावित समझौतों और विदेश नीति की दिशा को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई थीं। इन अनिश्चितताओं की शुरुआत

ही संसद में शपथ ग्रहण से ही होती है, जहां सांसदों को 'संविधान की रक्षा' की शपथ लेनी होती थी।[273] यह वही संविधान है जिसके विरोध में NLD ने 2010 के आम चुनावों में भागीदारी करने के इंकार कर दिया था। इसके बाद सरकार के गठन की सीमाओं पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जैसे NLD की शीर्ष नेता को संविधान इस आधार पर राष्ट्रपति बनने से रोकता है क्योंकि उनकी शादी विदेशी व्यक्ति से हुई थी। इसके अलावा संविधान के प्रावधान गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सीमा मामलों के मंत्री के पदों को सेना के लिए आरक्षित करते हैं।[274] इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि नागरिक सरकार बनने के बाद भी तात्मादॉ (सेना) सशस्त्र जातीय समूहों को लेकर निर्णय का अधिकार काफी हद तक अपने पास सुरक्षित रखता है। यही नहीं, यहां तक कि कानून पारित करने के लिए संसद में कम से कम 75% वोटों की आवश्यकता होती है, जिसमें संविधान में संशोधन करने वाला कानून भी शामिल है, जो नागरिक सरकार के बहुमत के बाद भी असंभव था, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित थे।[275]

अप्रैल 2016 में पांच दशकों बाद पहली बार एक नागरिक सरकार ने सेना के व्यापक वर्चस्व के बीच सत्ता संभाली। अब तक किवदंती बन चुकी आंग सान सू ची के नेतृत्व में NLD ने सरकार का गठन किया। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों की वजह से सू ची राष्ट्रपति नहीं बन पाई लेकिन उन्हें 'स्टेट काउंसिलर' का पद दिया गया।[276] 'स्टेट काउंसिलर' का पद पहली बार अप्रैल 2016 में ही गठित किया गया, जो कि सू ची के लिए निर्मित किया गया था। इस पद का अधिकार क्षेत्र व्यापक था जो सरकार के प्रमुख के रूप में काम करता था। इस पद ने सू ची को सरकार के विभिन्न विभागों और नीतियों पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार दिया।[277]

सू ची की सरकार ने प्रशासन ने आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास आगे बढ़ा और गरीबी दर में कमी आई।[278] सरकार ने अगस्त 2016 में यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस – '21वीं सदी पांगलोंग'[279] की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और लंबे समय से चले आ रहे जातीय संघर्षों इन सशस्त्र जातीय समूहों की चिंताओं और मांगों को

लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर समाधान के रास्ते पर लाना था। हालांकि, इस दौर की ख़बरों बताती हैं कि जातीय समूहों और सेना के बीच हिंसक संघर्ष का दौर जारी रहा और इस बीच रखाईन क्षेत्र में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई व्यापक हिंसा ने तत्कालीन प्रशासन और सरकार पर भी ढेरों सवाल उठाए, जिसकी ज़द में आंग सान सू ची की नीतियां और सेना के उनके संबंध भी आए।

25 अगस्त, 2017 को अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) नामक रोहिंग्या उग्रवादियों ने रखाइन राज्य में 30 से ज़्यादा सरकारी पुलिस स्टेशनों पर हमला किया। जवाब में सरकारी सैनिकों ने रखाइन राज्य के रोहिंग्या गांवों पर हमले किए।[280] 2 सितंबर, 2017 को सरकारी सैनिकों ने रखाइन राज्य में दस रोहिंग्या पुरुषों को मार डाला। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (MSF) के अनुसार, सितंबर 2017 के अंत तक हिंसा में लगभग 7,000 रोहिंग्या मारे गए, जिनमें 730 बच्चे भी शामिल थे।[281] 2017 में 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश भाग गए। रोहिंग्या शरणार्थी भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी भागे।[282] 12 सितंबर, 2018 को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (HRC) द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र मिशन की रिपोर्ट ने म्यांमार सरकार पर "नरसंहार के इरादे" से सामूहिक हत्याओं और बलात्कार में शामिल होने का आरोप लगाया।[283] वहीं, 11 नवंबर, 2019 को, गाम्बिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार किया है।[284] अगले महीने, म्यांमार की स्टेट काउंसलर, आंग सान सू ची ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि म्यांमार "रोहिंग्या उग्रवादियों द्वारा समन्वित और व्यापक हमलों से शुरू हुए एक आंतरिक सशस्त्र संघर्ष से निपट रहा था"।[285] उन्होंने यह भी कहा कि अगर "म्यांमार की सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा युद्ध अपराध किए गए हैं, तो उन पर म्यांमार के संविधान के अनुसार और देश की सैन्य न्याय प्रणाली के माध्यम से मुकदमा चलाया जाएगा।"[286] 10 दिसंबर, 2019 को, अमेरिकी सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कथित मानवाधिकारों के हनन के लिए कमांडर-इन-चीफ सहित चार म्यांमार सैन्य नेताओं के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध (संपत्ति फ्रीज) लगाए।[287] 3 सितंबर, 2020 को, कनाडा और नीदरलैंड की सरकारों ने ICJ

में म्यांमार सरकार के खिलाफ गाम्बिया के मामले में भागीदारी की।[288] यह घटनाक्रम एक समावेशी राजनीतिक ढांचा और संघीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनाने की मंशा के बिलकुल ही विपरीत जाता दिखता है।

2016 में गठित नई असैन्य सरकार से राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों को लागू करने की उम्मीद थी, जो एक समावेशी संघीय लोकतंत्र की दिशा की राह आसान कर सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक ढांचे की उम्मीद की जा रही थी जो जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों, देश के संसाधनों का समान बंटवारा और उनके समावेशी विकास को सत्ता का विकेंद्रीकरण के ज़रिए पूरा कर सके। इसी के साथ एक प्रमुख मुद्दा था राजनीतिक संरचना के सेना को अलग करना। हालाँकि, रोहिंग्या संकट और लगातार चल रहे जातीय संघर्षों ने इस परिवर्तन की संरचनात्मक सीमाओं और म्यांमार के राजनीतिक परिदृश्य की गहरी चुनौतियों को उजागर कर दिया था। बुनियादी बात यह भी थी कि सू ची और NLD के नेतृत्व वाली असैन्य सरकार ने 2016 में लोकतांत्रिक सुधारों के व्यापक जनादेश के साथ पदभार संभाला था। 21वीं सदी के पांगलोंग सम्मेलन के माध्यम से शांति प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका उद्देश्य एक राष्ट्रव्यापी युद्धविराम पर बातचीत करना और एक संघीय प्रणाली की ओर बढ़ना था, जो अल्पसंख्यक जातीय राज्यों और क्षेत्रों को शासकीय स्वायत्तता प्रदान करेगा।[289] इससे रोहिंग्या जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर मान्यता और अधिकार मिलने की आशा भी बढ़ी थी। 2017 में रोहिंग्या संकट ने इन आशाओं को काफी धक्का पहुंचाया और म्यांमार के लोकतांत्रिक परिवर्तन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। इस संकट पर असैन्य सरकार की प्रतिक्रिया को व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा। जब आंग सान सू की ने दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार का बचाव करने के लिए पेश हुईं, तो यह उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।[290] 2017 के इस रोहिंग्या संकट, नागरिक सरकार के सेना के मिलीभगत की आशंकाओं ने जातीय विभाजनों को गहरा कर दिया।[291] वहीं, रोहिंग्या नागरिकता को मान्यता देने या उन्हें म्यांमार की राजनीतिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया, लेकिन सच यह भी था कि नागरिक सरकार के पास रक्षा, गृह मामले और सीमा मामले सीधे नियंत्रण में नहीं थे। जिससे NLD को सैन्य

प्रभुत्व को चुनौती देने की सीमित शक्ति मिली। इस दौरान भी पूरे देश में जातीय सशस्त्र समूह सेना और केंद्र सरकार के नियंत्रण का विरोध कर ही रहे थे। असैन्य सरकार ने शांति वार्ता की मध्यस्थता करने का प्रयास तो किया, लेकिन सेना के कठोर रुख और जातीय क्षेत्रों में निरंतर सैन्य हमलों ने इन प्रयासों को कमजोर ज़रूर कर दिया। इस बीच सबसे बड़ी बात शायद यही थी कि संवैधानिक सुधारों की रुकी हुई प्रक्रिया ने एक वास्तविक संघीय प्रणाली के विकास की गति को काफी सीमित कर दिया।

सू ची: टकराव के बजाय यथास्थितिवाद का सहारा

आंग सान सू ची की सरकार सेना के साथ मिलकर 2020 तक सरकार चला रही थी यहां तक कि उन्होंने कई मसलों पर सेना का बचाव भी किया।[292] संवैधानिक बाध्यताओं को दरकिनार करके उन्हें स्टेट काउंसिलर का पद दिया गया, जिसका गठन भी सू ची के लिए ही किया गया और जिसका विरोध सेना की तरफ से नहीं हुआ। 2015 के आम चुनावों के बाद सू ची और NLD सरकार ने म्यांमार के जनरलों के साथ अनौपचारिक समझौते के तहत सेना के विशेषाधिकारों को कायम रखते हुए चुनाव परिणामों और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करवाया। दोनों पक्षों के बीच यह सहयोग काफी जटिल ताना-बाना था, क्योंकि दोनों पक्ष लोकतांत्रिक सुधारों के दबाव और यथास्थिति बनाए रखने की समझ के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे थे। एनएलडी की 'लेटिंग स्लीपिंग डॉग्स लाई' की अनकही नीति ने संक्रमण में काफी मदद की।[293] सू ची की पार्टी ने सेना के विशेषाधिकारों की रक्षा करने वाली राजनीतिक प्रणाली को संशोधित करने का प्रयास नहीं किया। बदले में, सेना ने NLD की सरकार को गिराने का प्रयास नहीं किया। सेना से गहरे रूप से जुड़े हुए नौकरशाही तंत्र का सामना करते हुए, आंग सान सू की के नेतृत्व में NLD ने तुरंत इन तत्वों से टकराव करने का रास्ता चुनने के बजाए विश्वास निर्माण और भविष्य के सुधारों की नींव रखने पर ध्यान केंद्रित किया।

सेना की देश में राजनीतिक संरचना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के कई कारणों में एक कारण यह भी रहा है कि म्यांमार में सैन्य बलों के शुरु से ही अपने आर्थिक हित रहे हैं, जो यथास्थितिवाद को आगे ले जाने में यकीन करते हैं। अपनी विशाल आर्थिक समूह कंपनियों, म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स

लिमिटेड (MEHL) और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन (MEC) के माध्यम से, सेना प्राकृतिक संसाधनों, खनन, बैंकिंग और दूरसंचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण रखती है। ये उद्यम सेना को बड़ी मात्रा में आर्थिक शक्ति देते हैं।[294] सेना की आर्थिक स्वायत्तता ने संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों के प्रयासों को कमजोर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। NLD के नागरिक शासन के दौरान भी, सेना ने उन आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों का विरोध किया जो उसकी पकड़ को कमजोर कर सकते थे[295] यहां तक कि तत्कालीन सरकार ने भी सुधारों की आकांक्षों को एक हद तक सीमित ही रखा।

इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार के पास ठोस उपलब्धियों के रूप में दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। प्रमुख सवाल यह भी है कि क्या बदलावों के एजेंडों को NLD ने 2020 तक छोड़ दिया था या स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए और क्रमिक सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। बाद में कुछ आलोचकों ने इसे देश में इसे 'जुड़वां अधिनायकवाद' की संज्ञा दी।[296]

सू ची की नेतृत्व वाली सरकार के इस विशलेषण में सबसे प्रमुख सवाल है कि क्या म्यांमार इस दौरान अपने संघीय संवैधानिक लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ा या नहीं ? देश की आज़ादी के समय से ही जातीय समूहों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए एक ऐसे संविधान और राजनीतिक प्रणाली की ओर बढ़ना था जहां संघवाद सच्चे मायनों में देश को एकजुट कर सके। म्यांमार की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा जातीय अल्पसंख्यकों ने सू ची और NLD का समर्थन किया था यह उम्मीद करते हुए कि वह सैन्य प्रभुत्व को चुनौती देंगी और संघीयता के सपने को साकार करेगी।[297] हालांकि, समय के साथ, वह सत्ता की स्थिरता हावी होती हुई लगी, जहां जातीय समुदायों की मांगों के मुकाबले राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी गई। 21वीं सदी के पांगलोंग सम्मेलन की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि सेना और जातीय सशस्त्र समूहों के बीच शांति सुनिश्चित किया जाएगा।[298] जबकि इस कोशिश ने देश के लंबे समय से चले आ रहे गृह युद्ध को और बढ़ावा ही दिया और 2015 का संघर्ष विराम भी सफल नहीं हो सका।

2020 का आम चुनाव

घरेलू और देश के बाहर भी NLD सरकार को मिले कई झटकों के बावजूद 2020 के अंत में एक बार फिर से आम चुनाव हुए। 8 नवंबर 2020 को हुए इस चुनाव में USDP और NLD सहित कई दलों ने भाग लिया। चुनाव में सू ची की पार्टी NLD ने एक बार फिर भारी जीत दर्ज की वह भी पहले से ज्यादा मतों के साथ। NLD ने दोनों सदनों को मिलाकर कुल 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत हासिल की, जो वर्ष 2015 के पिछले चुनाव से 390 सीटों की तुलना में 6 सीटें अधिक थी। पार्टी ने म्यांमार के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में 440 सीटों में 258 सीटें और ऊपरी सदन में 224 सीटों में 138 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बहुमत हासिल करने के लिए केवल 322 सीटों की आवश्यकता थी।[299] दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल - सेना-समर्थित USDP केवल 33 सीटें ही जीत सकी। इस पार्टी ने संसद के निचले सदन में 26 और ऊपरी सदन में केवल 7 सीटें ही हासिल की। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब चुनाव पर्यवेक्षकों ने इस चुनाव को 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' बताया तो वहीं तात्मादॉ ने चुनावों में घोर अनियमितताओं के आरोप लगाए।[300]

चुनावों के परिणाम यह बताते हैं कि नीतिगत स्तर पर कई असफलताओं के बाद भी देश में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। उनके अतीत के बलिदानों और नेतृत्व क्षमता पर जनता का विश्वास बना रहा। 2015 में NLD को जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भी जीत मिली थी, और 2020 में भी आंग सान सू की ने उन समुदायों में अपनी लोकप्रियता बनाए रखी,[301] बावजूद इसके कि उनकी सरकार जातीय समूहों की मांगों को हल करने में विफल रही थी।

NLD को चुनावों में जीत का जश्न मना ही रही थी कि USDP और 16 अन्य राजनीतिक दलों ने चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें करनी शुरु कर दी और फिर से मतगणना और स्वतंत्र जांच की मांग की गई। USDP ने 800 से अधिक शिकायतें दर्ज कराईं,[302] जिसके बाद यूनियन इलेक्शन कमीशन (UEC) पर भी सवाल उठने शुरु हो गए। म्यांमार की सेना चुनाव के पहले से ही यूनियन इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय NLD सरकार के कामकाज की आलोचना कर रही थी।

टेबल 7

2020 आम चुनाव: परिणाम[303]		
राजनीतिक दल	**प्रतिनिधि सभा (निचला सदन)**	**राष्ट्रवादियों का सदन (उच्च सदन)**
नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD)	258	138
यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP)	26	7
शान नेशनलिटीज लीग फॉर डेमोक्रेसी	13	2
अराकान नेशनल पार्टी	4	4
ता-अमग (पलौंग) नेशनल पार्टी	3	2
मोन यूनिटी पार्टी	2	3
पा-ओ नेशनल ऑर्गनाइजेशन	3	1
कायाह स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी	2	3
काचिन स्टेट पीपल्स पार्टी	1	0
अराकान फ्रंट पार्टी	1	0
वा नेशनल पार्टी	1	0
जोमी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी	1	0

2 नवंबर 2020 को रक्षा सेवा के कमांडर-इन-चीफ कार्यालय ने एक 'सात-बिंदुओं'[304] वाला बयान जारी किया, जिसमें UEC और संघ सरकार पर चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। इस बयान में ज़ोर दिया कि "आयोग (UEC) का कामकाज वास्तव में संघ सरकार की जिम्मेदारी होती है और आयोग को सरकार को रिपोर्ट करना होता है। इसलिए, चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर की जाने वाली आलोचना आयोग पर नहीं, बल्कि सरकार पर केंद्रित होनी चाहिए"।[305]

इन सब घटनाक्रमों का नतीजा यह हुआ कि सेना और NLD के बीच तनाव बढ़ गया। सेना प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने चुनाव परिणामों के बाद कहा कि वह "जनता की इच्छानुसार चुनाव परिणाम स्वीकार करेंगे"।[306] NLD की ऐतिहासिक जीत के बावजूद, सेना और नागरिक सरकार के बीच गहराते टकराव और विवादित चुनावी नतीजों ने म्यांमार के लोकतंत्र पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया। राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य प्रभाव और जातीय विभाजन के चलते देश का लोकतांत्रिक भविष्य 2021 के जनवरी तक अनिश्चित बना रहा।

2021 का तख्तापलट और गृहयुद्ध का नया दौर

सैन्य समर्थित राजनीतिक दल USDP और सेना ने नवंबर 2020 के चुनाव परिणामों को अस्वीकार करते हुए NLD पर आरोप लगाया कि चुनाव में धोखाधड़ी और अनियमितताएँ हुई हैं। इतना ही नहीं सेना ने चुनावों को फिर से कराने की मांग भी कर दी।[307] वहीं, चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव में धोखाधड़ी या अनियमितताओं के कोई प्रमाण नहीं हैं जो परिणाम को प्रभावित कर सकें। आयोग के इस रुख का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू चुनाव पर्यवेक्षकों ने भी किया।[308]

इसके बाद सेना ने सरकार से फरवरी 2021 की शुरुआत में निर्धारित संसद के उद्घाटन सत्र को स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। जनवरी 2021 के अंत में, सेना के सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने चेतावनी दी कि यदि कानूनों का सम्मान या पालन नहीं किया गया तो संविधान को रद्द किया जा सकता है।[309] 1 फरवरी 2021 को चुनाव के बाद पहली बार संसद की बैठक निर्धारित थी और उसी दिन सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया।[310]

राष्ट्रपति विन मिंत, आंग सान सू ची, और अन्य NLD सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया, और पूर्व सैन्य अधिकारी म्यिंट स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। नए राष्ट्रपति ने तुरंत संविधान के अनुच्छेद 417 और 418 को लागू करते हुए एक वर्ष की आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और सरकार की कार्यकारी, विधायी, और न्यायिक शाखाओं का नियंत्रण सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ, सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग को सौंप दिया। उन्होंने दावा किया कि "सैन्य अधिग्रहण आवश्यक था क्योंकि कथित चुनावी अनियमितताओं का समाधान नहीं हुआ था"[311] जनरल ह्लिंग ने

आपातकालीन स्थिति के अंत के बाद नए चुनाव कराने और विजेता को सत्ता सौंपने का वादा किया।

सेना ने राज्य प्रशासनिक परिषद (State Administration Council यानी SAC) का गठन किया गया, जिसमें सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग अध्यक्ष बने, ताकि आपातकालीन स्थिति के दौरान सरकारी कार्यों को संभाला जा सके। अगस्त 2021 में राज्य प्रशासनिक परिषद को एक सैन्य-नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार में बदल दिया गया और जनरल ह्लिंग को इसका प्रमुख नामित किया गया।[312]

इस तख्तापलट के बाद, देश के प्रमुख शहरों में बड़े स्तर पर व्यापक नागरिक अवज्ञा, विरोध प्रदर्शनों और सशस्त्र प्रतिरोध को भड़का दिया।[313] अंतरराष्ट्रीय निंदा और घरेलू विरोध का सामना करने के बावजूद, सेना ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद के शुरुआती 20 महीनों में कम से कम 6,000 नागरिकों की मौत हुई।[314] वहीं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, "म्यांमार में सुरक्षा बलों ने कम से कम 1,600 लोगों की हत्या की है और तख्तापलट के एक वर्ष के भीतर 12,500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है।"[315] राजनीतिक बंदियों के लिए सहायता संघ बर्मा के अनुसार, 19 फरवरी 2024 तक कुल 26,147 राजनीतिक कैदी हिरासत में थे।[316] देश जल्द ही "एक क्रूर और विध्वंसक गृहयुद्ध में उतर गया।"[317]

तख्तापलट और गृह युद्ध का नया दौर

2021 के तख्तापलट के बाद, विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पूर्व सांसदों ने एक 'निर्वासित सरकार' नेशनल युनिटी गवर्मेंट (NUG) का गठन किया गया। NUG ने देश में चल रहे प्रतिरोध गतिविधियों को संगठित किया और स्थानीय अल्पसंख्यक जातीय सशस्त्र संगठनों को एक संगठित बल में बदला, जिसे पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस (PDFs) कहा जाने लगा।[318] PDF जातीय सशस्त्र संगठनों के साथ संयुक्त कमान प्रणाली के तहत काम करती रही। जून 2019 में, तीन सशस्त्र समूहों—अराकान आर्मी (AA), म्यांमार

नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी (MNDAA), और ता'आंग नेशनल लिबरेशन आर्मी (TNLA) ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे 'थ्री ब्रदरहुड अलायंस' कहा जाता है।[319] यह गठबंधन 2023 में जुंटा (सैन्य शासन) के खिलाफ प्रतिरोध में प्रमुखता से उभरा। 27 अक्टूबर 2023 को, गठबंधन ने उत्तरी शान राज्य में जुंटा के खिलाफ "ऑपरेशन 1027" नामक एक सुनियोजित हथियारबंद अभियान शुरू किया।[320] जातीय समूहों के बीच आंतरिक मतभेद थे लेकिन इसके बाद भी विभिन्न विपक्षी गुट एकजुट हुए। यह सहयोगात्मक प्रयास देश के दो-तिहाई क्षेत्र में फैल गया, जो जुंटा के लिए आने वाले वक्त में बड़ा झटका साबित हुआ और PDF को लड़ाई के मैदान में बड़ी जीत हासिल हुई।[321] ऑपरेशन 1027 की शुरुआत उत्तरी शान राज्य से हुए जब 'थ्री ब्रदरहुड एलायंस' ने 27 अक्टूबर 2023 को म्यांमार सेना और पुलिस पर समन्वित हमले शुरू किए। नवंबर 2023 की शुरुआत तक, ब्रदरहुड एलायंस ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रगति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 100 से अधिक सैन्य अड्डों और कई कस्बों पर नियंत्रण प्राप्त किया। ऑपरेशन 1027 के एक साल बाद, यह गठबंधन और अन्य "प्रतिरोध बलों" ने म्यांमार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (60 प्रतिशत से अधिक[322,323,324])[325] अपने नियंत्रण में ले लिया है।

ऑपरेशन 1027 शुरू होने के करीब एक साल के अंदर 4,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है या उन्होंने अपनी सेवा छोड़ दी है, जो 2021 के तख्तापलट के बाद आत्मसमर्पण करने वाले 14,000 सैनिकों के आंकड़े में जुड़ गए।[326] जनवरी 2025 तक यह संख्या 15,000 से अधिक हो गई। द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट (ACLED) के अनुसार, 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से पहले तीन सालों में म्यांमार में कम से कम 50,000 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कम से कम 8,000 नागरिक शामिल हैं।[327]

इस बीच, म्यांमार में राजनीतिक कैदियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।[328] 2021 के तख्तापलट के बाद से, म्यांमार की सैन्य जुंटा की कार्यवाईयों में 6,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 20,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और न्यायिक फांसी की कार्यवाही को फिर से शुरू

किया गया है।[329] इस गृहयुद्ध की वजह से कम से कम 35 लाख से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, जबकि लाखों की संख्या में दूसरे देशों में भी लोगों का पलायन हुआ है, जिसमें मुख्यरूप से थाईलैंड, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश हैं।[330] भारत में, फरवरी 2021 से म्यांमार के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के लगभग 60,000 (नवंबर 2024 तक) लोगों ने शरण ली है।[331]

तख्तापलट के चार साल पूरे होते-होते यह स्पष्ट हो रहा था कि 2021 के तख्तापलट के बाद से म्यांमार में सशस्त्र विरोध काफी मुखर और व्यापक हो गया, जबकि जुंटा की सेनाएँ कमजोर होती गईं। आधिकारिक सैनिकों की संख्या 130,000 और सहायक बलों की संख्या 70,000 तक कम हो गई।[332] शान राज्य के प्रमुख सामरिक क्षेत्रों के साथ-साथ सशस्त्र बलों ने राखाइन, चिन, करेन, करेननी, सगाइंग और मगवे के एक बड़े हिस्से पर भी नियंत्रण कर लिया। वहीं, कचिन राज्य में कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने कई सैन्य पोजीशन्स पर कब्जा करने में सफलता पाई। दिसंबर 2024 में विद्रोहियों का आक्रमण म्यांमार के मध्य भाग में आगे बढ़ना शुरु हो गया, जिससे मांडले क्षेत्र में सेना पर दबाव बढ़ता जा रहा था।[333]

2024 के अगस्त में, म्यांमार की सेना (जुंटा) को लाशियो (सेना का उत्तरपूर्वी क्षेत्रिय मुख्यालय) में करारी हार का सामना करना पड़ा, जब म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी (MNDAA) ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया। कई महीनों तक चले हवाई हमलों के बावजूद जुंटा इस शहर को फिर से अपने नियंत्रण में नहीं ले पाई।[334] यह हार सेना के लिए एक महत्वपूर्ण झटका थी, क्योंकि यह पहली बार था जब सेना ने अपने 14 क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालयों में से एक को खो दिया।[335] इस पराजय से जुंटा समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया और सेना प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग के इस्तीफे की मांग तेज़ हो गई। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद शुरू हुए संघर्ष में सेना लगातार अपना नियंत्रण खोती चली गई। विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहों और तख्तापलट के विरोध में बने "पीपुल्स डिफेंस फोर्स" (PDF) जैसे संगठनों ने कई क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया।[336] म्यांमार पीस मॉनिटर के अनुसार, जनवरी 2025 तक 95 शहर जुंटा के हाथ से निकल चुके थे।[337] काचिन राज्य के उत्तर में 200 से अधिक सैन्य ठिकाने और कई महत्वपूर्ण शहर सेना ने खो दिए, जिनमें दुर्लभ

खनिजों के खनन वाले केंद्र भी शामिल थे। पश्चिम में रखाइन राज्य के 17 में से 14 टाउनशिप जुंटा के नियंत्रण से बाहर गया, जबकि केंद्रीय सगाइंग क्षेत्र में भी सेना को कई महत्वपूर्ण ठिकानों से हाथ धोना पड़ा।[338] हालांकि सेना लगातार हवाई हमलों और दमन के ज़रिए नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की।[339]

2024 में जुंटा ने देश में चुनाव कराने का वादा किया है, जिसे चीन का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव किस तरह कराए जाएंगे, क्योंकि देश के बड़े हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्ज़ा है।[340] विशेषज्ञों का मानना है कि सेना को मतदान कराने के लिए अत्यधिक हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे और अधिक संघर्ष भड़क सकता है।

संघर्ष ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। व्यापार मार्गों की बंदी के कारण खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। पेट्रोल की कीमत 7,500 क्यात ($3.60) प्रति लीटर हो गई है, जबकि चावल की एक बोरी की कीमत 290,000 क्यात ($138) हो गई है।[341] म्यांमार में व्यापक स्तर पर गरीबी बढ़ चुकी है, और आधी आबादी अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि रखाइन राज्य में व्यापार मार्गों के बंद होने और खाद्य आपूर्ति में रुकावट के कारण भुखमरी का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, और सेना द्वारा लागू किए गए अनिवार्य सैन्य भर्ती कानून के कारण बड़ी संख्या में युवा देश छोड़कर भाग रहे हैं।[342] हालांकि, जैसे-जैसे म्यांमार में गृहयुद्ध अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, स्थिति अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि विद्रोही समूहों ने महत्वपूर्ण बढ़त बनाई है, लेकिन आर्थिक संकट, मानवीय आपदा, और एक स्थिर सरकार बनाने की चुनौती अभी बाकी है।

बढ़ते दबाव के बीच जुंटा की असंगत नीतियाँ

फरवरी 2024 में जुंटा ने अनिवार्य सैन्य सेवा क़ानून को लागू कर दिया। एक अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार की फरवरी 2024 की अनिवार्य सैन्य भर्ती नीति के कारण बड़ी संख्या में युवा देश छोड़कर भागने लगे। कुछ मानवाधिकार समूहों का कहना था कि सैन्य सेवा से बचने के लिए दसियों हजार लोग पलायन कर गए।[343] ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के

अनुसार, फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच रखाइन राज्य से 1,000 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिम पुरुषों और लड़कों को जबरन भर्ती किया गया।[344] यह स्पष्ट था कि जुंटा को लेकर आम लोगों के समर्थन में तख्तापलट के बाद भारी कमी आई। यहां तक कि सेना को आम लोगों से कहना पड़ा कि "जनता राज्य के प्रति वफादार रहें और उन्हें कानून का पालन करने के साथ-साथ किसी भी सुरक्षा संबंधी कानून का पालन करना चाहिए, और राज्य की सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन करते रहें।"[345] ऐसे में यह समझा जा सकता है कि जब एक राज्य (State) अपने नागरिकों से वफादारी की मांग करता है तो वह राष्ट्रीय एकता और उसके प्रति लोगों की निष्ठा और राष्ट्र के कानूनों के अनुपालना को लेकर आशंकित है। यहां मुद्दे का एक पहलू यह है कि 'राज्य' के प्रति वफादारी और 'राष्ट्र' के प्रति वफादारी के बीच का अंतर है।[346] सितंबर 2024 में बढ़ते दबाव के बीच म्यांमार की सेना और SAC प्रमुख ने "विद्रोही संगठनों को राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक तरीकों से हल करने का प्रस्ताव" दिया। सेना प्रमुख ने उन समूहों के साथ संवाद करने का प्रस्ताव रखा, जिन्हें उन्होंने "आतंकवादी" करार था। सितंबर के इस प्रस्ताव में इन विद्रोही समूहों को "पार्टी राजनीति या चुनावी प्रक्रियाओं" के माध्यम से राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो शासन के पहले के कड़े रुख में एक बड़ा बदलाव है। बुनियादी बात है कि सैन्य शासन के रुख़ में यह बदलाव एक भीषण लड़ाई के बाद आया, जो उनके वैचारिक विरोधाभास को भी सामने रखता है। अक्टूबर 2024 में, SAC ने इन विद्रोही और लोकतंत्र समर्थक गुटों को फिर से 'आतंकवादी'[347] के रूप में नामित किया। SAC ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों को चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने सशस्त्र विद्रोही समूहों को संभावित सहायता प्रदान करने के बारे में चिंता व्यक्त की।

यह कहा जा सकता है कि 'ऑपरेशन1027' ने जुंटा की वैधता और वर्चस्व को और कमजोर कर दिया है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ता गया। इस दबाव के चलते लोकतंत्र समर्थक समूहों को एक नई ऊर्जा और वैधता मिलती गई कि देश के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व अब विपक्षी धड़ा कर रहा है। पड़ोसी आसियान देशों की ओर से भी यह दबाव बढ़ता गया क्योंकि जुंटा पहले ही आसियान के प्रस्तावित 'पांच-सूत्रीय सहमति' प्रक्रिया

को लागू करने में विफल हो चुका है।[348] विरोधी और लोकतंत्र समर्थक समूहों की बढ़त ने बाहरी दुनिया के सामने यह सोचने को मजबूर किया कि अब जुंटा के अलावा उनकों चुनौती देने वाले समूहों की ओर भी अब रुख करना चाहिए।[349] इसका एक बड़ा कारण था कि जुंटा शांति स्थापित की दिशा में बहुत कम प्रगति कर पाया, विशेष रूप से हिंसा रोकने या समावेशी संवाद शुरू करने के मुद्दे पर। अक्टूबर 2024 के आसियान शिखर सम्मेलनों में, फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इन चिंताओं को स्वीकार करते हुए कहा, "हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम वास्तव में स्थिति में सुधार लाने में बहुत सफल नहीं रहे हैं। इसलिए, हम नई रणनीतियों के बारे में सोचने का प्रयास कर रहे हैं।"[350] म्यांमार की इस बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए, थाईलैंड ने दिसंबर 2024 में एक अनौपचारिक चर्चा के आयोजन के लिए सक्रिय कदम उठाए।[351] इस कोशिश की बुनियाद में ही राज्य-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर समाधान के लिए दूसरे समूहों से संवाद की राह खुलने के संकेत है, जो जुंटा या केंद्रीय शासन से अलग राज्य को चुनौती देते हुए देश के एक बड़े हिस्सा पर काबिज हो चुके हैं और लोकतंत्र को स्थापति करने की बात करते हैं।

वैकल्पिक राजनीतिक प्रणाली और विरोधाभास

म्यांमार में 1 फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद, देश एक गहरे राजनीतिक संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ चला। इस तख्तापलट ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) सरकार को अपदस्थ कर दिया। यही वह वक्त था जब निर्वासित सरकार 'राष्ट्रीय एकता सरकार' (NUG) की स्थापना हुई। NUG का गठन एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि यह एक समावेशी शासन की दिशा में था, जिसमें विभिन्न जातीय समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। तख्तापलट के बाद, इन जातीय संगठनों और लोकतंत्र समर्थक बलों के बीच एकजुटता का नया अध्याय शुरू हुआ। यह एक साझा दुश्मन - सैन्य शासन - के खिलाफ सहयोग का एक ऐतिहासिक अवसर था। NUG ने संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की बात की, जो EAOs के लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्यों के साथ मेल खाती थी, जिसकी वजह से NUG और EAOs के बीच राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर समन्वय बढ़ा।

5 फरवरी 2021 को, 298 संसद सदस्यों ने वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहली आपातकालीन संसदीय बैठक आयोजित की और Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) का गठन किया।[352] वैध और कानूनी रूप से चुने गए संसद सदस्यों ने आभासी रूप से बैठक की और संसद के कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए 15 सांसदों को नियुक्त किया। इस बैठक में डेनमार्क, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य के दूतावासों से म्यांमार के कई पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।[353] CRPH के गठन और अधिकारों को अधिकृत करने वाले सांसदों की कुल संख्या 398 थी। यह संख्या ऑनलाइन बैठक में शामिल होने वाले और हस्ताक्षरित पत्रों के माध्यम

से अधिकृत करने वाले सांसदों का संयुक्त आंकड़ा था। 7 फरवरी को, CRPH ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया जिसमें सैन्य तख्तापलट को "आपराधिक कृत्य" करार दिया गया। CRPH ने म्यांमार के दंड संहिता की धारा 6 के उल्लंघन का हवाला दिया, जो नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के संदर्भ में था, साथ ही इसे निर्विवाद रूप से असंवैधानिक बताया।[354] 10 फरवरी 2021 को, CRPH ने जातीय पार्टियों के दो और सांसदों को शामिल करने का विस्तार किया और 26 अप्रैल को तीन और सदस्यों को जोड़ा गया। इसके बाद CRPH वैध विधायी प्राधिकरण के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश में लग गई और सैन्य शासन के खिलाफ एक नागरिकों के नेतृत्व वाली समानांतर सरकार के रूप में सामने आई। NUG के संगठन में अलग-अलग जातीय समूहों के प्रतिनिधियों को प्रमुख पदों पर शामिल किया गया। इसका मकसद संघीय लोकतंत्र की दिशा में काम करना था, जिससे म्यांमार के विभिन्न जातीय समुदायों की स्वायत्तता और अधिकारों को मान्यता मिल सके।

वैकल्पिक संघीय लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का रोडमैप

CRPH ने 31 मार्च 2021 को 2008 के संविधान को अमान्य घोषित किया और दूसरी घोषणाओं के साथ साथ संघीय लोकतांत्रिक चार्टर (Federal Democracy Charter - FDC) को संघीय लोकतंत्र की नींव रखने के लिए प्रस्तुत किया गया।[355] FDC एक राजनीतिक ढांचा है जिसे म्यांमार में सैन्य शासन को उखाड़ फेंकने और संघीय लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे NUG, EAOs और लोकतंत्र समर्थक समूहों द्वारा अनुमोदित किया गया।[356]

संघीय लोकतांत्रिक चार्टर दो मुख्य भागों में विभाजित है:
भाग I: राजनीतिक दृष्टिकोण और सिद्धांत[357]

1. तात्मादॉ का राजनीतिक प्रभाव समाप्त होना चाहिए और 2008 का संविधान रद्द किया जाना चाहिए।

2. म्यांमार को एक संघीय प्रणाली अपनानी चाहिए, जिससे जातीय अल्पसंख्यकों को समान और आत्मनिर्णय का अधिकार मिल सके।

3. भविष्य की सरकार को नागरिकों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसमें तानाशाही को रोका जा सके।

4. सैन्य अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना और मानवाधिकारों का सम्मान हो।

5. सभी जातीय और धार्मिक समूहों को संघीय प्रणाली के तहत समान अधिकार होंगे।

6. सभी लोकतंत्र समर्थक बलों, जिसमें जातीय सशस्त्र संगठन (EAOs) और कार्यकर्ता शामिल हैं, को म्यांमार के भविष्य के राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बनना चाहिए।

भाग II: संघीय लोकतंत्र की राह:[358]

1. राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) लोकतंत्र बहाल होने तक वैध अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी।

2. पीपल्स डिफेंस फोर्सेज (PDFs) लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सैन्य विंग है, जो तात्मादॉ के खिलाफ संघर्ष कर रहा है।

3. NUG उन EAOs के साथ काम कर रहा है, जो दशकों से आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं।

4. एक नया संविधान जातीय समूहों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा, ताकि राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीयकरण हो सके।

5. युद्ध अपराधों और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार सैन्य नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

6. NUG विदेश सरकारों और संयुक्त राष्ट्र से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

FDC म्यांमार के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पिछली कोशिशों से अलग हटकर सैन्य प्रभाव को राजनीति से पूरी तरह अलग

कर देने की मांग करता है। यह म्यांमार की जातीय विविधता को भी स्वीकार करता है और मान्यता देता है कि जातीय समूहों को संघीय प्रणाली के तहत समान अधिकार और स्वायत्तता मिलनी चाहिए। हालांकि चार्टर (FDC) एक अस्थायी संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है और एक राजनीतिक दिशा-निर्देश सामने रखता है।[359] इस चार्टर के तहत राष्ट्रीय एकता परामर्श परिषद (NUCC) और प्रतिनिधि सभा (People's Assembly) को शासन का प्रमुख केंद्र बनाया गया। हालांकि, चार्टर के पहले भाग (Part I) पर व्यापक सहमति बनी, लेकिन दूसरे भाग (Part II) को लेकर मतभेद थे, विशेषकर कुछ जातीय समूहों की ओर से, जिसके चलते इसमें बाद में संशोधन किए गए।[360] जैसे-जैसे लोकतंत्र की बहाली के प्रयास आगे बढ़े, NUCC ने शासन में अधिक समावेशिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

संघीय लोकतांत्रिक चार्टर, म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक बलों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह चार्टर पूरी तरह से विकसित संविधान नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक ढांचा है जिसे विभिन्न प्रतिरोधी समूहों को एकजुट करने के लिए निर्मित किया गया, जिसमें जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs), राजनीतिक दल, सिविल सेवक और सविनय अवज्ञा आंदोलन (CDM) शामिल हैं।[361] हालांकि, NLD और जातीय समूहों के बीच पूर्णरूप से विश्वास की समस्याएं बनी रही।[362] अंतिम रूप से जो चार्टर अब हमारे सामने हैं वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस स्थिति में अंतरिम सरकार के लिए एक लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे की तरह काम करेगा, जब जुंटा का पूरी तरह पतन हो जाएगा। इतना ही नहीं यह चार्टर सभी शामिल धड़ों के लिए बाध्यकारी प्रावधान भी करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह संविधान के पहले का एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ है जो देश के सैन्य शासन से संक्रमण के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।[363] चार्टर के दूसरे भाग में संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि यह चार्टर एक व्यापक 12-चरणीय रोडमैप का हिस्सा है, जिसमें एक संक्रमणकालीन संविधान और एक अंतिम संविधान तैयार करना शामिल है, जब फेडरल डेमोक्रेटिक यूनियन स्थापित हो जाएगा।[364,365] इस 12-चरणीय रोडमैप में स्पष्ट किया गया कि राजनीतिक दलों, जातीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों के बीच सहयोग की आवश्यकता है, ताकि वे राजनीतिक समझौतों पर विचार करें और अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन और

विधायी और न्यायिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार करें। इसी के साथ एक संक्रमणकालीन संविधान का मसौदा तैयार करने और एक संविधान सभा को बुलाकर एक स्थायी संघीय लोकतांत्रिक संविधान बनाने की योजना है।[366] अंत में, रोडमैप में जनमत संग्रह, चुनाव और विधायी, कार्यकारी और न्यायिक निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है, जो कानून के शासन और संविधानवाद को बनाए रखेंगे, जिससे म्यांमार का लोकतांत्रिक संघीय प्रणाली में संक्रमण पूरा होगा।

संघवाद की दुविधा

संघवाद के स्वरूप को लेकर म्यांमार के तमाम धड़ों के बीच बहस पिछले सात दशकों से जारी है। इसमें एक मुद्दा है जातीय राष्ट्रीयता या कहें जातीय आधारित उप-राष्ट्रवाद का भी है और इसीलिए कई जातीय समूह ख़ुद के लिए 'जातीय अल्पसंख्यक' की शब्दावली को नहीं मानती और अधिक स्वायत्तता या विशिष्ट राष्ट्रीय मान्यता की मांग करती हैं।[367] इसके पीछे एक कारण यह भी है कि ये समूह अपने-अपने क्षेत्रों में बहुमत में हैं, लेकिन केंद्रीयकृत शासन संरचना और सैन्य प्रभाव के कारण उनकी राजनीतिक शक्ति सीमित रहती है। 2008 के संविधान ने जातीय राजनीतिक आकांक्षाओं को और गौण बना दिया। 2010 के बाद से हुए चुनावों, विशेष रूप से NLD की जीत, ने लोकतांत्रिक प्रगति को दर्शाया, लेकिन साथ ही जातीय असंतोष भी सामने आया। 2018 के उपचुनावों में जातीय राज्यों में NLD के खराब प्रदर्शन ने इस बात को स्पष्ट किया कि केंद्रीय सरकार और जातीय समूहों के बीच एक बड़ा अंतर है। जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, जहाँ NLD ने उच्च सदन की छह में से पाँच सीटें गंवा दीं। उत्तरी काचिन क्षेत्र में, NLD एक उच्च सदन की दौड़ में तीसरे स्थान पर रही, जबकि यह सीट 2015 में एनएलडी ने जीती थी।[368]

भाषा और धर्म भी म्यांमार के संघवाद को प्रभावित करते रहे हैं। बर्मी (बर्मीज़) आधिकारिक भाषा है, लेकिन कई जातीय समुदाय अपनी विशिष्ट भाषाएँ बोलते हैं जिन्हें आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। बौद्ध धर्म, जिसे लगभग 88% जनसंख्या मानती है, एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है,[369] लेकिन यह गैर-बौद्ध जातीय अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से चिन, काचिन और

कयाह राज्यों में रहने वाले ईसाइयों और रखाइन राज्य में रहने वाले मुसलमानों के लिए हाशिए की स्थिति पैदा करता रहा है।

1947 के पांगलोंग समझौते से लेकर 2021-22 तक म्यांमार एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की तलाश में जुटा है, जो समावेशिता की दुविधा को खत्म कर दे। सेना के वर्चस्व से अलग बुनियादी बात यह है कि सेना अपने आप को देश की एकजुटता के लिए ज़रूरी मानती है।[370] जैसे कि इतिहास बताता है कि 1958 में नागरिक सरकार ने देश का शासन खुद ही सेना के हाथ में यह समझते हुए सौंप दिया था कि वह देश में जारी अस्थिरता को संभाल नहीं सकता। तब सेना को जनता का समर्थन भी मिला था।[371] विभिन्न जातीयों के बीच में टकराव, जातीय समूहों का सेना से टकराव, लोकतंत्र परस्तों का आपस में टकराव, यहां तक कि 2021 की तख्तापलट के बाद बने अस्थाई संघीय लोकतांत्रिक चार्टर के प्रावधानों को लेकर NLD, सांसदों, लोकतंत्र समर्थकों और कुछ जातीय समूहों के बीच मनमुटाव इस बात को मुखर रूप से सामने रखते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे को लेकर विचारों का एक जबरदस्त विरोधभास मौजूद है।[372] संघीय संरचना के अपनी अपनी परिभाषाओं की गुत्थी हैं जो म्यांमार के राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी हावी है और यह दुविधा जुंटा की वर्चस्ववादी मानसिकता के लिए भी फायदेमंद है।

यह कहना सही होगा कि म्यांमार में संघवाद (फेडरलिज्म) की अवधारणा लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रही है, जो देश की जटिल इतिहास, जातीय विविधता, राजनीतिक संघर्ष और सैन्य वर्चस्व से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक रूप से, संघवाद जातीय अल्पसंख्यक समूहों, जैसे कि काचिन, करेन और शान, की एक प्रमुख मांग रही है,[373] जो ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने, स्थायी शांति स्थापित करने और स्थानीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए अधिक स्वायत्तता और स्व-निर्णय की मांग करते रहे हैं।[374] हालांकि, सेना ने लगातार इन मांगों का विरोध किया है, क्योंकि वह संघवाद को राष्ट्रीय एकता और अपने स्थापित वर्चस्व के लिए खतरा मानती रही है। 2008 का संविधान ने एक बहुत ही केंद्रीकृत शासन संरचना को स्थापित किया, जो सेना के वर्चस्व को बनाए रखते हुए जातीय राज्यों को केवल सीमित स्वायत्तता प्रदान करता है।[375]

2021 के सैन्य तख्तापलट ने संघवाद पर बहस में एक नाटकीय मोड़ ला दिया, इसे एक दीर्घकालिक राजनीतिक आकांक्षा से एक तत्काल और जरूरी मुद्दे में बदल दिया। तख्तापलट के बाद, संघवाद के दो स्पष्ट रूप से अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं: एक सैन्य जुंटा द्वारा थोपा गया और दूसरा विपक्षी ताकतों, जैसे कि NUG और विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) द्वारा समर्थित।[376] सेना के संघवाद का दृष्टिकोण, जिसे "अनुशासित संघीय लोकतंत्र" के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो एक नियंत्रित और केंद्रीकृत मॉडल है, जिसका मकसद ही सेना की राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।[377] इसके साथ ही जुंटा ने अपने शासन को सही ठहराने और कुछ जातीय समूहों के साथ चुनिंदा तौर पर जुड़ने के लिए संघवाद को जुमले की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन साथ ही दूसरे समूहों के खिलाफ हिंसक सैन्य अभियान भी चलाए हैं। यह दृष्टिकोण 2008 के संविधान में झलकता है, जो राष्ट्रीय मामलों पर सेना के अंतिम अधिकार को सुनिश्चित करता है, भले ही यह औपचारिक रूप से राज्य और क्षेत्रीय सरकारों के अस्तित्व को स्वीकार करता हो।

इसके विपरीत, विपक्ष का संघवाद का दृष्टिकोण लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और जातीय राज्यों को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने पर आधारित है। NUG, EAOs और सिविल सोसाइटी समूहों ने सेना के केंद्रीकृत मॉडल को खारिज कर दिया है और इसके बजाय एक नए संघीय व्यवस्था की वकालत की है जो सभी जातीय समूहों के समान अधिकारों को मान्यता देती है। इस दृष्टिकोण को मार्च 2021 में जारी फेडरल डेमोक्रेसी चार्टर में औपचारिक रूप से व्यक्त किया गया था,[378] जो 2008 के संविधान को समाप्त करने और संघीय सिद्धांतों पर आधारित एक नए राजनीतिक ढांचे की स्थापना का आह्वान करता है। विपक्ष का मॉडल केंद्र सरकार से सत्ता को विकेंद्रित करने, जातीय क्षेत्रों के लिए स्व-शासन सुनिश्चित करने और समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।[379] तख्तापलट के बाद से इस दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है, क्योंकि कई EAOs जो पहले सेना के साथ युद्धविराम में थे, व्यापक प्रतिरोध आंदोलन के साथ जुड़ गए और तख्तापलट को सेना के वर्चस्व से मुक्त होने और एक वास्तव में समावेशी संघीय व्यवस्था स्थापित करने का अवसर मानने लगे हैं।

विरोधाभासों का भंवर और राजनीतिक सुधार का भविष्य

यदि हम फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद के म्यांमार की बात करें, तो कई ज्वलंत प्रश्न हैं, जैसे कि जातीय सशस्त्र समूहों (EAOs) और पीपल्स डिफेंस फोर्सेज (PDFs) के पास म्यांमार के भविष्य के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं और सत्ता साझा करने और विचारधारात्मक स्थितियों को संयमित करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। EAOs का लक्ष्य मुक्ति और स्व-शासन प्राप्त करना है, जबकि PDFs आंग सान सू ची के नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने की आकांक्षा रखते हैं।[380]

इस गृहयुद्ध में जुंटा के खिलाफ दोनों धड़े संघर्ष तो साथ रहे हैं लेकिन कई संकेत और विशेषज्ञ बताते हैं उनके अंतिम लक्ष्य काफी अलग है। EAOs का उद्देश्य अपने मातृभूमि को मुक्त करना और अपनी स्वयं की सरकार स्थापित करना है, जबकि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) का लक्ष्य उनकी पूर्व नेता आंग सान सू ची के नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करना है।[381]

इन मुद्दों के बावजूद, 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद NLD और कुछ जातीय समूहों जैसे लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा एक प्रक्रिया शुरू की गई, जिसने 'स्प्रिंग रिवोल्यूशन' (वसंत क्रांति) के रूप में जानी जाने वाली परिवर्तन की धारा को जन्म दिया।[382] इस प्रक्रिया को और संगठित करते हुए नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल (NUCC) ने अप्रैल में एक नए फेडरल डेमोक्रेसी चार्टर (संघीय लोकतंत्र चार्टर) को अनुमोदित और प्रकाशित किया। इस चार्टर की घोषणा ने सैन्य शासन के खिलाफ प्रतिरोध और म्यांमार की राजनीति को पुनर्निर्मित करने के प्रयासों में एक नए चरण की शुरुआत की।[383] यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जुंटा के पतन के बाद की स्थितियों में अंतरिम संवैधानिक प्रावधानों, संविधान निर्माण के प्रयासों और प्रक्रिया और दूसरी कानूनी और संघीय राजनीतिक के व्यवहारिक स्वरूप को मूर्त रूप देना था।[384]

लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नागरिकों की आकांक्षाओं को जताने का एक प्रमुख साधन होते हैं, लेकिन म्यांमार की स्थिति में चुनावी प्रक्रिया कई जटिलताओं और विरोधाभासों से भरी हुई है। म्यांमार में सैन्य शासन द्वारा 2025 में प्रस्तावित चुनाव लोकतंत्र की स्थापना करने के बजाय 2008 के

संविधान के उन तत्वों को मज़बूती देते हैं जो सेना के राजनीतिक दखल को बनाए रखते।[385] यह संविधान सेना को संसद में एक तरह वीटो की शक्ति देता है इसके साथ ही सैन्य समर्थित राजनीतिक दलों के निर्णायक स्थिति को भी बनाए रखता है,[386] जिससे यह सत्ता संरचना में सेना के प्रभुत्व को कायम रखता है। यही वजह है कि मौजूदा संविधान संघीय लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में विफल रहा है, जो जातीय समूहों और लोकतंत्र समर्थक ताकतों के बीच असंतोष का एक बड़ा कारण बना हुआ है।

मोटे तौर देखें तो म्यांमार का गृहयुद्ध तीन प्रमुख पक्षों के बारे में है, जिसमें सैन्य जुंटा, लोकतंत्र समर्थक ताकतें, और जातीय सशस्त्र संगठन (EAOs) हैं। प्रत्येक समूह देश के भविष्य की राजनीतिक संरचना में अपनी स्वायत्त स्थिति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, म्यांमार ने विभिन्न संवैधानिक परिवर्तन देखे हैं, जिनमें 1948 का संसदीय संविधान, 1974 का समाजवादी संविधान, और 2008 का संविधान शामिल हैं। 1948 के संविधान के अलावा बाकी के दोनों संविधान सेना की निगरानी में एक छद्म लोकतंत्र की स्थिति को स्थापित करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया। इन संविधानों में से किसी ने भी एक व्यापक रूप से समावेशी राजनीतिक ढांचा स्थापित करने की कोशिश नहीं की या फिर वो इसमें विफल ही रहा।

हालांकि, सैन्य शासन और लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों के बीच विभाजन स्पष्ट है, लेकिन इसके साथ साथ, सेना विरोधी विपक्षी समूह भी संघवाद और राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा को लेकर आंतरिक मतभेदों से जूझते रहे हैं। NLD नेतृत्व वाली NUG और EAOs दोनों ही सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक लक्ष्यों में स्पष्ट अंतर है।[387] मुख्य विवाद इस बात को लेकर है कि क्या म्यांमार को एक केंद्रीकृत लोकतंत्र के रूप में संघीय तत्वों के साथ पुनर्गठित किया जाए, या इसे वास्तविक विकेंद्रीकृत संघीय राज्य के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें जातीय अल्पसंख्यकों को आत्म-शासन और स्वतंत्र प्रशासन का अधिकार मिले? इस दृष्टिकोण में अंतर के कारण विरोधी ताकतों के बीच एकता स्थापित करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रही हैं, ऐसे में आशंका है कि सैन्य शासन के विरुद्ध संगठित विरोध एक समय के बाद कमजोर हो सकता है।

2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद, स्प्रिंग रिवोल्यूशन (वसंत क्रांति) की शुरुआत हुई, जिसमें लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता, पूर्व और मौजूदा NLD सदस्य और जातीय समूह शामिल हुए।[388] इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल (NUCC) द्वारा अप्रैल 2021 में लिया गया, जब इसने संघीय लोकतंत्र चार्टर को मंजूरी दी। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, NLD-नेतृत्व वाले NUG और EAOs के बीच गहरे वैचारिक मतभेद लगातार बाधा बने रहे।[389]

जातीय समूहों को संदेह रहा कि यदि एक बर्मी-बहुसंख्यक सरकार सत्ता में आती है, तो वह वास्तविक संघीय सुधारों को लागू करने में रुची नहीं लेगी। इसके उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी (UWSA) और अराकान आर्मी (AA) जैसे कई EAOs हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्थाएँ स्थापित किए। NUG और EAOs के बीच इस अविश्वास के कारण EAOs ने पूर्ण समर्थन देने में पूर्व में हिचकिचाहट दिखाती रही है।[390]

संघवाद और लोकतंत्र को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण

पीपल्स डिफेंस फोर्सेज (PDFs), जो प्रतिरोध की एक सशस्त्र शाखा के रूप में उभरी, म्यांमार के राजनीतिक परिदृश्य में एक और परत जोड़ती है। हालांकि PDFs और EAOs दोनों ही सैन्य शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं,[391] लेकिन संकेत बताते हैं कि उनके भविष्य के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। सैन्य जुंटा ने इन आंतरिक विभाजनों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक वार्ताएं की हैं, पूर्व में कुछ जातीय समूहों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है, जबकि अन्य के खिलाफ हिंसक सैन्य अभियानों को तेज कर दिया। इस "विभाजन और शासन करो" की रणनीति ने सैन्य शासन के खिलाफ संगठित और समन्वित प्रतिरोध को कमजोर ही किया है।[392] सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो EAOs "नीचे से ऊपर" (Bottom-Up) शासन प्रणाली व्यवस्था का समर्थन करते रहे हैं,[393] जहां सत्ता का ढांचा स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं से शुरू होता है और केंद्रीय सरकार को उनकी स्वायत्तता में न्यूनतम हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है।[394] उनके लिए संघवाद "जातीय समानता" और "आत्म-निर्णय" के अधिकार प्राप्त करने लक्ष्य है। वहीं, NLD और NUG

"ऊपर से नीचे" (Top-Down) शासन प्रणाली व्यवस्था का समर्थन करते हैं,[395] जिसमें राज्यों को कुछ स्वायत्तता दी जाती है, लेकिन वे एक शक्तिशाली केंद्रीय राजनीतिक तंत्र के अधीन रहते हैं। कई EAOs को लगता रहा है कि NLD की संघीय नीति केवल एक राजनीतिक रणनीति है, जिसमें वास्तविक स्वायत्तता का कई स्तरों पर अभाव है। इसीलिए वे NUG को पूरी तरह से समर्थन देने में हिचकिचाते रहे हैं।

EAOs और NLD के बीच अविश्वास का भी इतिहास काफी लंबा है। यह इतिहास दशकों पुराने राजनीतिक और सामाजिक तनावों से उपजा है। 1947 के पांगलोंग समझौते में जातीय समूहों को स्वायत्तता का वादा किया गया था, लेकिन इस समझौते को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।[396] इसके परिणामस्वरूप, जातीय समूहों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। 2016 से 2020 तक NLD के शासनकाल के दौरान, जातीय समूहों को यह महसूस हुआ कि उन्हें नीति-निर्माण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। NLD ने मुख्य रूप से सेना के साथ संबंध सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे जातीय समूहों को लगा कि उनकी आवाज़ों और चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। इसके अलावा, NLD ने संघीय सुधारों को लागू करने में धीमी गति दिखाई, जिससे जातीय समूहों के बीच यह संदेह और गहरा हो गया कि बर्मी-बहुसंख्यक सरकार कभी भी उनके स्वायत्तता के अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता नहीं देगी।[397]

म्यांमार के कई जातीय समूहों ने NLD की संघवाद की नीतियों को लेकर मतभेद ज़ाहिर करते रहे हैं, मुख्य रूप से केंद्रीकरण (centralization) की प्रवृत्ति और राजनीतिक प्रक्रिया में वास्तविक समावेशन (inclusion) की कमी को लेकर। जातीय सशस्त्र संगठन (EAOs), जैसे कि करेन नेशनल यूनियन (Karen National Union - KNU) और शान राज्य की पुनर्स्थापना परिषद (Restoration Council of Shan State - RCSS), खुद को NLD की नीतियों की वजह में हाशिए पर महसूस करते रहे हैं।[398] आलोचना का एक मुख्य बिंदु NLD की शांति प्रक्रिया भी रही, विशेष रूप से राष्ट्रव्यापी संघर्षविराम समझौता (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA), समावेशी नहीं थी। कई EAOs, जैसे कि काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गनाइज़ेशन

(KIO), ने NCA में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह उनके हितों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करता।[399] इसके अलावा, NLD सरकार की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और EAOs के साथ सार्थक बातचीत करने की अनिच्छा ने इन समूहों को और अधिक अलग-थलग कर दिया। इन परिस्थितियों ने जातीय समूहों में एक तरह की हताशा को जन्म दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि KNU और RCSS ने दिसंबर 2018 में शांति प्रक्रिया से पीछे हट गए। दोनों संगठनों ने अपने इस फैसले के पीछे यह तर्क दिया कि उप-राष्ट्रीय यानी क्षेत्रिय स्तर के मुद्दों और चिंताओं को संघीय (यूनियन-लेवल) की शांति वार्ताओं में शामिल नहीं किया गया।[400] इसके अलावा, कई जातीय नेताओं ने NLD की उन मुद्दों को लेकर आलोचना की, जिसमें कहा गया कि NLD ने म्यांमार के स्टेट और अलग अलग जातीय समाजों के बीच के संघर्ष के लिए, एक संघीय समाधान खोजने की उनकी मांगों को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया।

2021 के सैन्य तख्तापलट ने इन राजनीतिक विभाजनों को और भी गहरा कर दिया। सैन्य शासन के बाद, EAOs (जातीय सशस्त्र संगठनों) ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया। इससे "नीचे से ऊपर संघवाद" का एक नया दृष्टिकोण उभरने लगा,[401] जिसमें जातीय समूहों ने अपने क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा दिया। वहीं, NLD-नेतृत्व वाला NUG (राष्ट्रीय एकता सरकार) खुद को देश की वैध सरकार मानता है। हालांकि, EAOs को यह डर है कि यदि NUG सत्ता में आती है, तो यह फिर से बर्मी-बहुसंख्यक शासन को स्थापित करेगा और जातीय समूहों के हितों को पीछे धकेल देगा। इस प्रकार, म्यांमार का भविष्य अभी भी संघवाद, जातीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक शासन के बीच उलझा हुआ है। यह स्थिति देश के राजनीतिक संकट को और भी गहरा बना रही है, जिससे शांति और स्थिरता की राह और भी कठिन होती जा रही है।

सेना और राजनीति

फरवरी 2021 की तख्तापलट के बाद 2024 तक सैन्य शासन ने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के ले सात बार आपातकाल का विस्तार किया। लेकिन 2024 की शुरुआत में जुंटा ने 2025 के अंत तक राष्ट्रीय चुनाव कराने की अपनी पुरानी

घोषणा को दोहराया, जिसे औपचारिक रूप से नागरिक शासन की बहाली के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया। 2008 के संविधान के अनुरूप, इसके लिए आवश्यक था कि चुनाव से छह माह पूर्व आपातकाल की समाप्ति हो और सत्ता एक अंतरिम सरकार को हस्तांतरित की जाए। जुलाई 2025 के अंतिम दिनों में, जनरल मिन आंग ह्लाइंग के नेतृत्व वाले प्रशासन ने आपातकाल का खात्मा कर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल (SAC) को भंग कर दिया गया, और शासन को पुनर्गठित कर एक तथाकथित "अंतरिम सरकार" के रूप में स्थापित किया गया।[402] जबकि वास्तविक सत्ता अब भी सैन्य नेतृत्व के हाथों में ही केंद्रित रही, क्योंकि इस अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति, खुद सेना प्रमुख जनरल ह्लाइंग ही हैं और नई दस-सदस्यीय केयरटेकर आयोग के आधे सदस्य शीर्ष सैन्य जनरल ही हैं (जिनमें सेना के उप प्रमुख और क्षेत्रीय कमांडर शामिल हैं)।[403] इस संरचनात्मक परिवर्तन के साथ नए कानून भी पारित किए गए, जिनमें *'कठोर चुनाव कानून'* जिसके तहत मतदान की किसी भी प्रकार की "अवरोधक गतिविधि" को अपराध घोषित कर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है।[404] इसी के साथ, एक *साइबर कानून* जिसके अंतर्गत VPN के प्रयोग और लक्षित सोशल मीडिया सामग्री को दंडनीय बनाया गया है।[405] अंतरिम सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद, जुंटा ने अनेक जातीय-बहुल टाउनशिपों में फिर से मार्शल लॉ और आपातकाल लागू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सुरक्षा नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथ में ही रहेगी।[406] इस पुनर्गठन के पीछे अनेक आंतरिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखते हैं, जिसमें संविधान के प्रावधानों का हवाला देकर शासन यह दावा कर सकता है कि वह एक "अंतरिम संरक्षक" (caretaker) है, जो देश में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करेगा।

इसके साथ ही राजनीतिक स्तर पर सभी महत्त्वपूर्ण विपक्षी दलों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। अधिकांश एनएलडी नेता (आंग सान सू ची सहित) या तो कैद में थे या राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए। मीडिया की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई और 2023 व 2024 में पारित नए सुरक्षा क़ानूनों ने शासन को किसी भी विरोधी को प्रतिबंधित करने या कारावास में डालने का व्यापक अधिकार दे दिया है। तख्तापलट के समय म्यांमार में 90 राजनीतिक दल थे। हालांकि, जुंटा द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण कानून में किए गए संशोधनों के कारण, 40 दलों की वैधता को ही भंग कर दिया गया, जिनमें NLD के

साथ-साथ और दूसरे लोकतंत्र समर्थक समूह भी शामिल थे।[407] 2024 के अंत तक केवल 53 राजनीतिक दल की ही वैधता ही बची रही या दूसरे शब्दों में कहें वो आधिकारिक रूप से पंजीकृत वैध दल हैं, जिनमें से अधिकांश सैन्य समर्थित राजनीतिक दल हैं।[408] 2023 में, म्यांमार के सैन्य-नियंत्रित यूनियन इलेक्शन कमीशन (UEC) ने एक कड़े नए चुनावी पंजीकरण कानून लागू किए, जो सैन्य-समर्थित दलों को फायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए थे। इन कानूनों के तहत, राजनीतिक दलों को 90 दिनों के भीतर 1,00,000 सदस्य जोड़ने और देश के कम से कम आधे टाउनशिप में कार्यालय खोलने की शर्तें पूरी करनी थीं।[409] यह एक लगभग असंभव सी प्रक्रिया थी। नतीजतन, 28 मार्च 2023 को UEC ने औपचारिक रूप से NLD और 39 अन्य राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि ये दल "स्वतः अस्तित्वहीन हो गए हैं"।[410]

यह स्पष्ट दिखता है कि म्यांमार की सेना येन-केन-प्रकारेण राजनीति को राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों है?

तात्मदॉ की पहचान मुख्य रूप से उसकी शुरुआत की कहानी और राज्य-निर्माण में अपनी भूमिका को लेकर बनाई गई धारणा से जुड़ी है। म्यांमार की सेना आज़ादी से पहले के औपनिवेशिक-विरोधी आंदोलन से निकली और स्वतंत्रता मिलने के शुरुआती सालों के नाज़ुक दौर में अपनी ताक़त को मज़बूत करती गई। उसने अपने को सिर्फ़ सीमाओं की रक्षा करने वाला बल नहीं, बल्कि पूरे संघ का निर्माता और रक्षक माना। इसकी विचारधारा में "तीन राष्ट्रीय कारण," संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता को केवल नारे नहीं, बल्कि ज़मीनी कामकाज की ज़रूरी शर्तें माना जाता है। इन संदेशों को सैनिक प्रशिक्षण, आंतरिक नियमों की रूपरेखा और प्रचार के औज़ारों के ज़रिए बार-बार मजबूत किया गया और सैन्य संरचना का अटूट हिस्सा बनाया गया है।

तात्मदॉ के नज़रिए में राजनीति से पीछे हटना केवल सत्ता का कम होना नहीं है, बल्कि राज्य के अस्तित्व और सेना की वैधता के लिए सीधा ख़तरा है। यह सोच इस विचार से जुड़ी है कि म्यांमार जैसा बहु-जातीय, बंटा हुआ और विवादों से घिरा देश स्वभाव से अस्थिर है, और केवल एक अनुशासित और सख़्त संस्था ही इसे टूटने से बचा सकती है।[411] अपने को भाषाओं, क्षेत्रों और सशस्त्र समूहों

को जोड़ने वाली ताक़त मानकर तात्मदॉ खुद को ऐसे तत्व के रूप में देखता है जिसकी जगह कोई दूसरी संस्था नहीं ले सकती है।[412] जन आंदोलनों, चुनावों में हार या अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बावजूद यही विश्वास उसकी राजनीति पर पकड़ को सही ठहराती भी रही है।[413] इस तरह, ऐतिहासिक भूमिका, संस्थागत प्रशिक्षण और हर वक्त मिशन की स्थायी भावना मिलकर तात्मदॉ की भूमिका को म्यांमार की राजनीति के केंद्र में बनाए रखती आई है।

जैसा के पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि 2008 का संविधान म्यांमार की राजनीति तंत्र में सेना को स्थायी हिस्सा बना देता है क्योंकि सेना के लिए संसद की 25 प्रतिशत सीटें तय की गई हैं। इतना ही नहीं सरकार के तीन अहम मंत्रालयों – रक्षा, गृह और सीमा मामले – सेना के हाथों में आरक्षित रखने का प्रावधान भी है।[414] इसका मतलब यह है कि सेना की म्यांमार की सेना को राजनीतिक तंत्र में सिर्फ़ अस्थायी हिस्सेदारी नहीं, बल्कि स्थायी संवैधानिक ताक़त देता है। चूँकि संविधान में बदलाव के लिए तीन-चौथाई से ज़्यादा बहुमत चाहिए, इसलिए अकेले सेना का 25 प्रतिशत हिस्सा किसी भी सुधार को रोकने के लिए काफी है।[415] सरल शब्दों में कहें तो जनता के द्वारा सीधी चुनी गई सरकार भी संविधान में बदलाव नहीं कर सकती, जब तक कि उसे सेना का समर्थन न हासिल हो। रक्षा, गृह और सीमा मामले के मंत्रालयों पर सीधा अधिकार[416] होने से सेना के पास पुलिस, खुफिया तंत्र, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं का सीधा नियंत्रण रहता है।[417] यानी राजनीति को आकार देने और विरोध को नियंत्रित करने वाले सभी साधन उस वक्त भी सेना के हाथों में रहेंगे, जब चुनावों से कोई लोकतांत्रिक सरकार सरकार चला रही होगी। संविधान का राजनीतिक तानाबाना ही इस व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, जिससे सेना के लिए राजनीति में बने रहना स्वाभाविक हो जाता है। म्यांमार के 2008 के संविधान का अनुच्छेद 445[418] भी यहां बेहद ख़ास हो जाता है क्योंकि यह अनुच्छेद, सेना के जवानों और अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए पूरी तरह से छूट देता है। इसका मतलब है कि सैनिकों और अधिकारियों पर ऐसे कार्यों के लिए नागरिक अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह सुरक्षा व्यवस्था सेना को मानवाधिकार उल्लंघन और अन्य अत्याचारों की कानूनी जिम्मेदारी से बचाती है। जवाबदेही को रोककर यह प्रावधान सेना के भीतर दण्डहीनता की गहरी संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसका एक मतलब यह भी है कि अगर सेना

सत्ता के राजनीतिक तंत्र से बाहर जाती है तो उनके अधिकारियों और संस्थागत हितों को नागरिक निगरानी या कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। यह स्पष्ट है कि 2008 का प्रभावी संविधान सेना को ऐसे कानूनी और संस्थागत औज़ार देते हैं, जिससे वह कानून तोड़े बिना भी राजनीति पर पकड़ बनाए रख सकती है। जैसे, संवैधानिक धाराओं या आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके असंवैधानिक दखल को वैध ठहराना, अपने मंत्रालयों के ज़रिए सुरक्षा और प्रशासनिक हालात पर प्रभाव डालना, या फिर अस्थायी सरकारें, नियंत्रित चुनाव और कानूनी सुधार लाकर लोकतांत्रिक दिखावा करना, जबकि असली ताक़त अपने पास रखना।

तात्मदॉ का बड़े कारोबारी समूहों पर नियंत्रण उसकी स्वतंत्र ताक़त को अपने हाथों में बनाए रखती आई है। दरअसल, सेना इन समूहों, खनिज-संसाधनों के ठेकों और सेवाओं पर एकाधिकार के ज़रिए लगातार आर्थिक लाभ करती है।[419] यह आर्थिक संसाधन सेना में पेंशन, रसद, हथियार ख़रीदने और सेना संचालन के खर्च जैसे कामों पर लगाया जाता है और इसकी कोई सीधी जवाबदेही संसद या सरकारी बजट के ज़रिए नहीं होती।[420] यह आमदनी केवल सेना को चलाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अफ़सरों, रिटायर्ड अधिकारियों और उनसे जुड़े हुए व्यापारियों के बीच बाँटी जाती है।[421] इससे ऐसे आर्थिक रिश्ते और निष्ठा बनती हैं, जो सेना के अंदर अनुशासन और राजनीतिक वफ़ादारी को मजबूत करते हैं। इस व्यवस्था में राजनीति पर सीधा कब्ज़ा और भी मज़बूत होता है, क्योंकि राजनीतिक ताक़त से सेना को ठेके, अलग-अलग तरह के लाइसेंस जैसे अनुमतियां और नियामक सुविधाएँ मिलती हैं। यह स्पष्ट है कि अगर सेना राजनीतिक तंत्र से दूर होती है तो संस्थागत रूप से जो आर्थिक संसाधन सेना के संचालन और व्यक्तिगत लाभ के लिए पहुंचते हैं वह या तो खत्म हो जाएगी या बेहद सीमित हो जाएगी।

पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि कैसे 2021 के तख्तापलट के बाद NUG की पीपुल्स डिफेंस फ़ोर्स (PDFs) के उभरने के बाद कई जातीय संगठन दोबारा नई ऊर्जा के साथ नए-नए बने स्थानीय मिलिशियाओं के साथ मिलकर केंद्रीय सैन्य सत्ता के खिलाफ सक्रिए हो गए।[422] इससे पहले जो विद्रोह अलग-अलग इलाकों तक सीमित थे, वे अब पूरे देश में फैलकर एक बड़ा वैकल्पिक तंत्र बना

चुके हैं।[423] यह परिस्थिति सेना के उस तर्क को और भी मज़बूत करता है कि उनका सीधा राजनीतिक नियंत्रण ज़रूरी है और इस संघर्ष के लिए राजनीति ही वो रास्ते हैं जो ऐसे संसाधन मुहैया करा सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर दमनकारी कार्रवाइयाँ चलाई जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में सेना के नज़रिए को भी रेखांकित करना ज़रूरी है।[424] यह नज़रिया वह है जहां सेना के कमांडर राजनीति को युद्धक्षेत्र के चश्मे से देखते हैं, वे शासन और सुरक्षा अभियानों को एक ही सिलसिले का हिस्सा मानते हैं। सेना का नज़रिया कहता है कि राजनीतिक तंत्र से दूर हटना, विद्रोहियों को जगह देने के जैसा है, जबकि राजनीतिक सत्ता बनाए रखना या उसे फिर से हासिल करना एकीकृत राज्य बनाने का व्यावहारिक (और ज़रूरी) तरीका है।[425,426] इसी से पता चलता है कि क्यों सेना, युद्ध क्षेत्र में भारी कीमत चुकाने और अंतरराष्ट्रीय अलगाव झेलने के बावजूद, रणनीतिक संकट के समय बार-बार सीधे शासन में लौट आती है।

संरचनात्मक रूप से म्यांमार सेना का विशलेषण करें तो यह पता चलता है कि यहां पदोन्नति प्रणाली, पेशेवर-लाभ और कारोबारी संस्थानों पर नियंत्रण एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जिसमें सैन्य अधिकारियों का निजी हित सेना की सत्ता से जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, सेना की सालों से चली आ रही संगठनात्मक प्रक्रिया इस बात पर बल देती है कि निजी हित, सेना का राजनीति से जुड़ाव पर काफी हद तक निर्भर है। संगठनात्मक प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण और पेशेवर संस्कृति से जुड़ी है, जो उनके सामने एक ऐसा गढ़ा हुआ सच सामने रखता, जो यह बताता है कि उनकी दुनिया और अस्तित्व लगातार ख़तरों से घिरा हुआ है। यह ख़तरे, आतंरिक और विदेश दखल तक जाता है, जो किसी भी समय देश में 'अराजकता' की स्थिति पैदा कर सकता है, इसीलिए राजनीतिक तंत्र में हस्तक्षेप वैध और ज़रूरी कदम है।[427] इन ढांचागत प्रक्रियाओं के साथ-साथ कई कानूनी कार्रवाईयों की भी सेना को आशंका बनी रहती है। सेना के वरिष्ठ कमांडर यह मानते रहे हैं कि अगर वे सत्ता छोड़ देंगे तो उनके पास मौजूद कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी और वे मानवाधिकार उल्लंघनों—जैसे रोहिंग्या पर कार्रवाई या तख्तापलट के बाद की मानवाधिकार उल्लंघन की ज्यादतियों, के लिए घरेलू या अंतरराष्ट्रीय जांच और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।[428,429] इस तरह भौतिक स्वार्थ, विचारधारात्मक खतरे की धारणा और कानूनी कार्रवाई से बचने

की प्रवृत्ति मिलकर एक ऐसी नेतृत्व शैली का निर्माण करते हैं, जो बेहद सतर्क, बदलावों का दमन करने वाली प्रक्रियाओं का सहारा लेने में नहीं हिचकती है।

यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले करीब सात से ज्यादा दशकों में म्यांमार की सेना ने अपने आप को केवल एक सुरक्षा संस्था के बजाय एक राजनीतिक शक्ति भी बना दिया है। सेना के अफसर बड़ी संख्या में वरिष्ठ सिविल पदों, सरकारी कंपनियों और राजनीतिक दलों में शामिल हो जाते हैं, जिससे वर्दी और सिविल सेवा के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और नागरिक नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है।[430] मंत्रालयों, नौकरशाही और आर्थिक संस्थानों में अक्सर सेना से जुड़े लोग ही होते हैं। इस प्रक्रिया की वजह से शासन की सोच आशंकाओं और किसी भी बदलाव से अपने को सुरक्षित रखने पर केंद्रित हो जाती है और जब राजनीतिक और नागरिक संस्थाएं विचाराधात्मक रूप से कमज़ोर होंगी तो सेना पर निगरानी करने वाली औपचारिक व्यवस्थाएँ अपने आप ही कमजोर हो जाएगी।

आज म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच सीधा टकराव है और मोटे तौर से यही टकराव एक संरचनात्मक संघर्ष की नींव भी रखता आया है। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था सेना के पास प्रभावी रूप से वीटो का अधिकार (अस्वीकृति का अधिकार) है। लोकतांत्रिक सोच वाले लोग इसे अधिनायकवादी शासन की कानूनी जड़ मानते हैं और इसे बदलना ही सबसे ज़रूरी सुधार मानते हैं। इसी के साथ, कई जातीय और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि सिर्फ औपचारिक लोकतंत्र काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ नए तरह का क्षेत्रीय समझौता होना चाहिए, यानि सच्चे संघवाद या विकेन्द्रीकृत शासन की व्यवस्था। जिस व्यवस्था में म्यांमार की जातीय-भाषाई विविधता और लंबे समय से सक्रिय सशस्त्र समूहों की राजनीतिक मांगों को प्रभावी जगह मिल सके।

तत्मादॉ के राजनीतिक प्रभुत्व पर अड़े रहने को एक सुनियोजित, लेकिन स्वार्थपूर्ण तर्क के रूप में समझा जा सकता है, जो विचारधारा, कानून, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सत्ता-सुरक्षा को जोड़कर उसके प्रासंगिक बने रहने की रणनीति बनाता है। विचारधारा के स्तर पर सेना खुद को राष्ट्रीय एकता की अनिवार्य संरक्षक मानती है और राजनीतिक रूप से पीछे हटने को राज्य की अखंडता और उसकी संस्थागत

भूमिका के लिए खतरा मानती है। रणनीतिक स्तर पर, लगातार जारी जातीय विद्रोह और 2021 के बाद चल रहे व्यापक गृहयुद्ध, सेना को केंद्रीकृत सत्ता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी तर्क मुहैया कराते हैं। इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखें तो सेना के दृष्टिकोण से प्रभुत्व बनाए रखना तर्कसंगत लगता है, क्योंकि इससे उसकी पहचान, संसाधन और अधिकार सुरक्षित रहते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक और बहुलतावादी नजरिए से यही तर्क निरंकुशता को बनाए रखता है, राज्य की वैधता को नागरिकों की नजर में कम करता है और जिन संघर्षों को खत्म करने का दावा करता है, उन्हें और बढ़ा देता है। इस तरह सेना का खुद को "राष्ट्र को जोड़ने वाला गोंद" मानना वास्तव में म्यांमार की राजनीतिक टूटन को गहराता है, न कि उसे भरता है।

निष्कर्ष: तलाश जारी है...

म्यांमार में समावेशी राजनीतिक ढाँचे की संरचना और निर्माण की प्रक्रिया के पूरा नहीं हो पाने के पीछे मोटे तौर पर कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ या वर्चस्वशाली वर्गों - व्यक्तियों के फैसले लग सकते हैं, लेकिन यहां बुनियादी रूप से अलग-अलग समूहों के बीच भरोसे, सहयोग और लचीली नीतियों की कमी स्पष्ट रूप से सामने आती है। रणनीतिक स्तर पर जब भी व्यापक राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई, वह हमेशा एकतरफ़ा सोच, केंद्रीकृत सत्ता की लालसा और सत्ता में भागीदारी को सीमित रखने की वजह से ही विफल रही है। समावेशी भागीदारी के लिए केवल क़ानूनी प्रावधान ही नहीं, बल्कि इसके लिए विकेंद्रीकरण और साझा शासन की प्रथाएं भी ज़रूरी हैं, जो अब तक बहुसंख्यक हितों के दबाव और केंद्रीय नियंत्रण छोड़ने की अनिच्छा के कारण संभव नहीं हो पाई। लगातार संवाद और समझौते की संस्कृति न होने से ऐसे संस्थागत ढाँचे नहीं बन सके, जो अल्पसंख्यकों के हितों को न्यायापूर्ण जगह दे सकें और संघीय ढाँचे या बहुलतावाद की दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इसके अलावा, संस्थाओं की अपनी संरचनात्मक कमी और दूरदृष्टि वाले नेतृत्व का अभाव, नीतियों को बिखरा हुआ और अप्रभावी बना देता है।

म्यांमार की आज़ादी के बाद से ही हर सरकार ने राष्ट्रीय एकता और केंद्रीकृत ताक़त को सबसे बड़ा लक्ष्य माना और इस प्रक्रिया में ऐसे संवैधानिक और संस्थागत सुधारों को नज़रअंदाज़ कर दिया, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार और संघीय ढाँचे की स्वतन्त्रता सुनिश्चित कर सकते थे। सेना-समर्थित अभिजात वर्ग ने समझौते और सच्चे संवाद की बजाय दबाव और लाभ बांटने की व्यवस्था से ही "यथास्थिति" बनाए रखी। शांति समझौते और संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ भी ज़्यादातर इस तरह लागू की गईं कि सत्ता केंद्र के हाथ में ही मज़बूत रहे, न कि जातीय इलाक़ों को उस तरह की स्वायत्ता मिले, जहां स्थानीय प्रशासन, संसाधनों का दोहन, सांस्कृतिक हमले, वित्तीय स्वायत्ता पर सीधे जातीय समूहों का

अधिकार हो। एक ऐसी व्यवस्था जहां, केंद्रीय नीतियों, जातीय इलाकों की ज़मीनी सच्चाईयों और समानता के विचार पर आधारित हो। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि केद्रीय नीतियों का मूल दृष्टिकोण सेना को एक “संरक्षक” मानता है, जो बहुसंख्यक की पहचान और राष्ट्र की एकता की रक्षा करता है—और इसी कारण बहुलतावादी शासन हमेशा केंद्रीकृत नियंत्रण के नीचे दबता ही रहा। मज़बूत संवैधानिक गारंटी और समावेशन की राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना, म्यांमार का नेतृत्व ‘ऊपर से नीचे’ तक चलने वाले सत्ता मॉडल पर टिक गया है। इस नियंत्रण-प्रधान सोच ने बराबरी और समावेश पर आधारित राजनीतिक ढाँचे के बनने की प्रक्रिया को लगातार कमजोर किया है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक म्यांमार का राजनीतिक इतिहास यह भी बताता है कि नीतिगत स्तर पर, प्रशासन और सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को गैर-निर्वाचित और बिना जवाबदेही वाली संस्थाओं को सौंपा गया है। इससे उन संस्थाओं के नियमन और निगरानी की व्यवस्था भी कमजोर पड़ जाती है और ऐसा तंत्र खड़ा होता है जो बाहर से देखने में संक्रमणकालीन (ट्रांजिशनल) लगता है लेकिन असल में पुरानी तानाशाही परंपराओं को ही बनाए रखता है। साथ ही, इन्हें इस तरह की छूट दी जाती है जिससे जवाबदेही और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए न्याय की संभावना और कम हो जाती है।

समावेशी राजनीतिक तंत्र की यह तलाश उस वक्त और भी संकटों में दिखती है जब हमें यह पता चलता है कि विपक्षी दलों और सेना विरोधी गुटों के बीच भी नीतिगत असहमतियां रही हैं। सत्ता विकेंद्रीकरण को लेकर उनकी सोच अलग-अलग है, उदाहरण के लिए कुछ समूह सीमित संघीय ढाँचे की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा स्वायत्तता की माँग रखते हैं। जैसे बामार लोग, जो लंबे समय से वर्चस्वशाली समूह रहे हैं, संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे को एक मज़बूत संघ के भीतर विकेंद्रीकरण के सांचे की तरह समझते आए है। उनका पसंदीदा मॉडल के मुताबिक रक्षा, विदेश नीति और व्यापक आर्थिक नियंत्रण जैसे मामलों में एक मज़बूत केंद्रीय सरकार बनी रहनी चाहिए। यह समूह इस बात की वकालत करता है कि राज्यों को 2008 के संविधान से अधिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए। बामार समूह का दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना, धीरे–धीरे सुधार की प्रकिया को बढ़ाना और अल्पसंख्यक अधिकारों पर ज़ोर देता है, लेकिन उन्हें बँटवारे या अलगाववादी तत्वों को लेकर बड़ी चिंताएं रही हैं। वहीं, बड़े जातीय

समूह संघवाद को अलग–अलग नज़रिये से देखते आए हैं। उदाहरण के लिए, शान लोग संघवाद को पांगलोंग समझौते के वादों की पूर्ति मानते हैं, जिसमें राज्यों की बराबरी की गारंटी थी। उनकी संरचनात्मक प्राथमिकता में शान राज्य को ऊंचे स्तर की स्वायत्तता मिलना शामिल है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों, कर वसूली और आंतरिक सुरक्षा पर नियंत्रण शामिल है। वे संप्रभुता और संघिय ढांचे की मान्यता को लेकर 'स्वैच्छिकता' जैसा लचीलापन चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे समूह, केंद्रीय हस्तक्षेप और बामार प्रभुत्व से सावधान रहने में ही यकीन करते हैं।

करेन समूह की बात करें तो, उनके मुताबिक संघीय लोकतंत्र को आत्मनिर्णय और सांस्कृतिक संरक्षण का एक रास्ता मानते हैं। उनका पसंदीदा मॉडल जातीय आधार पर संगठित राज्य का है, जिसमें विधायी, न्यायिक और पुलिस शक्तियां हों। हालाँकि कुछ गुट मिश्रित नागरिक-क्षेत्रीय ढांचे को भी स्वीकारते हैं। वे भाषा अधिकारों, भूमि अधिकारों और जातीय क्षेत्रों के सैन्यीकरण को खत्म करने पर ज़ोर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि करेन इलाक़ों में सेना की मौजूदगी को लेकर बनी रही है। साथ ही वो केंद्र के साथ शांति समझौते को संवैधानिक गारंटी में बदलेंना चाहते हैं। रखाइन (अराकान) लोग संघवाद को लगभग संघ-संघीय स्वायत्तता के रूप में देखते हैं। उनकी प्राथमिकता है कि स्थानीय शासन, बंदरगाहों और संसाधनों पर अधिकतम नियंत्रण रहे और केंद्र का दखल बेहद कम हो। वे ऐतिहासिक संप्रभुता और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देते हैं, लेकिन उन्हें यह चिंता रहती है कि केंद्रीय सरकार उनके संसाधनों का शोषण करेगी और राष्ट्रीय फ़ैसलों में उन्हें हाशिए पर रखेगी। मॉन लोग संघीय लोकतंत्र को सांस्कृतिक अस्तित्व और समावेशी विकास की गारंटी मानते हैं और उनका मॉडल जातीय आधार पर राज्य का है, जिसमें शिक्षा और संस्कृति की नीतियों पर व्यापक स्वायत्तता हो। वे मॉन भाषा और धरोहर की रक्षा और संसाधनों की आमदनी में न्यायसंगत हिस्सेदारी पर ज़ोर देते हैं, लेकिन उन्हें यह डर सताता रहा कि संघीय वार्ताओं में बड़े जातीय समूह उनके हितों पर हावी हो सकते हैं। वहीं भारत से लगती चिन क्षेत्र के चिन समुदाय संघवाद को सभी राज्यों के बीच बराबरी की साझेदारी के रूप में देखते आए हैं, चाहे उन राज्यों का आकार कुछ भी हो। उनका मॉडल शिक्षा, धर्म और स्थानीय शासन में मज़बूत राज्य शक्तियों और न्यायसंगत वित्तीय हस्तांतरण पर आधारित है। वे धार्मिक स्वतंत्रता (क्योंकि वे अधिकतर

ईसाई हैं) और बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़ोर देते हैं, लेकिन चिन समूहों की चिंता रही है कि भौगोलिक अलगाव उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल सकता है।

काचिन समूहों की बात करें तो, यह समूह संघीय लोकतंत्र को राजनीतिक समानता और संसाधनों पर नियंत्रण का साधन मानते हैं। उनका मॉडल जातीय आधार पर राज्य का है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों, ख़ासकर जेड और लकड़ी पर अधिकार, आंतरिक सुरक्षा और शिक्षा का नियंत्रण शामिल है। वे अपनी ईसाई पहचान, भूमि अधिकार और पर्यावरण संरक्षण पर ज़ोर देते हैं, लेकिन उन्हें इन बात की आशंका रही है कि केंद्रीय या विदेशी ताक़तें सैन्यीकरण और संसाधनों का शोषण कर सकती हैं। वहीं, कयाह (करेनी) लोग संघवाद को 1948 से पहले की स्वायत्तता समझौतों की बहाली के तौर पर मानते हैं। उनका पसंदीदा मॉडल छोटे राज्य का है, जिसमें आंतरिक मामलों, सुरक्षा और न्यायपालिका पर पूरा नियंत्रण हो। वे सांस्कृतिक संरक्षण, भूमि अधिकार और स्थानीय शासन पर ज़ोर देते हैं। लेकिन उन्हें चिंता है कि कहीं वे बड़े जातीय समूहों या केंद्रीय एजेंडे के अधीन न हो जाएँ।

उपर दिए गए उदाहरण यह बताने के लिए काफी हैं कि राजनीतिक तंत्र की संरचना को लेकर तमाम भगीदार पिछले करीब 8 दशको के बाद भी बहस से दौर में ही हैं। लेकिन सच यह भी है कि बिखराव का फायदा सत्ता में बैठा तबका उठाता रहा है और आपातकालीन नियम लागू करके फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इस तरह, सख़्त नीतियों और बंटी हुई विपक्षी रणनीतियों के कारण एक साझा राजनीतिक आवाज़ कभी उभर नहीं पाती और उनके बहिष्कार का चक्र चलता रहता है। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले यही ज़रूरी है कि संस्थागत ढांचे की संकल्पना को वैचारिक स्तर पर सुनिश्चित आकार दिया जाए, जो अभी तक दूर की ही कौड़ी लगती है।

रणनीतिक और नीतिगत स्तर पर, जुंटा-विरोधी संघर्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एकजुटता को किस तरह एक टिकाऊ और समावेशी राजनीतिक व्यवस्था में बदला जाए। सच्चाई के धरातल पर टिके रहने वाला बहुलवादी ढांचा तभी संभव हो सकता है, जब न केवल वर्चस्ववादी ढांचे को तोड़ा जाए, बल्कि ऐसे संस्थान भी बनाए जाएं जो बराबरी, अल्पसंख्यकों के संरक्षण और सभी वर्गों

की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे सुरक्षा इंतज़ाम हों जो सत्ता पर एकाधिकार को रोकें, ऐसे संवैधानिक और चुनावी ढांचे हों जो सत्ता में वास्तविक साझेदारी और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। इसके साथ ही इस व्यवस्था में ऐसे संक्रमणकालीन तंत्र हों जो जवाबदेही और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे की गारंटी दें ताकि विघटनकारी तत्वों को रोका जा सके।

पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि कैसे लोकतंत्र - संघवाद समर्थक ताकतों के भीतर ही कई विरोधाभास हैं। सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और स्थानीय स्वायत्तता की माँगों के बीच, अलग-अलग नेतृत्व के दावों के बीच, और भिन्न-भिन्न अंतिम लक्ष्यों के बीच का अंतर यह दिखाते हैं कि प्रतिस्पर्धी वैधताओं का टकराव जारी है और आशंका इस बात की बनी हुई है कि सेना के अलावा, विरोधी ढांचे में कोई नया अभिजात वर्ग न पैदा हो जाए। जुंटा के बनाए सुरक्षा तंत्र के भीतर का बिखराव एक ओर सुलह-बातचीत की गुंजाइश खोलता है, लेकिन दूसरी ओर ये गुंजाइश संस्थागत एकीकरण को और जटिल बना सकता है। बाहरी ताकतें गारंटी देने और संवाद को आगे बढ़ाने की क्षमता तो रखती हैं, लेकिन आशंका इसी बात की है कि वे शक्तियां न्याय और समावेशन से अधिक, स्थिरता और अपने रणनीतिक हितों को तरजीह देने लगेगीं।

वर्ष 2021 की सैन्य तख्तापलट के बाद का म्यांमार, अब सालों के गृह युद्ध के बाद एक नए चौराहे पर खड़ा है, जहां नजरें इस पर है कि क्या आने वाला वक्त यह तय कर सकता है कि सेना का वर्चस्व, मौजूदा राजनीतिक तंत्र से पूरी तरह खत्म होगा और विरोधी शक्तियां एक समय के बाद सेना को पूरी तरह राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर कर सकती हैं। सेना क्या वार्ता की मेज तक पहुंचेगी और क्या विरोधी शक्तियों को भी इस मेज पर आमंत्रित करेंगी और उससे भी बढ़कर क्या विरोधी शक्तियां इस मेज पर जुंटा के बरक्स बैठने को तैयार हो जाएंगी? अगर नहीं, तो क्या मौजूदा हालात को किसी नए राजनीतिक ताने बाने में गढ़ा जा सकता है? मौजूदा बढ़त तमाम विरोधी हितधारकों को बीच का रास्ता तलाशने के लिए कितना मजबूर करेगा या उलटा वो और भी दृढ़ होकर उभरेंगी यानी यह एक गतिरोध की स्थिति होगी। तब तो बहुलवादी राजनीतिक तंत्र का सपना और समीति हो सकता है, क्योंकि वैचारिक बिखराव पहले भी चुनौती थी और आगे भी होंगी, जिसका समाधान फिलहाल तो नहीं दिखता। इन अस्थिर परिस्थितियों

के बीच बस एक बात ही तय है कि जो भी स्थाई समाधान होगा, एक सशक्त और सबको जहां तक हो सके समावेशी राजनीतिक तंत्र के ज़रिए ही होगा।

---

[1] Infographic, Myanmar: Major ethnic groups and where they live, AlJazeera, 14 March 2017, at https://www.aljazeera.com/news/2017/3/14/myanmar-major-ethnic-groups-and-where-they-live (Accessed 21 August 2025)

[2] Lowell Dittmer, Burma or Myanmar? : The Struggle for National Identity, 1st ed. Singapore, World Scientific Publishing, 2010, p. 1.

[3] बर्मी भाषा में, "म्यांमार" बस "बर्मा" का अधिक औपचारिक रूप है। देश का नाम केवल अंग्रेजी में बदला गया था।

[4] Nono Umasy, "History of Myanmar: Map and Timeline," *History Maps*, 25 September 2023, at https://history-maps.com/story/History-of-Myanmar. (Accessed 7 January 2025)

[5] Lowell Dittmer, Burma or Myanmar? : The Struggle for National Identity, 1st ed. Singapore, World Scientific Publishing, 2010, p. 1.

[6] Richard Cockett, *Blood, Dreams and Gold: The Changing Face of Burma*, 1st ed. New Haven: Yale University Press, 2015, pp. 12-18.

[7] *Ibid.*

[8] Jeffrey Hays, "Konbaung Dynasty (1752-1885)," Facts and Details, at https://factsanddetails-com.translate.goog/southeast-asia/Myanmar/sub5_5a/entry-3004.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc. (Accessed January 8, 2025)

[9] David Steinberg, Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know, 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 26-38.

[10] *Ibid.*

[11] Jared Downing, "*Myanmar 101: British Burma,*" Frontier Myanmar, 11 April 2017, at https://www.frontiermyanmar.net/en/myanmar-101-british-burma/. (Accessed 18 January 2025)

[12] Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,* White Lotus, 2nd ed. Bangkok, 1991, pp. 44 – 45.

[13] "Unveiling Myanmar's Ethnic Diversity," Story Maps, 16 April 2024, at https://storymaps.arcgis.com/stories/04a5602f4cad48ab866bae60c1b58d79. (Accessed 18 January 2025)

[14] *Ibid.*

[15] "Jade and Conflict: Myanmar's Vicious Circle," Global Witness, 29 June 2021, at https://www-globalwitness-org.translate.goog/en/campaigns/

natural-resource-governance /jade-and-conflict-myanmars-vicious-circle/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc. (Accessed 18 January 2025)

[16] David Steinberg, Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know, 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 26-38.

[17] Robert L. Solomon, "Saya San and the Burmese Rebellion," *Modern Asian Studies*, Vol. 3 (3), 1969, pp. 209–23. http://www.jstor.org/stable/311948.

[18] W. Elliot Bulmer, "A New Constitution for Myanmar: Towards Consensus on an Inclusive Federal Democracy," *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2022, pp. 27-29. https://doi.org/10.31752/idea.2022.11.

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid.*

[21] *Ibid.*

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

[24] Rajiv Bhatia, *India--Myanmar Relations: Changing contours,* 1st ed. London: Routledge, 2015, pp. 75-80

[25] Bind Basni Prasad, "British India and Burma," *Journal of Comparative Legislation and International Law*, Vol. 21 (3), 1939, pp. 117–30. http://www.jstor.org/stable/754801.

[26] Frank N. Trager, "Burma: The Struggle for Independence, 1944–1948," Volume 1: From Military Occupation to Civil Government, 1 January 1944 to 31 August 1946. Edited by Hugh Tinker. London: HMSO, 1983. Cxxxvi, 1,078 Pp. Illustrations, Maps, Index. £95 (Cloth)," *The Journal of Asian Studies*, Vol. 44 (1), 1984, pp. 251–52. https://doi.org/10.2307/2056815.

[27] *Ibid.*

[28] Hugh Tinker, "Burma's Struggle For Independence: The Transfer of Power Thesis Re-Examined," *Modern Asian Studies*, Cambridge University Press, Vol. 20 (3), 1986, pp. 461-481. doi:10.4324/9781003101703-13.

[29] Camilla Buzzi, "The Ethnopolitics of Democratisation, Democratisation, nationality policy and ethnic relations in Burma, 1948-1962," PhD diss., University of Oslo, 2003.

[30] *Panglong Agreement*, Ethnic National Council of Burma, Panglong, 12 February 1947, at https://peacemaker.un.org/sites/default/files/document/files/2024/05/mm470212panglong20agreement.pdf . (Accessed 6 January 2025)

[31] *Ibid.*

[32] *Ibid.*

[33] *Ibid.*

---

[34] *Ibid.*

[35] John Pike, "Myanmar - Assassination of Aung San - July 19, 1947," *Global Security,* 10 August 2011, at https://www.globalsecurity.org/military/world/myanmar/history-british-8.htm#google_vignette. (Accessed 7 January 2025)

[36] *Ibid.*

[37] Derek Tonkin, The Death of Aung San in 1947 - An Important Clarification, Network Myanmar, 2013, at https://www.networkmyanmar.org/ESW/Files/Death-of-Aung-San.pdf. (Accessed 6 January 2025)

[38] Renaud Egreteau, "Separatism, ethnocracy, and the future of ethnic politics in Burma (Myanmar)," *Secessionism and Separatism in Europe and Asia,* Routledge, 2013. pp. 178-195.

[39] Publications and Debates Reports, "Burma Independence Bill," *UK Parliament*, 5 November 1947, at https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1947/nov/05/burma-independence-bill. (Accessed 6 January 2025)

[40] Graeme Wiffen, "*Drafting a Constitution for Burma: A Comparison of the Government's and an Expatriate Opposition Group's Proposals,*" Australasian Legal Information Institute, December 2000, at http://classic.austlii.edu.au/au/journals/SCULawRw/2000/7.pdf. (Accessed 6 January 2025)

[41] W. Elliot Bulmer, "A New Constitution for Myanmar: Towards Consensus on an Inclusive Federal Democracy," *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2022, pp. 27-29. https://doi.org/10.31752/idea.2022.11.

[42] *Ibid.*

[43] *Ibid.*

[44] Donal K. Coffey, "The Drafting of the Constitution of the Union of Burma in 1947: Dominion Status, Indo–Burmese Relations, and the Irish Example," *Law and History Review*, Vol. 41 (2), 2023, pp. 253–72. https://doi.org/10.1017/S0738248022000487.

[45] Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,* White Lotus, 2nd ed. Bangkok, 1991, pp. 137 - 145.

[46] *Ibid.*, pp. 330 - 335.

[47] Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,* White Lotus, 2nd ed. Bangkok, 1991, pp. 149 - 150.

[48] Dinyar Godrej, "A Short History of Burma," New Internationalist, 18 April 2008, at https://newint.org/features/2008/04/18/history. (Accessed 10 January 2025)

[49] *Ibid.*

[50] David Steinberg, Burma: The State of Myanmar, Georgetown University Press, Washington DC, 2001, pp. 47 – 49.

[51] David Steinberg, Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know, 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 53 - 54.

[52] *Ibid.*

[53] Nehginpao Kipgen, "Political Change in Burma: Transition from Democracy to Military Dictatorship (1948-62)," *Economic and Political Weekly,* Vol. 46 (20), 2011, pp. 48–55. http://www.jstor.org/stable/23018213.

[54] David Steinberg, Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know, 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 53 - 54.

[55] *Ibid.*

[56] Nehginpao Kipgen, "Political Change in Burma: Transition from Democracy to Military Dictatorship (1948-62)," *Economic and Political Weekly,* Vol. 46 (20), 2011, pp. 48–55. http://www.jstor.org/stable/23018213.

[57] Richard Butwell, "The New Political Outlook in Burma," Far Eastern Survey, Vol. 29 (2), 1960, pp. 21–27. https://doi.org/10.2307/3024460.

[58] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar*, Taylor & Francis, Oxfordshire, 2nd ed. 2022, pp. 38 - 45.

[59] Lindsay Maizland, "Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict," Council on Foreign Relation, 31 January 2022, at https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya. (Accessed 14 January 2025).

[60] Aung Kyaw Min, "*The emergence of the non-aligned foreign policy of Burma from the end of the second world war to Bandung conference*," Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD), 2022, 6040. https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/6040

[61] Zaw Thein, *"Failure of Democr e of Democratic Consolidation: The Thr atic Consolidation: The Three Year Interlude of ear Interlude of Military Rule (1958-1962) in Burma,"* Master's thesis, Western Michigan University, 2014.

[62] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar*, Taylor & Francis, Oxfordshire, 2nd ed. 2022, pp. 22 – 26.

[63] *Ibid.*

[64] Pamela T. Stein, "*The Role of the Military in Myanmar's Political Economy,*" Master's thesis, Naval Postgraduate School, California, 2016.

[65] *Ibid.*

[66] Yoshihiro Nakanishi, Strong Soldiers, Failed Revolution: The State and Military in Burma, 1962-88, *Research Gate,* 2013. 10.2307/j.ctv1qv1qg.

[67] Kristian Stokke, "Political Representation by Ethnic Parties? Electoral Performance and Party-Building Processes among Ethnic Parties in

Myanmar," *Journal of Current Southeast Asian Affairs,* Vol. 38 (3), 2019, pp. 307-336. doi:10.1177/1868103419893530.

[68] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar*, Taylor & Francis, Oxfordshire, 2nd ed. 2022, pp. 28 – 36.

[69] *Ibid.*

[70] "History of Elections in Myanmar," Myanmar Election Watch, at https://myanmarelectionwatch.org/en/history-of-elections-in-myanmar. Accessed 14 January 2025.

[71] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar*, Taylor & Francis, Oxfordshire, 2nd ed. 2022, p. 29.

[72] Thant Myint-U, *The River of Lost Footsteps: Histories of Burma*, 1st ed. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006, pp. 277 – 297.

[73] "The State Religion Act," Religion and Public Life at Harvard Divinity School, at https://rpl.hds.harvard.edu/faq/state-religion-act. (Accessed 12 January 2025)

[74] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar*, Taylor & Francis, Oxfordshire, 2nd ed. 2022, pp. 22 – 26.

[75] *Ibid.*, p. 38.

[76] Lindsay Maizland, "Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict," Council on Foreign Relation, 31 January 2022, at https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya. (Accessed 14 January 2025).

[77] Josef Silverstein, "The Burma Socialist Program Party and Its Rivals: A One-Plus Party System," *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 8 (1), 1967, pp. 8–18. http://www.jstor.org/stable/20067609.

[78] Lindsay Maizland, "Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict," Council on Foreign Relation, 31 January 2022, at https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya. (Accessed 14 January 2025).

[79] William Topich, and Keith Leitich, *The History of Myanmar*, Bloomsbury Publishing USA, New York, 1st ed. 2013, pp. 86 – 88.

[80] David Steinberg, *Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know*, 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 63 - 65.

[81] Konsam Shakila Devi, "Myanmar under the Military Rule 1962-1988," *International Research Journal of Social Sciences,* Vol. 3 (10), October 2024, pp. 46 - 50. https://www.isca.me/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf.

[82] David Steinberg, *Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know*, 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 63 - 65.

[83] Fred R. von der Mehden, 'The Burmese Way to Socialism,'" *Asian Survey*, Vol. 3 (3), 1963, pp. 129–35. https://doi.org/10.2307/3023620.

[84] C. P. Cook, "Burma: The Era of Ne Win," *The World Today*, Vol. 26 (6), 1970, pp. 259–66. http://www.jstor.org/stable/40394388.

[85] Konsam Shakila Devi, "Myanmar under the Military Rule 1962-1988," International Research Journal of Social Sciences, Vol. 3 (10), October 2024, pp. 46 - 50. https://www.isca.me/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf.

[86] C. P. Cook, "Burma: The Era of Ne Win," *The World Today*, Vol. 26 (6), 1970, pp. 259–66. http://www.jstor.org/stable/40394388.

[87] David Steinberg, *Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know*, 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 63.

[88] Robert H. Taylor, "The Evolving Military Role in Burma," *Current History,* Vol. 89 (545), 1990, pp. 105–35. http://www.jstor.org/stable/45316348.

[89] Konsam Shakila Devi, "Myanmar under the Military Rule 1962-1988," *International Research Journal of Social Sciences,* Vol. 3 (10), October 2024, pp. 46 - 50. https://www.isca.me/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf.

[90] Wei Yan Aung, "The Day Myanmar Experienced the Socialist Era's First Demonetization," *The Irrawaddy*, 17 May 2020, at https://www.irrawaddy.com/specials/on-this-day/day-myanmar-experienced-socialist-eras-first-demonetization.html#:~:text=YANGON%E2%80%94On%20this%20day%20in,value%20of%20the%20Myanmar%20kyat. (Accessed 15 January 2025).

[91] Konsam Shakila Devi, "Myanmar under the Military Rule 1962-1988," *International Research Journal of Social Sciences,* Vol. 3 (10), October 2024, pp. 46 - 50. https://www.isca.me/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf.

[92] "Constitutional Profile Myanmar," ConstitutionNet, at https://constitutionnet.org/country/myanmar. (Accessed 15 January 2025.)

[93] Panglong Agreement, Ethnic National Council of Burma, Panglong, 12 February 1947, at https://peacemaker.un.org/sites/default/files/document/files/2024/05/mm470212panglong20agreement.pdf . (Accessed 6 January 2025)

[94] *Rule of Law for Human Rights in the Asean Region: A Base-line Study*, Human Rights Resource Centre, at https://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/07.-ROL-English-Myanmar.pdf. (Accessed 16 January 2025)

[95] "Burma (Myanmar), December 31, 1973: Constitution," *Database and Search Engine for Direct Democracy*, 15 January 2019, at

https://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=mm011973. (Accessed 16 January 2025)

[96] "Constitutional Profile Myanmar," ConstitutionNet, at https://constitutionnet.org/country/myanmar. (Accessed 15 January 2025.)

[97] "Constitutional Profile Myanmar," ConstitutionNet, at https://constitutionnet.org/country/myanmar. (Accessed 15 January 2025.)

[98] Vote to Nowhere: The May 2008 Constitutional Referendum in Burma, Human Rights Watch, New York, 2008, at https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0508_1.pdf. (Accessed 16 January 2025)

[99] "Constitutional Profile Myanmar," ConstitutionNet, at https://constitutionnet.org/country/myanmar. (Accessed 15 January 2025.)

[100] *Ibid.*

[101] Konsam Shakila Devi, "Myanmar under the Military Rule 1962-1988," *International Research Journal of Social Sciences,* Vol. 3 (10), October 2024, pp. 46 - 50. https://www.isca.me/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf.

[102] W. Elliot Bulmer, "A New Constitution for Myanmar: Towards Consensus on an Inclusive Federal Democracy," *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2022, p. 27. https://doi.org/10.31752/idea.2022.11.

[103] David Steinberg, *Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know,* 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 63 - 65.

[104] Albert Moscotti, *Burma's Constitution and Elections of 1974: A Source Book*, Institute of Southeast Asian Studies, 1st ed. Singapore, 2018.

[105] Albert Moscotti, *Burma's Constitution and Elections of 1974: A Source Book*, Institute of Southeast Asian Studies, 1st ed. Singapore, 2018, pp. 74 – 78.

[106] "Burma/Myanmar (1948-present)," *University of Central Arkansas*, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 17 January 2025).

[107] "Civil War in Myanmar," Global Conflict Tracker, 10 January 2025, at https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/rohingya-crisis-myanmar#:~:text=Since%20gaining%20independence%20from%20British,groups%20fighting%20for%20self%2Ddetermination. (Accessed 16 January 2025).

[108] Erin Murphy, Matthew Turpin and Peter Kucik, "Reforming Myanmar's Military," *PRISM*, Vol. 5 (3), 2015, pp. 76–89. http://www.jstor.org/stable/26470412.

[109] Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,* White Lotus, 2nd ed. Bangkok, 1991, pp. 258 – 261.

[110] *Ibid.*

[111] Resource Information Center: Myanmar, "*Chronology of Burmese Major Opposition Groups,*" U.S. Citizenship & Immigration Services, 17 August 2000, at https://www.uscis.gov/archive/resource-information-center-myanmar-2. (Accessed 17 January 2025)

[112] *Ibid.*

[113] National Democratic Front - Burma, *14th Session of the UN Working Group on Indigenous Peoples,* Geneve, Switzerland, July 1996, at https://cendoc.docip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASHbb10/9c9feded.dir/960435.pdf

[114] *Ibid.*

[115] Tin Maung Maung Than, "The Essential Tension: Democratization and the Unitary State in Myanmar (Burma)," *South East Asia Research*, Vol. 12 (2), 2004, pp. 187–212. http://www.jstor.org/stable/23750296.

[116] Lindsay Maizland, "Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict," *Council on Foreign Relations,* 31 January 2022, at https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya. (Accessed 17 January 2025)

[117] Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,* White Lotus, 2nd ed. Bangkok, 1991, pp. 75 – 80.

[118] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[119] Raja Segaran Arumugam, "Burma: Political Unrest and Economic Stagnation," *Southeast Asian Affairs*, 1976, pp.167–75. http://www.jstor.org/stable/27908277.

[120] *Ibid.*

[121] *Ibid.*

[122] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[123] Anna S. King, "Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government," *Religions*, Vol. 13 (7);594, 2022. https://doi.org/10.3390/rel13070594

[124] Andrew Selth, "*Death of a hero: The U Thant disturbances in Burma, December 1974,*" Research Paper, Griffith Asia Institute, July 2018, at

https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0032/483827/AS-death-of-a-hero-U-Thant-disturbance-web-final.pdf.

[125] Tin Maung Maung Than, "The Essential Tension: Democratization and the Unitary State in Myanmar (Burma)," *South East Asia Research,* Vol. 12 (2), 2004, pp. 187–212. http://www.jstor.org/stable/23750296.

[126] Dieter Nohlen, Florian Grotz, and Christof Hartmann, editors. *Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook: Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia,* OUP, Oxford, 1st ed. 2001, pp. 615.

[127] Zhu Xianghui, "General Elections in Myanmar from the Perspective of Inter-Ethnic Relations: Contest and Adaptation," *Myanmar Research Institute & Center for China's Neighboring Diplomacy Studies,* Yunnan University. URL. https://www.stimson.org/wp-content/files/file-attachments/Zhu%20Xianghui%20-%20General%20Elections%20in%20Myanmar%20R2.pdf.

[128] Tom Kramer, "Ethnic Conflict and Lands Rights in Myanmar," *Social Research,* Vol. 82 (2), 2015, pp. 355–74. http://www.jstor.org/stable/44282108.

[129] Dieter Nohlen, Florian Grotz, and Christof Hartmann, editors. *Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook: Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia,* OUP, Oxford, 1st ed. 2001, pp. 615.

[130] "Burmese Voting Starts In Single-Party Election," *The New York Times,* 5 October 1981, at https://www.nytimes.com/1981/10/05/world/burmese-voting-starts-in-single-party-election.html. (Accessed 18 January 2025)

[131] Dieter Nohlen, Florian Grotz, and Christof Hartmann, editors. *Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook: Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia,* OUP, Oxford, 1st ed. 2001, pp. 615.

[132] Zhu Xianghui, "General Elections in Myanmar from the Perspective of Inter-Ethnic Relations: Contest and Adaptation," *Myanmar Research Institute & Center for China's Neighboring Diplomacy Studies,* Yunnan University. URL. https://www.stimson.org/wp-content/files/file-attachments/Zhu%20Xianghui%20-%20General%20Elections%20in%20Myanmar%20R2.pdf.

[133] Tom Kramer, "Ethnic Conflict and Lands Rights in Myanmar," *Social Research,* Vol. 82 (2), 2015, pp. 355–74. http://www.jstor.org/stable/44282108.

[134] Raja Segaran Arumugam, "Burma: Political Unrest and Economic Stagnation," *Southeast Asian Affairs*, 1976, pp.167–75. http://www.jstor.org/stable/27908277.

[135] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[136] Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,* White Lotus, 2nd ed. Bangkok, 1991, pp. 304 – 306.

[137] Konsam Shakila Devi, "Myanmar under the Military Rule 1962-1988," *International Research Journal of Social Sciences,* Vol. 3 (10), October 2024, pp. 46 - 50. https://www.isca.me/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf.

[138] Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,* White Lotus, 2nd ed. Bangkok, 1991, pp. 304 – 306.

[139] "Jade and Conflict: Myanmar's Vicious Circle," Global Witness, 29 June 2021, at https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/jade-and-conflict-myanmars-vicious-circle/. (Accessed 20 January 2025)

[140] Josef Silverstein, "Burma in 1980: An Uncertain Balance Sheet," *Asian Survey,* Vol. 21(2), 1981, pp. 212–22. https://doi.org/10.2307/2643766.

[141] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[142] Josef Silverstein, "Burma in 1980: An Uncertain Balance Sheet," *Asian Survey,* Vol. 21(2), 1981, pp. 212–22. https://doi.org/10.2307/2643766.

[143] *Ibid.*

[144] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[145] Josef Silverstein, "Burma in 1980: An Uncertain Balance Sheet," *Asian Survey,* Vol. 21(2), 1981, pp. 212–22. https://doi.org/10.2307/2643766.

[146] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[147] *Ibid.*

[148] 10 Years for The Rohingya Refugees In Bangladesh: Past, Present And Future, *Médecins Sans Frontières-Holland*, 2002, at https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/sites/default/files/attachments/2002-03-bangladesh-report-rohingya.pdf. (Accessed 17 January 2025)

[149] "A Timeline of Rohingya History - Burma's Path to Genocide - United States Holocaust Memorial Museum," United States Holocaust Memorial Museum, 21 January 2025, at https://exhibitions.ushmm.org/burmas-path-to-genocide/timeline?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 20 January 2025)

[150] Least Developed Country Category: Myanmar Profile, "Department of Economic and Social Affairs," United Nations, at https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-myanmar.html. (Accessed 20 January 2025)

[151] "The Day Three Myanmar Banknotes Suddenly Became Worthless," *The Irrawaddy,* 5 September 2019, at https://www.irrawaddy.com/specials/on-this-day/day-three-myanmar-banknotes-suddenly-became-worthless.html. (Accessed 20 January 2025)

[152] Karin Dean, Myanmar: Surveillance and the Turn from Authoritarianism? *Surveillance & Society,*

Vol. 15(3/4), pp. 496-505.

[153] Sunjay Chandiramani, "Burma and Western Precepts of Democracy," Economic and Political Weekly, Vol. 43 (39), 2008, pp. 25–27.

[154] Maung Aung Myoe, "A Historical Overview of Political Transition in Myanmar Since 1988," *Asia Research Institute Working Paper Series No. 95*, Asia Research Institute National University of Singapore, 2007.

[155] *Ibid.*

[156] "The Military: Institution and Politics," In Myanmar: Politics, Economy and Society, edited by Adam Simpson and Nicholas Farrelly, 2nd ed., Taylor & Francis, Oxfordshire, 2023, pp. 47-52.

[157] Nick B. Williams Jr., "Commerce Snarled As Burma Rules Much of Its Currency Is Worthless," Los Angeles Times, 12 September 1987 at https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1987-09-12-mn-1980-story.html. (Accessed 6 January 2025).

[158] Priscilla Clapp, "Burma's Long Road to Democracy," Special Repot 193, United States Institute of Peace, November 2007.

[159] Eli Meixler, "How A Failed Uprising Set The Stage For Myanmar's Future," TIME, 8 August 2018, at https://time.com/5360637/myanmar-8888-uprising-30-anniversary-democracy/. (Accessed 6 January 2025).

[160] Richard Butwell, "Ne Win's Burma: At the End of the First Decade," Asian Survey, Vol.12 (10), 1972, pp. 901–12.

[161] Rudy Guyon, "Violent repression in Burma: human rights and the global response," UCLA Pac. Basin LJ, 10, 1991, p. 409.

[162] Radio Diaries, "Timeline: Myanmar's '8/8/88' Uprising," NPR, 8 August 2013, at https://www.npr.org/2013/08/08/210233784/timeline-myanmars-8-8-88-uprising. (Accessed 6 January 2025).

[163] John B. Haseman, "Destruction of Democracy: The Tragic Case of Burma," *Asian Affairs: An American Review*, Vol. 20 (1), 1993, pp. 17-26.

[164], Tin Maung Maung Than, "Military in Charge," Government & Politics in Southeast Asia, *Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,* 2001, p. 203.

[165] Maung Aung Myoe, "A Historical Overview of Political Transition in Myanmar Since 1988," *Asia Research Institute Working Paper Series No. 95*, Asia Research Institute National University of Singapore, 2007.

[166] "The Military: Institution and Politics," In Myanmar: Politics, Economy and Society, edited by Adam Simpson and Nicholas Farrelly, 2nd ed., Taylor & Francis, Oxfordshire, 2023, pp. 4 - 8.

[167] Egreteau Renaud, "The Repression of the August 8-12 1988 (8-8-88) Uprising in Burma/Myanmar," 25 February 2009, at https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/repression-august-8-12-1988-8-8-88-uprising-burmamyanmar.html. (Accessed 6 January 2025).

[168] "The Military: Institution and Politics," In Myanmar: Politics, Economy and Society, edited by Adam Simpson and Nicholas Farrelly, 2nd ed., Taylor & Francis, Oxfordshire, 2023, pp. 4 - 8.

[169] "Aung San Suu Kyi: Myanmar Democracy Icon Who Fell from Grace," BBC News, 6 December 2021, at https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11685977#:~:text=%22I%20could%20not%20as%20my%20father%27s%20daughter%20remain,the%20revolt%20against%20the%20then-dictator%2C%20General%20Ne%20Win. (Accessed 5 January 2025)

[170] Whitney Stewart, *Aung San Suu Kyi: Fearless Voice of Burma,* iUniverse, 2nd Edi. 2008, p. 54.

[171] "Aung San Suu Kyi: Myanmar Democracy Icon Who Fell from Grace," BBC News, 6 December 2021, at https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11685977#:~:text=%22I%20could%20not%20as%20my%20father%27s%20daughter%20remain,the%20revolt%20against%20the%20then-dictator%2C%20General%20Ne%20Win. (Accessed 5 January 2025)

[172] "Once an icon of democracy, today on trial for genocide," Koha, 11 December 2019, at https://www.koha.net/en/bote/dikur-ikone-e-demokracise-sot-ne-gjyq-per-gjenocid. (Accessed 7 January 2025).

[173] Maung Aung Myoe, "A Historical Overview of Political Transition in Myanmar Since 1988," *Asia Research Institute Working Paper Series No. 95*, Asia Research Institute National University of Singapore, 2007.

[174] *Ibid.*

[175] "Myanmar: Parliamentary Elections Pyithu Hluttaw, 1990," *Inter-Parliamentary Union*, at https://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2388_90.htm. (Accessed 24 February 2025).

[176] David Steinberg, Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know, 1st ed. New York, Oxford University Press, 2010, pp. 12 – 17.

[177] Maung Aung Myoe, "A Historical Overview of Political Transition in Myanmar Since 1988," *Asia Research Institute Working Paper Series No. 95*, Asia Research Institute National University of Singapore, 2007.

[178] *Ibid.*

[179] National Coalition Government of The Union Of Burma, NCGUB: the National Coalition Government of the Union of Burma. Burma/Myanmar, 2002, Web Archive, at https://www.loc.gov/item/lcwaN0004803/. (Accessed 7 January 2025)

[180] Maung Aung Myoe, "A Historical Overview of Political Transition in Myanmar Since 1988," *Asia Research Institute Working Paper Series No. 95*, Asia Research Institute National University of Singapore, 2007.

[181] *Ibid.*

[182] *Ibid.*

[183] Ulf Sundhaussen, "Indonesia's New Order: A Model for Myanmar?" *Asian Survey*, Vol. 35 (8), 1995, pp. 768–80. https://doi.org/10.2307/2645735.

[184] Janelle M. Diller, "Constitutional Reform in a Repressive State: The Case of Burma," *Asian Survey*, Vol. 33 (4), 1993, pp. 393–407. https://doi.org/10.2307/2645105.

[185] Maung Aung Myoe, "A Historical Overview of Political Transition in Myanmar Since 1988," *Asia Research Institute Working Paper Series No. 95*, Asia Research Institute National University of Singapore, 2007.

[186] Lt. Gen Phone Myint, 1 February 1991 (WPD, 5 February 1991).

[187] Mohinder Pal Singh, "Myanmar: Militarised Democratic Landscape," *Scholar Warrior*, Centre for Land Warfare Studies, Spring 2013, pp. 72-79.

[188] Maung Aung Myoe, "A Historical Overview of Political Transition in Myanmar Since 1988," *Asia Research Institute Working Paper Series No. 95*, Asia Research Institute National University of Singapore, 2007.

[189] W. Elliot Bulmer, "A New Constitution for Myanmar: Towards Consensus on an Inclusive Federal Democracy," *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2022, pp. 27-29. https://doi.org/10.31752/idea.2022.11.

[190] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[191] *Ibid.*

[192] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar,* Routledge, London, 2nd ed. 2022, pp. 78.

[193] "Burma's 2010 Elections: Implications of the New Constitution and Election Laws," Congressional Research Service, 4 June 2010, at

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R41218/8. (Accessed 25 January 2025)

[194] Marco Buente, "Burma's Transition to 'Disciplined Democracy': Abdication or Institutionalization of Military Rule?" *GIGA Working Papers,* GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems, no. 177, August 2011. doi:10.2139/ssrn.1924279.

[195] "The 7-Step Roadmap," Online Burma/Myanmar Library, 5 December 2019, at https://www.burmalibrary.org/en/category/the-7-step-roadmap. (24 January 2025) "Myanmar's Seven-step Peace Process Not Inclusive, Lacks Timeline – Annan." UN News. Last modified November 10, 2003. https://news.un.org/en/story/2003/11/85072-myanmars-seven-step-peace-process-not-inclusive-lacks-timeline-annan.

[196] "Myanmar's Seven-step Peace Process Not Inclusive, Lacks Timeline – Annan," *UN News,* 10 November 2003, at https://news.un.org/en/story/2003/11/85072-myanmars-seven-step-peace-process-not-inclusive-lacks-timeline-annan. (Accessed 21 January 2025)

[197] David Steinberg, "Globalization, dissent, and orthodoxy: Burma/Myanmar and the Saffron Revolution." *Geo. J. Int'l Aff.* Vol. 9, 2008, p. 51.

[198] "Saffron Revolution," Religion and Public Life at Harvard Divinity School, at https://rpl.hds.harvard.edu/faq/saffron-revolution. (Accessed 21 January 2025)

[199] Benedict Rogers, "The saffron revolution: The role of religion in Burma's movement for peace and democracy," *Totalitarian Movements and Political Religions,* Vol. 9 (1), 2008, pp. 115-118.

[200] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar,* Routledge, London, 2nd ed. 2022, pp. 62 - 64.

[201] "2007 Uprising in Burma," Burma Campaign UK, at https://burmacampaign-org-uk.translate.goog/about-burma/2007-uprising-in-burma/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=wa. (Accessed 19 January 2025)

[202] Aung Hla Tun, "Myanmar monks march past Suu Kyi's home," Reuters, 22 September 2007, at https://www.reuters.com/article/world/myanmar-monks-march-past-suu-kyi-s-home-idUSSP146948/. (Accessed 19 January 2025)

[203] "2007 Uprising in Burma," Burma Campaign UK, at https://burmacampaign-org-uk.translate.goog/about-burma/2007-uprising-in-burma/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=wa. (Accessed 19 January 2025)

[204] *Ibid.*

[205] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[206] "2007 Uprising in Burma," Burma Campaign UK, at https://burmacampaign-org-uk.translate.goog/about-burma/2007-uprising-in-burma/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=wa. (Accessed 19 January 2025)

[207] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar,* Routledge, London, 2nd ed. 2022, pp. 62 - 64.

[208] Jacques Bertrand, Alexandre Pelletier, and Ardeth Thawnghmung, *Winning by Process: The State and Neutralization of Ethnic Minorities in Myanmar,* Southeast Asia Program Publications, Cornell University Press, 1st ed. 2022, pp. 64.

[209] Michael Martin, "Remembering Myanmar's Miserable May," *Center for Strategic and International Studies,* 12 July 2023, at https://www.csis.org/analysis/remembering-myanmars-miserable-may?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 23 January 2025)

[210] *Ibid.*

[211] "Burma's Military Blocks Constitutional Amendments," *The Congressional Research Service,* 30 March 2020, at https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11481.

[212] *Ibid.*

[213] "Burma's Military Blocks Constitutional Amendments," *The Congressional Research Service,* 30 March 2020, at https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11481.

[214] "Comparing Three Versions of The Myanmar (Burma) Constitution," *ConstitutionNet,* at https://constitutionnet.org/comparing-three-versions-myanmar-burma-constitution. (Accessed 22 January 2025)

[215] "Myanmar 2008 Constitution," *Constitute,* at https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008. (Accessed 22 January 2025)

[216] "Comparing Three Versions of The Myanmar (Burma) Constitution," *ConstitutionNet,* at https://constitutionnet.org/comparing-three-versions-myanmar-burma-constitution. (Accessed 22 January 2025)

[217] Lindsay Maizland, "Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict," *Council on Foreign Relations*, 31 January 2022, at https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya#:~:text=Reforms%20launched%20in%202011%2C%20including%20opening%20up,nearly%20double%20what%20it%20was%20in%202008. (Accessed 22 January 2025)

[218] W. Elliot Bulmer, "A New Constitution for Myanmar: Towards Consensus on an Inclusive Federal Democracy," *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2022, p. 27. https://doi.org/10.31752/idea.2022.11.

[219] *Ibid.*

[220] "Myanmar 2008 Constitution," *Constitute,* at https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008. (Accessed 22 January 2025)

[221] Fabio Armao, "The Tatmadaw Legacy and Beyond: On the Risks for the Democratisation Process in Myanmar," *European Journal of East Asian Studies*, Vol. 14 (1), 2015, pp. 32-51.

[222] "Comparing Three Versions of The Myanmar (Burma) Constitution," *ConstitutionNet,* at https://constitutionnet.org/comparing-three-versions-myanmar-burma-constitution. (Accessed 22 January 2025)

[223] Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,* White Lotus, 2nd ed. Bangkok, 1991, pp. 445 – 446.

[224] Jacques Bertrand, Alexandre Pelletier and Ardeth Maung Thawnghmung, *"Winning by process: the state and neutralization of ethnic minorities in Myanmar,"* Cornell University Press, London, 1st ed. 2022, pp. 4 - 7.

[225] Dr. Melissa Crouch, "The Constitutional Implications of Myanmar's Peace Process," *ConstitutionNet,* 25 July 2016, at https://constitutionnet.org/news/constitutional-implications-myanmars-peace-process. (Accessed 23 January 2025)

[226] *Ibid.*

[227] *Ibid.*

[228] "Myanmar 2008 Constitution," Constitute, at https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008#:~:text=Legislative%20power%20stipulated%20by%20this,elected%20from%20Regions%20and%20States. (Accessed 26 January 2025)

[229] Kaisa Ojola, "The Constitutional Implications of Myanmar's Peace Process," Master's thesis, Tallinn University of Technology, 2022.

[230] *Ibid.*

[231] "History of Elections in Myanmar," *Myanmar Election Watch,* at https://myanmarelectionwatch-org.translate.goog/en/history-of-elections-in-myanmar?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc. (Accessed 25 January 2025)

[232] *Ibid.*

[233] The November 2010 Elections, Burma: Country Summary. Human Rights Watch, 2011, at https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/burma_0_0.pdf. (Accessed 27 January 2025)

[234] *Ibid.*

[235] Burma's 2010 Elections: a comprehensive report, The Burma Fund UN Office, 2011. https://www.burmalibrary.org/docs11/BurmaFund-Election_Report-text.pdf. (Accessed 27 January 2025)

[236] *Ibid.*

[237] Psephos - Adam Carr's Election Archive. Accessed January 28, 2025. https://psephos.adam-carr.net/countries/b/burma/burma2010.txt. (27 January 2025)

[238] The November 2010 Elections, Burma: Country Summary. Human Rights Watch, 2011, at https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/burma_0_0.pdf. (Accessed 27 January 2025)

[239] Trevor Wilson, "The Significance of Myanmar's 2010 Election," New Mandala, 15 December 2010, at https://www.newmandala.org/the-significance-of-myanmar%E2%80%99s-2010-election/. (Accessed 26 January 2025)

[240] Trevor Wilson, "The Significance of Myanmar's 2010 Election," New Mandala, 15 December 2010, at https://www.newmandala.org/the-significance-of-myanmar%E2%80%99s-2010-election/. (Accessed 26 January 2025)

[241] Anna S. King, Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government, Religions, Vol. 13 (594), 2022. https://doi.org/10.3390/rel13070594

[242] Trevor Wilson, "The Significance of Myanmar's 2010 Election," New Mandala, 15 December 2010, at https://www.newmandala.org/the-significance-of-myanmar%E2%80%99s-2010-election/. (Accessed 26 January 2025)

[243] *Ibid.*

[244] Yoshihiro Nakanishi and Noriyuki Osada, "The 2015 Myanmar general election: A historic victory for the national league for democracy," *IDE-JETRO,* Vol. 48, no. 1, 2016, pp. 132-142. doi:10.1080/14672715.2015.1134929.

[245] Jacques Bertrand, Alexandre Pelletier, and Ardeth Thawnghmung, *Winning by Process: The State and Neutralization of Ethnic Minorities in Myanmar,* Southeast Asia Program Publications, Cornell University Press, 1st ed. 2022, pp. 64.

[246] *Ibid.*

[247] *Ibid.*, pp. 84 - 87.

[248] *Ibid.*

[249] "The Nationwide Ceasefire Agreement in Myanmar," Transnational Institute, 15 October 2023, at https://www.tni.org/en/article/the-nationwide-ceasefire-agreement-in-myanmar. (Accessed 26 January 2025)

[250] *Ibid.*

[251] International Crisis Group, "Myanmar's Peace Process: A Nationwide Ceasefire Remains Elusive," International Crisis Group, 2015. http://www.jstor.org/stable/resrep31853.

[252] *Ibid.*

[253] "The Nationwide Ceasefire Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Ethnic Armed Organizations," Peace Agreements, 2016, at https://www.peaceagreements.org/masterdocument/1436. (Accessed 27 January 2025)

[254] *Ibid.*

[255] *Ibid.*

[256] *Ibid.*

[257] *Ibid.*

[258] *Ibid.*

[259] *Ibid.*

[260] Jacques Bertrand, Alexandre Pelletier, and Ardeth Thawnghmung, *Winning by Process: The State and Neutralization of Ethnic Minorities in Myanmar,* Southeast Asia Program Publications, Cornell University Press, 1st ed. 2022, pp. 84 - 86.

[261] *Ibid.*

[262] *Ibid.*

[263] Nehginpao Kipgen, *Democratisation of Myanmar,* Routledge, London, 2nd ed. 2022, pp. 81 - 84.

[264] Myanmar 2008, Constitute, at https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008 (Accessed 24 August 2025)

[265] Tin Maung Maung Than, "Myanmar's 2012 By-Elections: The Return of NLD." *Southeast Asian Affairs*, 2013, pp. 204 –19. http://www.jstor.org/stable/23471145.

[266] "Myanmar 2012 By-elections," Online Burma/Myanmar Library, 5 December 2019, at https://www.burmalibrary.org/mm/myanmar-2012-by-elections?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 28 January 2025)

[267] C. S. Kuppuswamy, "Myanmar By-Elections: An Analysis," Eurasia Review, 7 April 2012, at https://www.eurasiareview.com/07042012-myanmar-by-elections-an-analysis/?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 28 January 2025)

[268] "History of Elections in Myanmar," *Myanmar Election Watch,* at https://myanmarelectionwatch.org/en/history-of-elections-in-myanmar. (Accessed 28 January 2025)

[269] Yoshihiro Nakanishi and Noriyuki Osada, "The 2015 Myanmar general election: A historic victory for the national league for democracy," *IDE-JETRO,* Vol. 48, no. 1, 2016, pp. 132-142. doi:10.1080/14672715.2015.1134929.

[270] Shankar Acharya, "Myanmar's historic election," *Business Standard,* 9 December 2015, at https://www.business-standard.com/article/opinion/shankar-acharya-myanmar-s-historic-election-115120901348_1.html. (Accessed 24 February 2025)

[271] Jonah Fisher, "Aung San Suu Kyi: Power Not Presidency in Myanmar," *BBC News*, 15 March 2016, at https://www.bbc.com/news/world-asia-35754335. (Accessed 28 January 2025)

[272] Yoshihiro Nakanishi and Noriyuki Osada, "The 2015 Myanmar general election: A historic victory for the national league for democracy," *IDE-JETRO,* Vol. 48, no. 1, 2016, pp. 132-142. doi:10.1080/14672715.2015.1134929.

[273] Tin Maung Maung Than, "Myanmar's 2012 By-Elections: The Return of NLD." *Southeast Asian Affairs*, 2013, pp. 204 –19. http://www.jstor.org/stable/23471145.

[274] Annabelle Heugas, "Reforming Myanmar's 2008 Constitution: a key element to the country's democratic transition," Foundation Office Myanmar, Konrad Adenauer Stiftung, 22 October 2019, at https://www.kas.de/en/web/myanmar/laenderberichte/detail/-/content/reforming-myanmar-s-2008-constitution-a-key-element-to-the-country-s-democratic-transition?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 28 January 2025)

[275] Annabelle Heugas, "Reforming Myanmar's 2008 Constitution: a key element to the country's democratic transition," Foundation Office Myanmar, Konrad Adenauer Stiftung, 22 October 2019, at https://www.kas.de/en/web/myanmar/laenderberichte/detail/-/content/reforming-myanmar-s-2008-constitution-a-key-element-to-the-country-s-democratic-transition?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 28 January 2025)

[276] "Aung San Suu Kyi - Burmese Politician, Nobel Laureate, Activist," Encyclopedia Britannica, 20 July 1998, at https://www.britannica.com/biography/Aung-San-Suu-Kyi/State-counselor. (Accessed 27 January 2025)

[277] "Aung San Suu Kyi to Become 'State Counsellor' of Myanmar," ABC (Australian Broadcasting Corporation), 5 April 2016, at https://www.abc.net.au/news/2016-04-05/aung-san-suu-kyi-to-become-state-counsellor/7301994. (Accessed 27 January 2025)

[278] Michal Lubina, "Myanmar Election: How the West Misread Aung San Suu Kyi," *9DASHLINE*, 6 November 2020, at

https://www.9dashline.com/article/myanmar-election-how-the-west-misread-aung-san-suu-kyi. (Accessed 27 January 2025)

[279] Angshuman Choudhury, "The Third 21st Century Panglong Conference: A Review," Institute of Peace & Conflict Studies, 16 July 2018, at https://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=5499. (Accessed 27 January 2025)

[280] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[281] "MSF: At Least 6,700 Rohingya Killed During Attacks in Myanmar," Doctors Without Borders, 14 December 2017, at https://www.doctorswithoutborders.org/latest/msf-least-6700-rohingya-killed-during-attacks-myanmar. (Accessed 25 January 2025)

[282] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[283] "Sexual and gender-based violence in Myanmar and the gendered impact of its ethnic conflicts," United Nations Human Rights Council, 22 August 2019, at https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/08/report/sexual-and-gender-based-violence-in-myanmar-and-the-gendered-impact-of-its-ethnic-conflicts/A_HRC_CRP_4.pdf. (Accessed 28 January 2025)

[284] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[285] "Myanmar Rohingya: Suu Kyi Rejects Genocide Claims at UN Court," BBC News, 11 December 2019, at https://www.bbc.com/news/world-asia-50741094. (Accessed 19 January 2025)

[286] *Ibid.*

[287] "Burma/Myanmar (1948-present)," University of Central Arkansas, at https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/. (Accessed 19 January 2025)

[288] *Ibid.*

[289] Angshuman Choudhury, "Of Guarantees and Stalemates: An Assessment of Myanmar's Fourth 21st Century Panglong Peace Conference," Institute of Peace and Conflict Studies, 14 September 2020, at https://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=5723. (Accessed 29 January 2025)

---

[290] "Myanmar Rohingya: Suu Kyi Rejects Genocide Claims at UN Court," BBC News, 11 December 2019, at https://www.bbc.com/news/world-asia-50741094. (Accessed 19 January 2025)

[291] Andrew Selth, "Myanmar's Armed Forces and the Rohingya Crisis," United States Institute of Peace, August 2018, at https://www.usip.org/sites/default/files/2018-08/pw140-myanmars-armed-forces-and-the-rohingya-crisis.pdf. (Accessed 28 January 2025)

[292] Veronica Lowe, Aung San Suu Kyi (Philosophy, Politics and Economics, 1964) Profile, St. Hugh's College, at https://www.st-hughs.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2021/04/Aung-San-Suu-Kyi-Profile-1.pdf (Accessed 29 January 2025)

[293] Michal Lubina, "Myanmar Election: How the West Misread Aung San Suu Kyi," *9DASHLINE*, 6 November 2020, at https://www.9dashline.com/article/myanmar-election-how-the-west-misread-aung-san-suu-kyi. (Accessed 27 January 2025)

[294] Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, The economic interests of the Myanmar military, Forty-second session, Human Rights Council, 12 September 2019.

[295] *Ibid.*

[296] Khin Zaw Win, "Twin Authoritarianisms in Myanmar," Centre Tricontinental, Last modified September 24, 2019. https://www.cetri.be/Twin-authoritarianisms-in-Myanmar.(Accessed 28 January 2025)

[297] Renaud Egreteau, "Aung San Suu Kyi's Win is Just the Start," Le Monde Diplomatique,. Last modified December 2015. https://mondediplo.com/2015/12/07myanmar. (Accessed 29 January 2025)

[298] Richard Dolan, "The Problem with the 21st Century Panglong Conference," The Diplomat, 6 August 2016. https://thediplomat.com/2016/08/the-problem-with-the-21st-century-panglong-conference/.

[299] Nigel Walker, Myanmar: 2020 parliamentary election, Briefing Paper, House of Commons Library, UK Parliament, 4 February 2021, at https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9127/CBP-9127.pdf. (Accessed 28 January 2025)

[300] Nigel Walker, Myanmar: 2020 parliamentary election, Briefing Paper, House of Commons Library, UK Parliament, 4 February 2021, at https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9127/CBP-9127.pdf. (Accessed 28 January 2025)

[301] *Ibid.*

[302] *Ibid.*

[303] Sanjay Pulipaka and Mohit Musaddi, "Myanmar Elections 2020: An Analysis," Delhi Policy Group Report, Vol. 5 (40), December 2020, at https://www.delhipolicygroup.org/uploads_dpg/publication_file/myanmar-elections-2020-an-analysis-2122.pdf.

[304] "Myanmar's Military Claims That the UEC, Along with the Union Government, Has Been Unable to Hold a Free and Fair General Election," Eleven Media Group Co. Ltd., at https://elevenmyanmar.com/news/myanmars-military-claims-that-the-uec-along-with-the-union-government-has-been-unable-to-hold-a. (Accessed 29 January 2025)

[305] *Ibid.*

[306] Myanmar's Military Chief Agrees to Accept Election Result", The Irrawaddy, 8 November 2020, at https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-military-chief-agrees-accept-election-result.html#google_vignette. (Accessed 28 January 2025)

[307] "2021 Myanmar Coup D'etat: History, Facts, & Explained," Encyclopedia Britannica, 12 July 2022, at https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat. (Accessed 29 January 2025)

[308] Morten B. Pedersen, "The 2021 Military Coup: Causes and Consequences," Chapter in Myanmar in Crisis: Living with the Pandemic and the Coup, edited by Justine Chambers and Michael R. Dunford, Lectures, Workshops, and Proceedings of International Conferences. ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2023, pp. 41–68.

[309] "2021 Myanmar Coup D'etat: History, Facts, & Explained," Encyclopedia Britannica, 12 July 2022, at https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat. (Accessed 29 January 2025)

[310] Morten B. Pedersen, "The 2021 Military Coup: Causes and Consequences," Chapter in Myanmar in Crisis: Living with the Pandemic and the Coup, edited by Justine Chambers and Michael R. Dunford, Lectures, Workshops, and Proceedings of International Conferences. ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2023, pp. 41–68.

[311] Virginia Gadzo, "Myanmar's Military Stages Coup D'etat," Al Jazeera, 1 February 2021, at https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/myanmar-military-stages-coup-against-aung-san-suu-kyi-live. (Accessed 29 January 2025)

[312] Vibhu Mishra, "Four Years After the Coup, Myanmar Remains on the Brink," UN News, 29 January 2025, at https://news.un.org/en/story/2025/01/1159561. (Accessed 30 January 2025)

[313] Lindsay Maizland, "Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict," Council on Foreign Relations, 31 January 2022. (Accessed 25 January 2025)

[314] "New Report Documents over 6,000 Civilians Killed in 20 Months Since Myanmar," Peace Research Institute, Oslo, 12 June 2023. (Accessed 25 January 2025)

[315] Myanmar: 'Appalling' Violations Demand 'Unified and Resolute International Response,' UN News, 2022.

[316] "Political Prisoners Post-Coup," Assistance Association for Political Prisoners.

[317] Andrew Selth, "Three Years on from the Coup, What Could Help Myanmar's Opposition Movement?" Lowy Institute, 17 January 2024. (Accessed 25 January 2025)

[318] Ye Myo Hein, "Understanding the People's Defense Forces in Myanmar," United States Institute of Peace, 3 November 2022. (Accessed 25 January 2025)

[319] Naseer Ganai, "As Three Brotherhood Alliance Moves Forward in Myanmar, What Should Be India's next Step?" Outlook India, 27 November 2023. (Accessed 29 January 2025)

[320] Yun Sun, "Operation 1027: Changing the Tides of the Myanmar Civil War?" Brookings, 24 January 2024. (Accessed 29 January 2025)

[321] Andrew Selth, "Three Years on from the Coup, What Could Help Myanmar's Opposition Movement?" Lowy Institute, 17 January 2024, at https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/three-years-coup-what-could-help-myanmar-s-opposition-movement (Accessed 29 January 2025)

[322] "Myanmar Resistance Claims It Holds 60% of Territory," Bangkok Post, 29 September 2023, at https://www.bangkokpost.com/world/2654881/myanmar-resistance-claims-it-holds-60-of-territory. (Accessed 30 January 2025)

[323] "The Military Dictatorship Controls Less Than 50% of Myanmar," The Economist, 16 May 2024, at https://www.economist.com/asia/2024/05/16/the-military-dictatorship-controls-less-than-50-of-myanmar. (Accessed 30 January 2025)

[324] Ophelia Yumlembam, "As Myanmar's Resistance Makes Headway, India Should Reconsider Its Realpolitik Strategy," South Asian Voices, 26 August 2024, at https://southasianvoices.org/geo-f-in-n-myanmars-resistance-makes-headway-05-21-2024/ (Accessed 30 January 2025)

[325] Yun Sun, "Operation 1027: Changing the Tides of the Myanmar Civil War?" Brookings, 24 January 2024, at https://www.brookings.edu/articles/operation-1027-changing-the-tides-of-the-myanmar-civil-war/#:~:text=On%20October%2027%2C%202023%2C%20the (Accessed 30 January 2025)

[326] Star Digital Report, "People of My Parents' Age Are Being Killed," The Daily Star, 30 January 2024, at https://www.thedailystar.net/news/asia/south-asia/news/people-my-parents-age-are-being-killed-3532056. (Accessed 9 December 2025)

[327] "Conflict Watchlist 2024, Myanmar: Resistance to the Military Junta Gains Momentum," Armed Conflict Location and Event Data Project, 18 January 2024, at https://acleddata.com/conflict-watchlist-2024/myanmar/ (Accessed 9 December 2025)

[328] International Federation for Human Rights, "Myanmar: 20,000 Political Prisoners Now Behind Bars - International Criminal Court Referral Urged," ReliefWeb, 16 February 2024, at https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-20000-political-prisoners-now-behind-bars-international-criminal-court-referral-urged (Accessed 30 January 2025)

[329] "Myanmar: Four Years After Coup, World Must Demand Accountability for Atrocity Crimes," Amnesty International, 31 January 2025, at https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/01/myanmar-four-years-after-coup-world-must-demand-accountability-for-atrocity-crimes/. (Accessed 30 January 2025)

[330] *Ibid.*

[331] "Myanmar Emergency - UNHCR Regional Update - October 2023," UNHCR Operational Data Portal.

[332] "Myanmar resistance forces make territorial advances," Mizzima, 25 August 2024, at https://eng.mizzima.com/2024/08/25/13211. (Accessed 30 January 2025)

[333] Ye Myo Hein and Billy Ford, The Myanmar Military's Institutional Resilience, United States Institute of Peace, 2 October 2024, at https://www.usip.org/publications/2024/10/myanmar-militarys-institutional-resilience. (Accessed 30 January 2025)

[334] Rebecca Ratcliffe, "Four Years After the Coup, Chaos Reigns As Myanmar's Military Struggles," The Guardian, 31 January 2025, at https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/31/myanmar-military-coup-anniversary?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 31 January 2025)

[335] *Ibid.*

[336] Subir Bhaumik, "China Intensifies Intervention in Myanmar Civil War, Forces Truce in Shan State," The Federal News, 26 January 2025, at https://thefederal.com/category/international/china-intensifies-intervention-in-myanmar-civil-war-forces-truce-in-shan-state-168726. (30 January 2025)

[337] Rebecca Ratcliffe, "Four Years After the Coup, Chaos Reigns As Myanmar's Military Struggles," The Guardian, 31 January 2025, at

https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/31/ myanmar-military-coup-anniversary?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 31 January 2025)

[338] "Myanmar Junta Losing Ground to Rebel Forces As Civil War Enters 5th Year," Firstpost, 31 January 2025, at https://www.firstpost.com/world/myanmar-junta-losing-ground-to-rebel-forces-as-civil-war-enters-5th-year-13857996.html. (Accessed 30 January 2025)

[339] Rebecca Ratcliffe, "Four Years After the Coup, Chaos Reigns As Myanmar's Military Struggles," The Guardian, 31 January 2025, at https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/31/myanmar-military-coup-anniversary?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 31 January 2025)

[340] "Myanmar Junta Losing Ground to Rebel Forces As Civil War Enters 5th Year," Firstpost, 31 January 2025, at https://www.firstpost.com/world/myanmar-junta-losing-ground-to-rebel-forces-as-civil-war-enters-5th-year-13857996.html. (Accessed 30 January 2025)

[341] Rebecca Ratcliffe, "Four Years After the Coup, Chaos Reigns As Myanmar's Military Struggles," The Guardian, 31 January 2025, at https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/31/myanmar-military-coup-anniversary?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 31 January 2025)

[342] Sreeparna Banerjee, "Arakan Army's Growing Influence in Myanmar: Implications for the Rohingyas," Observer Research Foundation, 24 January 2025, at https://www.orfonline.org/expert-speak/arakan-army-s-growing-influence-in-myanmar-implications-for-the-rohingyas. (Accessed 31 January 2025)

[343] "Myanmar Youth Flee into Thailand to Avoid Forced Service," The Hindu, 3 July 2024, at (Accessed 30 January 2025)

[344] "Myanmar: Military Forcibly Recruiting Rohingya," Human Rights Watch. Last modified April 19, 2024, at (Accessed 30 January 2025)

[345] National Self-Defence, The Global New Light of Myanmar, 24 September 2024, at (Accessed 30 January 2025)

[346] Yossi Shain, "The Shifting Character of Loyalty: The Dilemma of Exiles in Times of War," Comparative Politics 22 (3), 1990, pp. 323–39. https://doi.org/10.2307/421964.

[347] United Nations reports and discussions on Myanmar should acknowledge Myanmar's constructive endeavours, The Global New Light of Myanmar, 12 October 2024, at (Accessed 30 January 2025)

[348] Myanmar: ASEAN's Failed '5-Point Consensus' a Year On, Human Right Watch, 22 April 2022, at (Accessed 30 January 2025)

[349] Ahead of Summit, ASEAN Again Prepares to Grapple with Myanmar Conundrum, The Diplomat, 8 October 2024, at (Accessed 30 January 2025)

[350] Ruth Abbey Gita-Carlos, Asean seeking new strategies to address Myanmar crisis – Marcos, Inquirer, 10 October 2024, at (Accessed 30 January 2025)

[351] Poramet Tangsathaporn, Thailand offers to host new Myanmar talks, Bangkok Post, 10 October 2024, at (Accessed 30 January 2025)

[352] "History and Formation," ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် (The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw), at https://crphmyanmar.org/history-and-formation-of-crph/. (Accessed 2 February 2025)

[353] *Ibid.*

[354] *Ibid.*

[355] Constitution Brief Interregnum Series, "Myanmar's Federal Democracy Charter: Analysis and Prospects," International IDEA, 2022. <https://doi.org/10.31752/ idea.2022.27>.

[356] Federal Democracy Charter, Part - I, "Declaration of Federal Democracy Union 2021," Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, at https://crphmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/04/Federal-Democracy-Charter-English.pdf. (Accessed 2 February 2025)

[357] *Ibid.*

[358] "Federal Democracy Charter of Myanmar (Part 2)," ConstitutionNet, at https://constitutionnet.org/node/19422. (Accessed 3 February 2025)

[359] "Myanmar's Federal Democracy Charter: Analysis and Prospects," ConstitutionNet, at https://constitutionnet.org/vl/item/myanmars-federal-democracy-charter-analysis-and-prospects?utm_source=chatgpt.com. (Accessed 2 February 2025)

[360] Constitution Brief Interregnum Series, "Myanmar's Federal Democracy Charter: Analysis and Prospects," International IDEA, 2022. <https://doi.org/10.31752/ idea.2022.27>.

[361] Billie Phillips, "A Myanmar Roadmap: Charting the Path to Federal Democracy," International IDEA, 14 October 2022, at https://www.idea.int/news/myanmar-roadmap-charting-path-federal-democracy. (Accessed 2 February 2025)

[362] Constitution Brief Interregnum Series, "Myanmar's Federal Democracy Charter: Analysis and Prospects," International IDEA, 2022. <https://doi.org/10.31752/ idea.2022.27>.

[363] Shan, "PRCF's Charter: Roadmap to a Federal Democratic Constitution," Shan Herald Agency for News, 16 February 2024, at https://english.shannews.org/archives/26937. (Accessed 2 February 2025)

[364] Constitution Brief Interregnum Series, "Myanmar's Federal Democracy Charter: Analysis and Prospects," International IDEA, 2022. <https://doi.org/10.31752/ idea.2022.27>.

[365] *Ibid.*

[366] Constitution Brief Interregnum Series, "Myanmar's Federal Democracy Charter: Analysis and Prospects," International IDEA, 2022. <https://doi.org/10.31752/ idea.2022.27>.

[367] Harihar Bhattacharyya, *Federalism in Asia: India, Pakistan, Malaysia, Nepal and Myanmar,* 2nd ed. Routledge, New York, 2021, pp. 51 – 53.

[368] *Ibid.*

[369] *Ibid.*

[370] Francesca Baronio, "Myanmar's Army Will Do Whatever It Takes to Hold Onto Power," Italian Institute for International Political Studies, 9 December 2022, at https://www.ispionline.it/en/publication/myanmars-army-will-do-whatever-it-takes-hold-power-31157. (3 January 2025)

[371] Andrew Selth, Myanmar's Military Mindset: An Exploratory Survey, *Griffith Asia Institute,* Griffith University, 2021.

[372] Felix Thiam Kim Tan, Myanmar's Fragmented Democracy: Transition Or Illusion?, Vol. 1, World Scientific, 2022, pp. 194 – 196.

[373] Morten B. Pedersen, "Burma's ethnic minorities: Charting their own path to peace," *Critical Asian Studies*, Vol. 40, no. 1, 2008, pp. 45-66.

[374] Charmaine Craig, "Burma's Fault Lines: Ethnic Federalism and the Road to Peace," Dissent Magazine, 29 December 2014, at https://www.dissentmagazine.org/article/burmas-fault-lines-ethnic-federalism-and-the-road-to-peace/. (Accessed 2 February 2025)

[375] Morten B. Pedersen, "Burma's ethnic minorities: Charting their own path to peace," *Critical Asian Studies*, Vol. 40, no. 1, 2008, pp. 45-66.

[376] Ashley South, "Towards 'Emergent Federalism' in Post-Coup Myanmar," Contemporary Southeast Asia, Vol. 43, no. 3, 2021, pp. 439–460. https://www.jstor.org/stable/27096069.

[377] W. Elliot Bulmer, "A New Constitution for Myanmar: Towards Consensus on an Inclusive Federal Democracy," *International Institute for Democracy and Electoral Assistance,* 2022, p. 27. https://doi.org/10.31752/idea.2022.11.

[378] Catherine Renshaw, "The National Unity Government: Legitimacy and Recognition," In Myanmar's Changing Political Landscape: Old and New Struggles, Singapore: Springer Nature Singapore, 2023, pp. 225-241.

[379] *Ibid.*

[380] John Buchanan, *Militias in Myanmar,* The Asia Foundation, 1st ed. Washington, D.C., 2016.

---

[381] Michael Martin, "News from the Front: Observations from Myanmar's Revolutionary Forces," *Center for Strategic and International Studies*, 5 December 2022, at https://www.csis.org/analysis/news-front-observations-myanmars-revolutionary-forces (Accessed 25 December 2024)

[382] "Federal Democracy Charter Part -I," Declaration of Federal Democracy Union 2021, Federal Democracy Charter.

[383] "Myanmar's Federal Democracy Charter: Analysis and Prospects," International IDEA.

[384] "Federal Democracy Charter Part –I," Declaration of Federal Democracy Union 2021, Federal Democracy Charter.

[385] Mael Raynaud, "Asymmetrical Federalism in Myanmar: A Modern Mandala System?" *Perspective, Yusof Ishak Institute Analyse Current Events,* no. 155, November 2021.

[386] "Myanmar 2008 Constitution," Constitute, Accessed February 12, 2025, at https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.

[387] Narayanan Ganesan, "Democratization and its implications for the resolution of ethnic conflict in Myanmar." *Asian Journal of Peacebuilding*, Vol. 5, no. 1, 2017, pp. 111-129.

[388] Elliott Bynum, "Myanmar's Spring Revolution," ACLED, 11 August 2021, at https://acleddata.com/2021/07/22/myanmars-spring-revolution/.

[389] Constitution Brief Interregnum Series, "Myanmar's Federal Democracy Charter: Analysis and Prospects," International IDEA, 2022. <https://doi.org/10.31752/ idea.2022.27>.

[390] Antonio Graceffo, "Myanmar War: China's Support for Ethnic Armed Groups," *Special Eurasia,* 4 July 2024, at https://www.specialeurasia.com/2024/07/04/myanmar-war-chinas-ethnicmilitia/.

[391] *Ibid.*

[392] Jacques Bertrand, Alexandre Pelletier, and Ardeth Thawnghmung, *Winning by Process: The State and Neutralization of Ethnic Minorities in Myanmar,* Cornell University Press, 1st ed. Ithaca, 2022, pp. 16 – 19.

[393] Ashley South, "Towards 'Emergent Federalism' in Post-Coup Myanmar," *Contemporary Southeast Asia,* Vol. 43, no. 3, 2021, pp. 439–460. https://www.jstor.org/stable/27096069.

[394] *Ibid.*

[395] *Ibid.*

[396] Mary P. Callahan, "MYANMAR IN 2017: Crises of Ethnic Pluralism Set Transitions Back," *Southeast Asian Affairs,* 2018, pp. 243–64. https://www.jstor.org/stable/26492780.

[397], R. Myat David, and I. Holliday, Liberalism and illiberalism in Myanmar's National League for Democracy, Party Politics, (2023). https://doi.org/10.1177/13540688231205533

[398] "Myanmar's Coup Shakes Up Its Ethnic Conflicts," Crisis Group, 12 December 2022, at https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/myanmars-coup-shakes-its-ethnic-conflicts. (Accessed 11 February 2025)

[399] Ashley South, "Towards 'Emergent Federalism' in Post-Coup Myanmar," *Contemporary Southeast Asia,* Vol. 43, no. 3, 2021, pp. 439–460. https://www.jstor.org/stable/27096069.

[400] *Ibid.*

[401] *Ibid.*

[402] "Myanmar forms interim government before election but top general still in charge," Reuters, 1 August 2025, at https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-forms-interim-government-before-election-top-general-still-charge-2025-07-31/ (Accessed 23 August 2025)

[403] Maung Kavi, "Myanmar Junta Boss Forms New Government With Eye on December Election" The Irrawaddy, 31 July 2025, at https://www.irrawaddy.com/news/politics/myanmar-junta-boss-forms-new-government-with-eye-on-december-election.html (Accessed 23 August 2025)

[404] International IDEA Statement on the Situation in Myanmar, International IDEA, 12 August 2025, at https://www.idea.int/news/international-idea-statement-situation-myanmar (Accessed 23 August 2025)

[405] International IDEA Statement on the Situation in Myanmar, International IDEA, 12 August 2025, at https://www.idea.int/news/international-idea-statement-situation-myanmar (Accessed 23 August 2025)

[406] "Myanmar junta forms new government ahead of elections," Radio Free Asia, 31 July 2025, at

https://www.rfa.org/english/myanmar/2025/07/31/myanmar-state-of-emergency-elections/ (Accessed 23 August 2025)

[407] Manny Maung, "Myanmar Junta Dissolves Political Parties," *Human Rights Watch,* 29 March 2023, at https://www.hrw.org/news/2023/03/29/myanmar-junta-dissolves-political-parties. (Accessed 11 February 2025)

[408] *Ibid.*

[409] "*Myanmar's Military Government Enacts New Political Party Law,*" The Times of India, 27 January 2023, at https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/myanmars-military-government-enacts-new-political-party-law/articleshow/97382661.cms. (Accessed 10 February 2025)

[410] Reuters, *"Myanmar Junta Dissolves Suu Kyi's Party As Election Deadline Passes,"* CNN, 29 March 2023, at https://edition.cnn.com/2023/03/28/asia/myanmar-suu-kyi-nld-dissolved-intl-hnk/index.html. (Accessed 10 February 2025)

[411] Anna S. King, Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government, *Religions* 13(7), 2022, p. 594. https://doi.org/10.3390/rel13070594

[412] Francesca Baronio, Myanmar's Army Will Do Whatever It Takes to Hold Onto Power, Italian Institute for International Political Studies, 15 July 2021, at https://www.ispionline.it/en/publication/myanmars-army-will-do-whatever-it-takes-hold-power-31157?utm_source=chatgpt.com (Accessed 22 August 2025)

[413] "Myanmar's Coup Shakes Up Its Ethnic Conflicts," Asia Report N°319, International Crisis Group, 12 January 2022. https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/319-myanmar-coup-ethnic-conflicts.pdf

[414] W. Elliot Bulmer, "A New Constitution for Myanmar: Towards Consensus on an Inclusive Federal Democracy," *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2022, pp. 27-29. https://doi.org/10.31752/idea.2022.11.

[415] Vikram Nehru, "Myanmar's Military Keeps Firm Grip on Democratic Transition," CARNEGIE, 2 June 2015, at https://carnegieendowment.org/research/2015/06/myanmars-military-keeps-firm-grip-on-democratic-transition?lang=en&utm_source=chatgpt.com (Accessed 23 August 2025)

[416] Myanmar 2008, Constitute, at https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008 (Accessed 24 August 2025)

[417] Vikram Nehru, "Myanmar's Military Keeps Firm Grip on Democratic Transition," CARNEGIE, 2 June 2015, at https://carnegieendowment.org/research/2015/06/myanmars-military-keeps-firm-grip-on-democratic-transition?lang=en&utm_source=chatgpt.com (Accessed 23 August 2025)

[418] Myanmar 2008, Constitute, at https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008 (Accessed 24 August 2025)

[419] The economic interests of the Myanmar military, Human Rights Council, United Nations, 5 August 2019, at https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/08/report/the-economic-interests-of-the-myanmar-military/A_HRC_42_CRP_3.pdf?utm_source=chatgpt.com (Accessed 23 August 2025)

[420] The economic interests of the Myanmar military, Human Rights Council, United Nations, 5 August 2019, at https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/08/report/the-economic-interests-of-the-myanmar-military/A_HRC_42_CRP_3.pdf?utm_source=chatgpt.com (Accessed 23 August 2025)

[421] "Treasury Sanctions Military Holding Companies in Burma," U.S. Department of the Treasury, 25 March 2021, at https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0078?utm_source=chatgpt.com (Accessed 22 August 2025)

[422] "Civil War in Myanmar," The Center for Preventive Action, Council on Foreign Relations, 27 July 2025, at https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/rohingya-crisis-myanmar?utm_source=chatgpt.com (Accessed 23 August 2025)

[423] Morgan Michaels, Crossing the Rubicon: Are Myanmar's ethnic armies prepared to go all in? IISS Myanmar Conflict Map, February 2025, at https://myanmar.iiss.org/analysis/2025-02 (Accessed 23 August 2025)

[424] *Ibid.*

[425] Koh Ewe, "How Myanmar's Civil War Could Actually End," TIME, 31 October 2024, at https://time.com/7160736/myanmar-coup-civil-war-conflict-timeline-endgame-explainer/?utm_source=chatgpt.com, (Accessed 23 August 2025)

[426] Ye Myo Hein, Understanding the People's Defense Forces in Myanmar, United States Institute, 3 November 2022 at https://www.usip.org/publications/2022/11/understanding-peoples-defense-forces-myanmar?utm_source=chatgpt.com (Accessed 23 August 2025)

[427] Vikram Nehru, "Myanmar's Military Keeps Firm Grip on Democratic Transition," CARNEGIE, 2 June 2015, at https://carnegieendowment.org/research/2015/06/myanmars-military-keeps-firm-grip-on-democratic-transition?lang=en&utm_source=chatgpt.com (Accessed 23 August 2025)

[428] Anna S. King, "Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government," *Religions*, Vol. 13 (7), p. 594, 2022. https://doi.org/10.3390/rel13070594

[429] Andrew Selth, "Myanmar's Armed Forces and The Rohingya Crisis," United States Institute of Peace, Peaceworks, no. 140, August 2018.

[430] Marco Bünte, "Myanmar: Civil–Military Relations in a Tutelary Regime," *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 28 June 2021, at https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1887 (Accessed 24 August 2025)

अस्मिताओ, महत्वाकांक्षाओं और लगातार उभरती हुई राजनीतिक प्रवृत्तियों के बीच का टकराव ही म्यांमार की आधुनिक कहानी लिख रहा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस देश का राजनीतिक इतिहास मानो एक अधूरी गाथा है, जहां स्वतंत्रता के बाद से ही सत्ता के गलियारों में केंद्रीकरण की गूंज इतनी प्रबल रही कि बहुलतावाद और सहभागिता की संभावनाएं बार-बार दबा दी गई। यह प्रबंध-निबंध (मोनोग्राफ) इसी विफलता की परतों को खोलता है और बताता है कि समस्या केवल प्रभुत्वशाली वर्गो की सत्ता-लालसा तक सीमित नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक खालीपन में भी निहित है, जहाँ विश्वास, संवाद और साझा भविष्य की आकांक्षा अंकुरित हो ही नही पाई। जातीय समूह अपने-अपने संघवाद के सपने लेकर इस भूमि पर चलते रहे, परंतु साझा ढांचे की कल्पना आज भी विवादों के दलदल में फंसी हुई है। सेना और उससे जुड़े अभिजात वर्ग ने साझादारी को परे रखकर केवल नियंत्रण और लाभ की राजनीति की। विपक्षी दल और सेना-विरोधी गुट भी अपनी-अपनी सीमाओं में उलझे और बंटे हुए हैं। कोई सीमित स्वायत्तता पर संतुष्ट है तो कोई पूर्ण आत्मनिर्णय के बिना भविष्य को अंधकारमय मानता है। यही बंटवारा जुंटा के पतन के बाद भी किसी नए प्रभुत्वशाली वर्ग के उभरने की आशंका का जीवित रखता है। यह केवल संविधान, चुनाव और प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं.है; यह उस राजनीतिक संस्कृति के पुर्नजन्म का प्रश्न है, जो हर आवाज़ को सुने और हर स्वप्न को स्थान दे।

डॉ. ओमप्रकाश दास नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (MP-IDSA) के दक्षिण-पूर्वएशिया एवं ओशिनिया केंद्र में रिसर्च फेलो हैं। उनका शोध क्षेत्र रणनीतिक संचार, म्यांमार-भारत संबंध और दक्षिण-पूर्व एशिया की भू-राजनीति है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविघालय (JNU) से पीएचडी उपाधि हासिल की है। डॉ. दास को ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में लगभग अठारह वर्षों का अनुभव है, जिसमें उनकी विशेषज्ञता रक्षा, अंतराष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर रहा है।

MANOHAR PARRIKAR
idsa
MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
नं. 1, डेवलपमेंट एन्कलेव, राव तुला राम मार्ग,
दिल्ली कैंट., न्यू दिल्ली - 110010
फोनः (91-11) 2671-7983 फैक्स. (91-11) 2615 4191
वेबसाइटः http://www.idsa.in